असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

21 फरवरी, 2024

सप्तदश विधान सभा — बुधवार, तिथि 21 फरवरी, 2024 ई॰
एकादश सत्र — 02 फाल्गुन, 1945 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव राम : महोदय,...

अध्यक्ष : कार्यस्थगन के बारे में शून्यकाल में चर्चा करेंगे अभी प्रश्नोत्तर काल है । प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिये ।

(व्यवधान)

अभी प्रश्नोत्तर काल है, इतना बढ़िया से चला रहे थे आप लोग । शून्यकाल में बात उठाइयेगा ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-9 (श्री पवन कुमार जायसवाल, क्षेत्र संख्या-21, ढाका)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप शून्यकाल में अपनी बात को उठाइयेगा ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : यह है कि पथ निर्माण विभाग के अधीन राज्य उच्च पथ एस0एच0 एवं वृहद जिला पथ एम0डी0आर0 की कुल 13064 कि0मी0 की लंबाई में ओ0पी0आर0एम0सी0 अंतर्गत...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : पहले आप अपने स्थान पर जाइये । पहले आप जाइये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : सड़क सुरक्षा के सभी उपायों यथा जंक्शन, उन्नयन, साईनेज, रोड मार्किंग, स्पीड ब्रेकर एवं रंबल स्ट्रीप इत्यादि का प्रावधान किया गया है...

(व्यवधान जारी)

दुर्घटना प्रवण स्थलों यथा निजी/सरकारी स्कूल एवं अस्पताल इत्यादि के निकट वाहनों की गति नियंत्रण हेतु स्पीड ब्रेकर...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठ जाइये, बैठ जाइये ।

इस तरह से आपकी कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जायेगी । अपने स्थान पर जाकर बोलिये । अपने स्थान पर जाइये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : साईनेज, रंबल स्ट्रीप एवं जेबरा क्रॉसिंग का प्रावधान किया गया है एवं कार्य भी कराया जा रहा है।

(व्यवधान जारी)

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर देश के प्रत्येक जिले में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया गया है...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठ जाइये । बैठ जाइये ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : राज्य के सभी जिलों से साईनेज लगाने के 5433 एवं स्पीड ब्रेकर लगाने के 8603 मामले चिन्हित हैं परंतु मात्र 983 साईनेज एवं 1013 स्पीड ब्रेकर लगाये गये हैं । हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि पथ निर्माण विभाग नोडल विभाग है । आर0सी0डी0 से ही सारे विभाग गाइड होते हैं...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आपकी कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जायेगी । अपने स्थान पर जाइये ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : माननीय मंत्री जी बची हुई जगहों पर कब तक स्पीड ब्रेकर एवं साईनेज लगाने का काम करेंगे...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अपने स्थान पर जाइये । बैठिये । शून्यकाल में मौका देंगे, अपने स्थान पर जाइये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, इनका जो प्रश्न है कि ''कब तक विचार रखती है'' तो स्पष्ट बता दिया गया है कि दुर्घटना प्रवण स्थलों यथा निजी/सरकारी स्कूल एवं अस्पताल इत्यादि के निकट वाहनों की गति नियंत्रण हेतु स्पीड ब्रेकर...

(व्यवधान जारी)

साईनेज, रंबल स्ट्रीप एवं जेबरा क्रॉसिंग का प्रावधान किया गया है और जो कार्य बचा हुआ है वह कराया भी जा रहा है ।

(व्यवधान जारी)

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा यही कहना है कि राज्य की जिला सुरक्षा समितियों से 5433 स्पीड ब्रेकर का और 8603 साईनेज लगाने के मामले चिन्हित

किये गये हैं । मात्र 983 और 1013 लगे हैं । बाकी जगहों पर कब तक विभाग द्वारा लगाया जायेगा ?

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, जल्द से जल्द दिखवा लेते हैं ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-10 (श्री पवन कुमार जायसवाल, क्षेत्र संख्या-21, ढाका)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुरूप राज्य के सभी एन0एच0 पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट को सुधार करने का निदेश दिया गया है...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अपने स्थान पर जाकर बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : जिसके आलोक में लघुकालिक एवं दीर्घकालिक उपाय किये जा रहे हैं । चिन्हित ब्लैक स्पॉटों पर उक्त उपायों के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है...

(व्यवधान जारी)

वर्ष 2016 के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत निर्मित एन0एच0 पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है तथा जो एन0एच0 निर्माणाधीन हैं उनमें भी एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का प्रावधान किया जा रहा है ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सके ।

(व्यवधान जारी)

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को मुजफ्फरपुर से कोटवा तक 80 कि0मी0 की दूरी पर लगाया गया है जिससे इस रूट पर सड़क दुर्घटना में 27 प्रतिशत की कमी आयी है । राज्य के प्रत्येक एन0एच0/एस0एच0 पर ब्लैक स्पॉट...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : आप लोग जिंदाबाद । आप लोग मेरा मुर्दाबाद लगाते हैं हम आपको जिंदाबाद कहते हैं । बाहर भी बोल रहे हैं, जितनी बार लगाना है मुर्दाबाद लगाइये, हम आप सबका जिंदाबाद करेंगे । जिंदा रहिये और हमको मुर्दा करते रहिये । आप जितना मुर्दा करते रहियेगा उतना ही खत्म हो जाइयेगा । आप लोग बहुत कम संख्या में अगली बार आइयेगा । एक सीट भी नहीं मिलेगी यह जान लीजिये...

(व्यवधान जारी)

इसलिए लगाओ नारा, खूब नारा लगाओ । हम इसलिए कह रहे हैं जिदांबाद कि घर में रहना यहां आने की जरूरत नहीं है । क्या नहीं कर दिया ? सारा काम देख लिया । सारा काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है और गड़बड़ कर रहे थे तो आप ही लोग कर रहे थे । अभी हम सबकुछ सुधार कर दिये, एक-एक काम कर दिये और अब आप लोग बोल रहे हैं । कल ही हमने कह दिया लागू हो गया । अब कहियेगा अधिकारी को हटाइये । यह आपको अधिकार है ? सरकारी अधिकारी को किसी पद से हटाने की मांग करना गलत है। यह बिल्कुल गलत है । ईमानदार आदमी के खिलाफ आप लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जो सबसे ईमानदार है उसके खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं । ऐसे अधिकारी जो किसी का धंधा, इधर-उधर नहीं सुनते हैं और उसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं । बहुत गलत बात है और आप लोगों को जितना करना है उतनी जोर से हंगामा करिये और यही करते-करते दो साल के अंदर आप क्षेत्र ही में हंगामा करते रहियेगा ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठ जाइये । आप सब लोग अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइये ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को...मुजफ्फरपुर से कोटवा तक 80 कि0मी0 की दूरी पर लगाया गया है जिससे इस रूट पर सड़क दुर्घटना में 27 प्रतिशत की कमी आयी है । माननीय मंत्री महोदय, राज्य के अन्य एन0एच0/एस0एच0 पर कब तक एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करवाने का काम करेंगे ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अपने स्थान पर बैठिये । आपकी बात शून्यकाल में सुनेंगे । यहां आपकी कोई बात नहीं सुनी जायेगी, कोई बात प्रोसीडिंग में दर्ज नहीं होगी । अपने स्थान पर जाइये शून्यकाल में आपकी बात सुनेंगे ।

(व्यवधान जारी)

कहीं कोई बात दर्ज नहीं हो रही है । शून्यकाल में आपकी बात सुनेंगे । बैठिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो खंड-3 में कहा गया है कि चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाने का विचार रखती है तो स्पष्ट जवाब दिया गया है कि...

(व्यवधान जारी)

प्राधिकरण के अंतर्गत निर्मित एन0एच0 पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है तथा जो एन0एच0 निर्माणाधीन हैं उनमें भी एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का प्रावधान किया जा रहा है ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सके ।

(व्यवधान जारी)

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि पूरे राज्य में केवल मुजफ्फरपुर से कोटवा तक उसको लागू किया गया है । राज्य के अन्य एन0एच0 पर, राज्य के अन्य एस0एच0 पर इसको कब तक लागू किया जायेगा । राज्य में केवल एक ही जगह पर लागू है मेरा यह कहना है ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, इसकी समीक्षा करके यह पूरे राज्य के लिए लागू किया जायेगा । दुर्घटनाग्रस्त वातावरण से मुक्त करने का हमारा प्रयास रहेगा ।

(व्यवधान जारी)

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : हो गया । अब आगे आपका दूसरा प्रश्न है । अब अगला प्रश्न है श्री पवन कुमार जायसवाल जी ।

टर्न-2/मुकुल/21.02.2024

(व्यवधान जारी)

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या-12 (श्री पवन कुमार जायसवाल, क्षेत्र संख्या-21, ढाका)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के सभी नौ सड़क परियोजनाओं का कार्यान्वयन एन0एच0ए0आई0 द्वारा किया जा रहा है । प्रश्नगत परियोजनाओं में से चोरमा-बैरगनियां पथांश में कार्यारम्भ दिनांक-01.02.2024 से किया जा चुका है । सीवान-मशरख सहित अन्य परियोजनाओं में निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता एवं वन विभाग की अनापत्ति प्राप्त करते हुए शीघ्र कार्य आरम्भ करने हेतु राज्य सरकार द्वारा लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि राज्य में 1 दर्जन से ज्यादा परियोजनाएं हैं जो जमीन अधिग्रहण के कारण लंबित पड़ी हुई हैं । चोरमा से फुलवरिया घाट तक यह भारत माला परियोजना में सड़क है, 34 किलोमीटर की सड़क है, 400 करोड़ की योजना है यह लंबित है और जमीन का

अधिग्रहण नहीं हो पाया है । बिना अधिग्रहण किये हुए आर0सी0डी0 के द्वारा सड़क निर्माण का काम हो रहा है । वर्ष 2013 की रेट से जमीन का अधिग्रहण किया गया है, जबकि वर्ष 2023 के रेट से मिलना चाहिए । ऐसे दर्जनों मामले हैं जो समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए हैं । हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि संवेदक अगर एक साल के बदले पांच साल तक काम को लेकर जाता है तो उसको तीन गुना पैसा प्राक्कलन का एक्सेशन में दिया जाता है लेकिन किसानों को वर्ष 2013 की रेट के बदले वर्ष 2023 की रेट से पैसा देने में क्या दिक्कत है । आखिर यह योजना क्यों बाधित है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

(व्यवधान जारी)

आप अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइये । वेल से कही जाने वाली कोई भी बात कार्यवाही में नहीं आयेंगी, आपलोग अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि एजेंसी पर कार्रवाई करते हुए नौ सड़क परियोजनाओं को कब तक कार्य प्रारंभ करने के संबंध में सरकार से विचार जानना चाहते हैं । तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के सभी नौ सड़क परियोजनाओं का कार्यान्वयन एन0एच0ए0आई0 द्वारा किया जा रहा है ।

प्रश्नगत परियोजनाओं में से चोरमा-बैरगनियां पथांश में कार्यारम्भ दिनांक-01.02.2024 से किया जा चुका है । सीवान-मशरख सहित अन्य परियोजनाओं में निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता एवं वन विभाग की अनापत्ति प्राप्त करते हुए शीघ्र कार्य आरम्भ करने हेतु राज्य सरकार द्वारा लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पवन कुमार जायसवाल जी ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से यह है कि चोरमा से पकड़िदयाल की जो सड़क है वह हमलोगों के क्षेत्र से गुजरती है । वहां के किसानों को वर्ष 2013 की रेट से मुआवजा दिया जा रहा है । किसानों के विरोध के कारण समय से सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है जबकि आज वर्ष 2023 चल रहा है । माननीय मंत्री जी हमको बता दें कि किसानों को मुआवजा वर्ष 2013 से मिलेगा या वर्ष 2023 से मिलेगा । इसके कारण राज्य की कई परियोजनाएं बाधित हो रही हैं । हम माननीय मंत्री जी आपसे आग्रह करेंगे, यह हमलोगों की सरकार है और किसानों को उचित मुआवजा मिले और सड़क का निर्माण समय पर हो जाय इस दिशा में आप क्या कार्रवाई करना चाहेंगे ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका जो प्रश्न है और प्रश्न के हिसाब से हमने जवाब दिया है इनका मुआवजा से जुड़ा हुआ विषय अलग से है । अगर माननीय सदस्य इसके बारे में हमें लिखकर दे देंगे तो हम इसको दिखवा लेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप माननीय मंत्री जी को इसके बारे में लिखकर दे दीजिए ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : सर, मेरा चोरमा-पकड़िदयाल इस प्रश्न में शामिल है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मुआवजा की राशि की बात कर रहे हैं ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, काम बाधित है और काम बाधित होने का कारण है मुआवजा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप एक बार इसके बारे में माननीय मंत्री जी को लिखकर दे दीजिएगा और इनसे मिल लीजिएगा, ये करवा देंगे ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, ठीक है ।

(व्यवधान जारी)

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या-13 (श्री अजीत शर्मा, क्षेत्र संख्या-156, भागलपुर)</u>

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या-14 (श्री ललित कुमार यादव, क्षेत्र संख्या-82, दरभंगा (ग्रामीण))</u>

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बोलिए ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : कल मैंने जो कह दिया था, वह लागू हो गया है ।

(व्यवधान जारी)

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : मेरी बात सुनिये ।

अध्यक्ष : सुनिये, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : सिर्फ हल्ला कीजिएगा कि मेरी बात को भी सुनियेगा ।

अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी बात सुनिये ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : केवल हल्ला कीजिएगा कि मेरी बातों को भी सुनियेगा । कल ही हमने कह दिया है । आप जान लीजिए जो होगा 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक के लिए ।

(व्यवधान जारी)

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : सुनिये, आप नहीं जानते हैं, शिक्षकों को...

अध्यक्ष : आप इनकी बातों को सुन लीजिए पहले ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अरे आप मेरी बात को सुनिये । हम जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुन लीजिए, कल ही हमने कह दिया है कि पढ़ाई का 10 बजे से लेकर 4 बजे तक लेकिन टीचर्स को, जो बच्चे 10 बजे सुबह से पढ़ेंगे तो टीचर्स को 15 मिनट पहले आ जाना चाहिए, यही तरीका है ।

(व्यवधान जारी)

आप क्या बात करते हैं ? 10 बजे सुबह में बच्चे आकर बैठेंगे और टीचर्स क्या 15 मिनट पहले नहीं आयेंगे ? टीचर्स भी 15 मिनट पहले आ जायेंगे ताकि बच्चों की पढ़ाई 10 बजे सुबह से 4 बजे शाम तक अगर पढ़ाई पूरी हो जायेगी तो वे भी 15 मिनट के बाद चले जायेंगे, यही नियम पहले से भी है ।

(व्यवधान जारी)

इसका मतलब आपलोगों को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं रहा, लगता है कि इनको मालूम ही नहीं है । टीचर्स को हमेशा बच्चों-बच्चियों के 15 मिनट पहले स्कूल में आना पड़ता है, इसलिए उनको 15 मिनट पहले आ ही जाना पड़ेगा और जब सारे बच्चों की छुट्टी हो जायेगी तो उसके बाद 15 मिनट में वे भी चले जायेंगे, यही तरीका है और हमने यही कह दिया है । यह तय है और इसको कोई इधर-उधर नहीं करेगा और कोई इधर-उधर करेगा तो एक्शन होगा ।

(व्यवधान जारी)

आप पहले जान लीजिए न, पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं । अब हम आपकी बात नहीं सुनेंगे ।

अध्यक्ष : श्री सत्येदव राम जी, अपने स्थान पर जाइये ।

(व्यवधान जारी)

अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है तो आप अपने-अपने स्थान पर चले जाइये।

(व्यवधान जारी)

माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग । माननीय मंत्री संसदीय कार्य बोल रहे हैं, कृपया इनकी बातों को आपलोग सुनिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में माननीय सदस्य ने और बाहर भी जो शिक्षक संगठन के लोग हैं, सारे लोगों ने कहा था कि विद्यालय 9 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक चलने में छात्रों को भी कठिनाई होती है, शिक्षकों को भी कठिनाई होती हैं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप माननीय मंत्री जी की बात सुन लीजिए, अगर इनकी बातों को नहीं सुनियेगा तो कैसे होगा ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : माननीय मुख्यमंत्री जी ने...

(व्यवधान जारी)

अब आपलोग मेरी पूरी बात को सुन लीजिए । अगर आपलोग नहीं सुनेंगे तो कैसे होगा ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप माननीय मंत्री जी की बात सुनना नहीं चाहते हैं, सरकार की बात नहीं सुनना चाहते हैं । आपलोग अपने-अपने स्थान पर जाइये । यह कौन-सा तरीका है ? सरकार जब अपनी बात बता रही है, अगर उसकी बात नहीं सुनियेगा तो क्या होगा ? आप असेम्बली को हाईजैक करना चाहते हैं क्या ?

(व्यवधान जारी)

माननीय मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं पहले उनकी बातों को सुन लीजिए । माननीय मंत्री जी की बात सुनिये और अपने-अपने स्थान पर जाकर बोलिए । माननीय मंत्री जी बोल तो रहे हैं लेकिन आपलोग ही सुनना नहीं चाहते हैं । मंत्री जी बोल रहे हैं तो आपलोग उनको बोलने ही नहीं दे रहे हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कल ही मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में घोषणा की थी कि विद्यालय जो 9 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक चलते थे, जिसके बारे में बच्चों से लेकर के, अभिभावकों से लेकर के और शिक्षकों की शिकायत थी । मुख्यमंत्री जी ने बड़े ही संवेदनशीलता से उस पर निर्णय लेते हुए घोषणा की....

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : फिर आप बीच में बोलना शुरू कर दिये ।

अध्यक्ष : आप माननीय मंत्री जी की बातों को सुन लीजिए ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : आप ही फैसला लिख दीजिए, आप ही विद्यालय 11 बजे सुबह से आने के लिए चिट्ठी निकाल दीजिए । आप हमारी बातों को सुनते ही नहीं हैं । महोदय, आज अगर जो चिट्ठी निकली है, उससे अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई भ्रम की स्थिति है तो आज मुख्यमंत्री जी ने सदन में....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप माननीय मंत्री जी की बात को सुन लीजिए । इसका क्या मतलब है ? यह तरीका नहीं है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : आज मुख्यमंत्री जी ने जो सदन में घोषणा कर दी है कि कक्षाएं 10 बजे सुबह से 4 बजे शाम तक चलेंगी लेकिन शिक्षकों को 15 मिनट पहले यानी पौने दस बजे तक विद्यालय पहुंचना होगा ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आपलोग इनकी बातों को सुनते ही नहीं हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा कर दी है, मतलब वह सरकार का फैसला है और वही लागू होगा ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आपलोग अब अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइये । श्री सत्यदेव राम जी, आप अपनी जगह पर बैठ जाइये । सबलोग अपनी-अपनी जगह पर बैठ जाइये ।

(इस अवसर पर विपक्ष के सारे माननीय सदस्य अपनी-अपनी सीट पर वापस चले गये।)

टर्न-3/यानपति/21.02.2024

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या-375 (श्री अखतरूल ईमान, क्षेत्र संख्या-56, अमौर)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत कलथिया से चिलहाना एल021 तक पथ के नाम से निर्माणाधीन है, जिसमें सिर्फ सरफेस (बी0टी0) का कार्य बचा हुआ है । निर्माण कार्य मार्च 2024 तक पूर्ण करा लिया जायेगा ।

2- में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

3- में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, उत्तर में यह कहा गया है कि.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शून्यकाल में अपनी बात रखिएगा, अभी बैठिए । प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए ।

श्री अखतरूल ईमान : बैसा प्रखंड के चिन्नार जानेवाली सड़क जो 2020 में शुरू हुई, कहा जा रहा है कि इस साल इसको मुकम्मल किया जाएगा । आने जाने वालों को काफी कठिनाई हो रही है, मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि उसका एग्रीमेंट

पीरियड कितने दिनों का था, सड़क कबतक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, यदि ससमय सड़क को कंप्लीट नहीं किया गया तो उस संवेदक के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, उत्तर में स्पष्ट है कि 2024 तक उसको पूरा करा लिया जाएगा ।

श्री अखतरूल ईमान : मैं यह जानना चाहता हूं कि संवेदक का काम पूरा करने की अवधि कब थी सर ।

अध्यक्ष : 2024 में पूरा हो जाएगा ।

श्री अखतरूल ईमान : मैं कह रहा हूं संवेदक को संरक्षण, उसकी गलतियों को छुपाया न जाय, सदन यह जानना चाहता है कि उसका पीरियड कबतक था, आखिर किस वजह से छूट दी गई, यह बताना होगा सर । यह नीतिसंगत मामला है, बताना पड़ेगा कि कबतक होना था, क्यों नहीं हुआ ?

अध्यक्ष : 2024 में पूरा हो जाएगा, काम होने से न मतलब है ।

श्री अखतरूल ईमान : पूरा कब होना था ?

अध्यक्ष : आपने क्या पूछा है, उपरोक्त सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है या नहीं रखती है, इसका जवाब है कि रखती है 2024 तक ।

श्री अखतरूल ईमान : यह संवेदक की गलतियों को छुपाना है । सरकार के भ्रष्टाचार पर यह पर्दा डालना है, सर ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

तारांकित प्रश्न संख्या-376 (श्रीमती मीना कुमारी, क्षेत्र संख्या-34, बाबूबरही)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2- स्वीकारात्मक है ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 0.700 कि0मी0 है । इस पथ का सर्वे छूटे हुए बसावट अंतर्गत मोबाईल ऐप से कुसमार से रजवारा मुसहरी टोला पथ के नाम से किया गया है, जिसका सर्वे आई0डी0-66244 है । तदनुसार समीक्षोपरांत निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

श्रीमती मीना कुमारी : अध्यक्ष महोदय, यह बाबूबरही विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत बाबूबरही और खजौली ब्लॉक को जोड़ती है, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी कि उनका समय सीमा बता दें कि वह कितने दिन में पूरा हो जायेगा ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये, अभी कैसे बात कर सकते हैं ? शून्यकाल में बात करेंगे ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, जल्द ही इसकी कार्रवाई की जायेगी ।

श्रीमती मीना कुमारी : बहुत लंबित है, बहुत दिनों से है थोड़ा समय सीमा हमको बता दिया जाय ।

अध्यक्ष : जल्द ही तो कह रहे हैं माननीय मंत्री जी ।

श्रीमती मीना कुमारी : जल्द ही मतलब एक महीना या एक साल ?

तारांकित प्रश्न संख्या-377 (श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव, क्षेत्र संख्या-90, मीनापुर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-378 (श्री नारायण प्रसाद, क्षेत्र संख्या-6, नौतन)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, (क) अस्वीकारात्मक । पश्चिम चंपारण जिलांतर्गत नौतन प्रखंड के गहीरी मन में कोई नलकूप अधिष्ठापित नहीं है।

मंगलपुर गुदरिया में दो नलकूप क्रमशः मंगलपुर गुदरिया-1 तथा मंगलपुर गुदरिया-2 अधिष्ठापित है जिसे दिनांक-05.09.2023 तथा 25.09.2023 को चालू करा दिया गया है ।

नौतन प्रखंड के शिवराजपुर पंचायत में अवस्थित शिवराजपुर नलकूप का कमांड क्षेत्र समाप्त हो जाने के कारण उसे परित्यक्त कर दिया गया है ।

(ख) उपरोक्त खंड ''क'' में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री नारायण प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, हमको जवाब मिल गया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं अपने उप मुख्यमंत्री जी को ।

तारांकित प्रश्न संख्या-379 (श्रीमती निशा सिंह, क्षेत्र संख्या-66, प्राणपुर)

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए ।

श्रीमती निशा सिंह : उत्तर नहीं मिला है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिए, शून्यकाल में बात रखी जायेगी, अभी समय नहीं है । आप प्रश्नोत्तर काल नहीं चलाना चाहते हैं ? यह अधिकांश आपके ही मेंबर का प्रश्न है । कितना बढ़िया से तीन-चार दिन से काम कर रहे थे आप । आज आपको क्या हो गया है? 2024 का चुनाव होनेवाला है, जनता देख रही है कि क्या करनेवाले हैं आपलोग। जनता देख रही है कि आप जनता के हितों की कितनी चिंता कर रहे हैं । जो समय निर्धारित है जिस काम के लिए, कार्यसंचालन नियमावली के अनुसार ही मैं

काम करूंगा और वह यही कहता है कि मैं शून्यकाल में आपकी बात सुनूंगा, अभी बैठिए अपने स्थान पर ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग । निशा जी का उत्तर पढ़ दीजिए ।

(व्यवधान)

शून्यकाल में आपकी बात सुनूंगा, अभी कैसे विचार कर सकता हूं । प्रश्नोत्तर के बाद ही विचार करेंगे । यही नियम कहता है, मैं नियम के अनुसार चलूंगा । माननीय मंत्री जी, निशा सिंह जी का उत्तर पढ़ दीजिए उन्हें उत्तर नहीं मिला है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिलांतर्गत प्रश्नगत आजमनगर बाजार एवं सालमारी बाजार पथांश आजमनगर लिंक पथ का अंश है जो ओ0पी0आर0एम0सी0-2 वर्ष-2022 की योजना अंतर्गत संधारित है एवं पथ की स्थिति अच्छी है दोनों बाजार पथांश में नाला निर्माण तकनीकी सम्यता संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप विचार किया जायेगा ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

अध्यक्ष : आपलोग जबर्दस्ती करेंगे क्या ? नियम कहता है कि प्रश्नोत्तर काल के बाद विचार करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अपने स्थान पर जाइये । कोई बात आपकी दर्ज नहीं होगी, कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जायेगी, अपने स्थान पर बैठिए । वेल से कही जानेवाली कोई भी बात प्रोसीडिंग में दर्ज नहीं होगी, कोई बात सुनी भी नहीं जायेगी।

माननीय सदस्या श्रीमती निशा जी, आप बोलिये ।

श्रीमती निशा सिंह : महोदय, वहां बरसात के टाइम में हमेशा पानी जमा रहता है तो उनके लिए अभी तो बहुत जरूरत है ड्रेनेज सिस्टम का ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, स्पष्ट तौर पर जवाब दे दिया गया है कि प्राथमिकता के अनुरूप विचार किया जायेगा, उपलब्धता होने पर ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्रीमती निशा सिंह : उपलब्धता तो है, जरूरत बहुत ज्यादा है, हम बार-बार इस क्वेश्चन को लाये भी हैं मगर कोई जवाब सही नहीं मिला है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अब उसकी एक बार समीक्षा कर लेते हैं, अगले वित्तीय वर्ष में हमलोग देखेंगे ।

श्रीमती निशा सिंह : जी धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या–380 (श्री विजय कुमार मण्डल, क्षेत्र संख्या–210, दिनारा)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–381 (श्री राकेश कुमार रौशन, क्षेत्र संख्या–174, इस्लामपुर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–382 (श्री छोटे लाल राय, क्षेत्र संख्या–121, परसा)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–383 (श्री राजेश कुमार गुप्ता, क्षेत्र संख्या–208, सासाराम)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–384 (श्री अजीत कुमार सिंह, क्षेत्र संख्या–201, डुमरांव)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–385 (श्री सुरेन्द्र मेहता, क्षेत्र संख्या–142, बछवाड़ा)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्वीकारात्मक । न्यू पुनाईचक पटना, विधायक आवास–आर/1 में भवन के अंदर रंगाई–पोताई का कार्य हो गया है । वर्तमान में नाला एवं कैंपस के अंदर बने गार्ड रूम के बाहरी भाग में कार्य किया जा रहा है । मुख्य भवन आर/1 के बाहरी भाग के रंगाई–पोताई का कार्य 2024–25 के प्राथमिकता सूची में शामिल कर करा दिया जायेगा ।

श्री सुरेन्द्र मेहता : जल्द से जल्द उस कार्य को कर दिया जाय ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, यह काम जो प्रश्न में जिसकी बात की गई है वहां पर बाकी काम कराया जा रहा है और जो बचा हुआ काम है उसको भी अगले वित्तीय वर्ष में हमलोग करा देंगे ।

श्री सुरेन्द्र मेहता : महोदय, इस भवन का तीन साल से कोई रंगाई–पोताई नहीं हुआ है और जब यहां सवाल उठता है तब जाकर कुछ–कुछ करता है, सेशन खत्म हो जाता है तो फिर बंद कर देता है । इसलिए आग्रह है कि जल्द से जल्द इसको करवा दिया जाय ।

अध्यक्ष : आपकी बात को भवन निर्माण मंत्री जी सुने हैं, कह रहे हैं कि अगले वित्तीय वर्ष में करा देंगे तो हो ही जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या–386 (श्री रित लाल राय, क्षेत्र संख्या–186, दानापुर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-387 (श्री हरीभूषण ठाकुर ''बचोल'', क्षेत्र संख्या-35, बिस्फी)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2- स्वीकारात्मक है ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ नई अनुरक्षण नीति 2018 योजना अंतर्गत एस0एच0 से चहुता पथ के नाम से स्वीकृत है, जिसकी लंबाई 2.56 कि0मी0 है । पथ का एकरारनामा किया जा चुका है । वित्तीय वर्ष 2021-22 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से पथ काफी क्षतिग्रस्त हो गया है । उक्त स्थिति में पूर्व में प्रावधानित प्राक्कलन के अनुसार वर्तमान में कार्य करना संभव नहीं है । पथ के क्षतिग्रस्त पथांश को शामिल करते हुए पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया है, जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है । तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री हरीभूषण ठाकुर ''बचोल'' : महोदय, पूरक है कि 2021-22 में इसका टेंडर हुआ और आजतक यह सड़क नहीं बनी है, सड़क कब तक बनेगी, दोषी पदाधिकारी जो फाइल पर कुंडली मारकर बैठे रहते हैं दो-दो साल से पुनरीक्षित नहीं होता है और एक डिवीजन में सौ-सौ करोड़ का काम हो रहा है.....

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए ।

श्री हरीभूषण ठाकुर ''बचोल'' : पूरक है कि कबतक सड़क बन जायेगी और दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, इसमें लिखा हुआ है बाढ़ के कारण क्षति हो गई थी और उसके क्षतिग्रस्त पथांश को शामिल करते हुए पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया है जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई जल्द ही की जायेगी।

श्री हरीभूषण ठाकुर ''बचोल'' : महोदय, वहां बाढ़ आई ही नहीं यह बिल्कुल अपना मनगढ़ंत किया है, अगर बाढ़ आई तो फ्लड कंट्रोल से पैसा जाता है रिपेयरिंग का वह भी पैसा खा गया और उसके बाद आज, इसकी जांच मंत्री जी करवा दें ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसको दिखवा लेंगे ।

श्री हरीभूषण ठाकुर ''बचोल'' : दिखवा लेंगे का मतलब क्या है ?

टर्न–4/अंजली/21.02.2024

अध्यक्ष : वही हुआ न । दिखवाने का मतलब क्या होता है । श्री कुंदन कुमार ।

तारांकित प्रश्न सं0–388 (श्री कुंदन कुमार, क्षेत्र सं0–146, बेगूसराय)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

2. स्वीकारात्मक है ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लंबाई 1.00 किलोमीटर है । इस पथ का सर्वे छूटे हुए बसावट अंतर्गत मोबाईल ऐप से किया गया है, जिसका सर्वे आई0डी0–30494 है । तद्नुसार समीक्षोपरांत निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है पूरक पूछिये ।

श्री कुंदन कुमार : जी महोदय, पूरक पूछ रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, यह मामला बेगूसराय प्रखंड के कैथ पंचायत का है । यह दमदामा चैहरमल स्थान से सांगों कोठी का रोड है और महोदय, यह रोड जहां से शुरू होता है और जहां खत्म होता है केवल दलित आबादी है, पिछड़ा/अतिपिछड़ा और यह एकल संपर्क का मामला है, मतलब आज तक इसका संपर्क पथ भी नहीं बना है और अभी तक प्रायोरिटी में नहीं लिया जा रहा है तो इसको क्यों नहीं बनवाना चाह रही है, सरकार यह जवाब दे दे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, उत्तर में स्पष्ट लिखा हुआ है वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लंबाई 1.00 किलोमीटर है । इस पथ का सर्वे छूटे हुए बसावट अंतर्गत मोबाईल ऐप से किया गया है, जिसका सर्वे आई0डी0–30494 है । तदनुसार समीक्षोपरांत निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह दस महीना पहले जब उस समय तत्कालीन मंत्री श्री तेजस्वी यादव जी थे उन्होंने चिट्ठी लिखकर जवाब दिया था कि इसको इससे सर्वे करा लिया गया है इसका नंबर है । अब 12 महीना होने के लिए आया है और पक्ष में हो या विपक्ष में इस सदन में हमलोग बड़ी–बड़ी बात अतिपिछड़ा, दलित का करते हैं । एक संपर्क पथ हम देना नहीं चाह रहे हैं । यह कब तक होगा ? ये कब तक इसको प्रायोरिटी में लेंगे यह बतावें मंत्री जी ।

अध्यक्ष : देना नहीं चाह रहे हैं ऐसा सरकार ने नहीं कहा है ।

श्री कुंदन कुमार : महोदय, अभी इसमें साफ जवाब लिखा हुआ है दिखवा लेंगे, कब तक करेंगे, प्रायोरिटी होगा, पैसा होगा तो देंगे । यह दलितों का मामला है, अतिपिछड़ों

का मामला है, इसको इसमें अभी आज सदन में दिया जाय आश्वासन कि इसको तुरंत...

अध्यक्ष : जल्दी करा दीजिए माननीय मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, इसको मैंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा ।

अध्यक्ष : प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा । माननीय सदस्य श्री राज कुमार सिंह ।

तारांकित प्रश्न सं0-389 (श्री राज कुमार सिंह, क्षेत्र सं0-144, मटिहानी)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि गंगा नदी के बाढ़ से बचाव के लिए उत्तरी किनारे पर जल संसाधन विभाग का गुप्ता लखमिनियाँ तटबंध है, जो NH-31 के किलोमीटर 206 (चकिया BTPS) से प्रारम्भ होकर NH-31 के किलोमीटर 242 से प्रारम्भ होने वाली मुंगेर घाट-रसीदपुर पथ के 12वें किलोमीटर में मिलती है, जिसकी कुल लम्बाई 35.05 कि0मी0 है ।

जल संसाधन विभाग से NOC प्राप्त कर गुप्ता लखमिनियाँ तटबंध की पूरी लम्बाई (35.05 कि0मी0) एवं 3.75 मीटर चौड़ाई में मजबूतीकरण कार्य दिनांक- 30.11.2023 को ही पूर्ण किया जा चुका है ।

तकनीकी संभाव्यता, संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप चौड़ीकरण पर विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये ।

श्री राज कुमार सिंह : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि क्या सरकार समझती है कि गुप्ता लखमिनियां बांध का ये जो 35 किलोमीटर की लंबाई है इसका अगर चौड़ीकरण करके इसको फोर लेन में तब्दील कर दिया जाय तो कई लक्ष्यों की प्राप्ति एक साथ हो सकती है । पहले तो शहर को जाम से निजात मिलेगा । दूसरा, सरकार का जो लक्ष्य बिहार के किसी भी भाग से पटना पांच घंटे के अंदर पहुंचने का, उस लक्ष्य को भी साधने में यह सहायक होगा और साथ ही साथ चूंकि यह 35 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से होकर गुजरता है तो इसको फोरलेन बना देने से वहां के लोगों के लिए एक अतिरिक्त जीवनरेखा का भी वहां पर निर्माण होगा और अगर सरकार ऐसा समझती है तो क्या इसको प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द चौड़ीकरण करना चाहती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस पथ का ये जिक्र कर रहे हैं निश्चित तौर पर वह उस क्षेत्र के लिए आवश्यक है और इसको प्राथमिकता

के आधार पर विभाग लेगा और अगले वित्तीय वर्ष में इस प्राथमिकता को मूर्त रूप देने का प्रयास करेगी ।

श्री राज कुमार सिंह : बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अरूण सिंह ।

तारांकित प्रश्न सं0-391 (श्री अरूण सिंह, क्षेत्र सं0-213, काराकाट)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-392 (श्री कुमार शैलेन्द्र, क्षेत्र सं0-152, बिहपुर)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिये । उत्तर संलग्न है ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, मैंने उत्तर नहीं लिया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग, उत्तर पढ़ दीजिए ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2. स्वीकारात्मक ।

3. जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-460, दिनांक-12.02.2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रखंड नारायणपुर अंतर्गत पंचायत जयपुर चूहर पूरब, ग्राम सभा में रामूचक घाट का सौन्दर्यीकरण कराने से संबंधित योजना को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 15वें वित्त आयोग में पारित किया गया है । 15वें वित्त आयोग की राशि प्राप्त होते ही, अब इस योजना के कार्यान्वयन को पूर्ण किया जाएगा ।

अध्यक्ष : हो गया, अब क्या है ?

श्री कुमार शैलेन्द्र : धन्यवाद है । बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री चेतन आनंद ।

तारांकित प्रश्न सं0-393 (श्री चेतन आनंद, क्षेत्र सं0-22, शिवहर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 2.045 किलोमीटर है । इस पथ का सर्वे छूटे हुए बसावट अन्तर्गत मोबाईल ऐप से जानकी साह मोड़ से रेजमा PMGSY पथ के नाम से किया गया है, जिसका सर्वे आई.डी.-32180 है । तद्नुसार समीक्षोपरांत निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये ।

श्री चेतन आनंद : महोदय, यह जो सड़क है यह शिवहर प्रखंड के तीन मेजर गांव जो कि गम्हरिया, परसौनी और रेजमा को जोड़ती है और वहां की जनसंख्या देखते हुए इसको जल्द से जल्द कराने का आग्रह करता हूं ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्या सुश्री श्रेयसी सिंह ।

तारांकित प्रश्न सं0-394 (सुश्री श्रेयसी सिंह, क्षेत्र सं0-241, जमुई)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, यह योजना एवं विकास विभाग में स्थानांतरित है ।

अध्यक्ष : अगली बार में ।

सुश्री श्रेयसी सिंह : अध्यक्ष महोदय, तिथि तय कर दी जाय कि किस दिन हाऊस में यह सवाल आएगा ।

अध्यक्ष : अगली बार आएगा । जब आएगा इस विभाग का डेट तो ऑटोमैटिक आता है । स्थगित हुआ है ।

तारांकित प्रश्न सं0-395 (श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह, क्षेत्र सं0-1, वाल्मीकिनगर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न दो पुलों से संबंधित है, जिसकी स्थिति निम्नवत है:-

1. PMGSY में मिश्रौली से मझौवा के बीच सड़क में पुल:- यह पुल निर्मित मिश्रौली से मझौवा पथ के आरेखन पर अवस्थित है ।

2. हरनाटांड-कुनई पथ में बरखा तरूअनवा के बीच सड़क में पुल:- यह पुल निर्मित सेमरा से तरूअनवा पथ के आरेखन पर अवस्थित है ।

उक्त दोनों पुल के निर्माण हेतु चेक लिस्ट प्राप्त हुआ है । तदनुसार तकनीकी समीक्षोपरांत निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये ।

श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह : महोदय, जवाब मिल गया है लेकिन एक आग्रह था कि मझौवा वाला जो दिखाया जा रहा है मिश्रौली से मझौवा तक चूंकि इसमें दो-तीन गांव का जुड़ाव होता है और बहुत से बच्चे हैं जिनको दस-दस किलोमीटर की दूरी तय करके उसके बाद विद्यालय जाना पड़ता है या कहीं जाना पड़ता है तो माननीय मंत्री जी आग्रह है आपके माध्यम से कि इसको अगर विलंब करवा दिया जाता तो बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा रहता ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, ठीक है दिखवा लेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-396 (श्री अचमित ऋषिदेव, क्षेत्र सं0-47, रानीगंज (अ0जा0))

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अचमित ऋषिदेव । उत्तर संलग्न है पूरक पूछिये ।

श्री अचमित ऋषिदेव : जी पूछता हूं ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, नहीं देखे हैं क्या ?

श्री अचमित ऋषिदेव : महोदय, उत्तर नहीं आया है ।

अध्यक्ष : उत्तर आया तो है आप देखे नहीं हैं । माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, श्री अचमित ऋषिदेव जी का उत्तर पढ़ दीजिए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि समाप्त हो चुकी है । वर्तमान में पथ क्षतिग्रस्त है । उक्त पथ के मरम्मती/उन्नयन हेतु RCD रोड सुकेला मोड़ से हरपुर कलान भाया खजुरी तक पथ के नाम से चयन की प्रक्रिया में है । तत्पश्चात् समीक्षोपरांत प्राथमिकता एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य श्री राम विशुन सिंह ।

तारांकित प्रश्न सं0-398 (श्री राम विशुन सिंह, क्षेत्र सं0-197, जगदीशपुर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-399 (श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, क्षेत्र सं0-10, रक्सौल)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 0.550 किलोमीटर है जो कच्ची है । उक्त पथ के निर्माण हेतु सर्वे छूटे हुए बसावट अन्तर्गत मोबाईल एप से किया गया है, जिसका सर्वे आई0डी0-66230 है । तदनुसार समीक्षोपरांत निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये ।

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कब तक रोड की स्थिति बनावाएंगे ?

अध्यक्ष : बताइए, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग । कब तक करायेंगे ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, जल्द ही अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजीव कुमार सिंह ।

तारांकित प्रश्न सं0-400 (श्री राजीव कुमार सिंह, क्षेत्र सं0-164, तारापुर)

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है पूरक पूछिये ।

श्री राजीव कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो क्वेश्चन किया था वह जल संसाधन विभाग में लेकिन यहां आंसर आया है कि इसको लघु जल संसाधन विभाग से स्थानांतरण

कर दिया गया है जल संसाधन विभाग में तो अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि इसको इसी सत्र में दिखला दिया जाय ।

अध्यक्ष : उत्तर तो मिला होगा न आपको ।

श्री राजीव कुमार सिंह : महोदय, स्थानांतरित कर दिया गया है ।

अध्यक्ष : जवाब है । आप बैठ जाइए । सुनिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, प्रश्न का तो उत्तर अपलोड कर दिया गया है ।

अध्यक्ष : देखे नहीं होंगे ।

श्री राजीव कुमार सिंह : महोदय, उत्तर आया है ।

अध्यक्ष : तो पूरक पूछिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : उत्तर देख लिये हैं ?

श्री राजीव कुमार सिंह : लघु जल संसाधन विभाग से आया है कि यह स्थानांतरित कर दिया गया है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : जल संसाधन में आ गया है तो जल संसाधन की तरफ से उत्तर आपको दे देते हैं ।

श्री राजीव कुमार सिंह : महोदय, ऐसा है कि यह किसानों के हित...

अध्यक्ष : आप पहले सुन तो लीजिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : आप बिना उत्तर सुने पूरक क्यों पूछ रहे हैं ?

महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बांका जिलान्तर्गत बेलहर प्रखंड में बदुआ नदी पर बदुआ डैम निर्मित है जिससे बदुआ बायां मुख्य नहर निकलती है । बदुआ बायां मुख्य नहर के चेन संख्या-181 से बदुआ बेलहरना लिंक नहर निकलती है जिसकी कुल लंबाई 2.74 किलोमीटर है । इस लिंक नहर के माध्यम से बेलहर एवं संग्रामपुर प्रखंडों के किसानों को सिंचाई सुविधा मुहैया कराई जाती है । बदुआ बेलहरना लिंक नहर से खरीफ 2022 एवं 2023 में निर्धारित सिंचाई लक्ष्य जो 490 हेक्टेयर था के विरुद्ध बेलहर और संग्रामपुर में जो सूचना है उस हिसाब से पूर्ण शत् प्रतिशत सिंचाई दी गई है । वर्तमान में बदुआ बेलहरना लिंक नहर में आंशिक गाद जमा हुआ है लिंक नहर में जमा गाद की सफाई कर खरीफ वर्ष 2024 मतलब मई-जून से पहले इसकी सफाई करा दी जाएगी जो सिल्ट गाद जमा हुआ है और किसानों को समुचित सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी ।

श्री राजीव कुमार सिंह : आभार प्रकट करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री शंभू नाथ यादव ।

तारांकित प्रश्न सं0-401 (श्री शंभू नाथ यादव, क्षेत्र सं0-199, ब्रहमपुर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-402 (श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह, क्षेत्र सं0-109, दरौंदा)
(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-403 (श्री महा नंद सिंह, क्षेत्र सं0-214, अरवल)
(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-404 (श्रीमती भागीरथी देवी, क्षेत्र सं0-2, रामनगर (अ0जा0)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुलिया PMGSY-III के अन्तर्गत स्वीकृत MRL 16 नरकटियागंज मनवा परसी रोड से एकडेरवा पथ, लम्बाई 14.47 किलोमीटर के चैनेज 550 मीटर पर अवस्थित है, जो क्षतिग्रस्त है । उक्त पथ के DPR में इस क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 6 (छः) मीटर स्पैन का RCC Culvert का प्रावधान किया गया है । निविदा के माध्यम से पथ के साथ पुलिया का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : उत्तर चला गया है, पूरक पूछिये । भागीरथी देवी जी ।

श्रीमती भागीरथी देवी : माननीय अध्यक्ष जी, बेतिया जिलान्तर्गत गौनाहा प्रखंड है और वहां से लखन खोर गांव है और लखन खोर से एकडेरवा जाने के लिए रास्ता एकदम नहीं है, वह नाली एकदम जर्जर हो गया है उस नाली के कारण आने-जाने में खतरा है, कम से कम उसको बनवा दिया जाय ।

टर्न-5/आजाद/21.02.2024

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जल्द ही निविदा करके इस काम को कराया जायेगा ।

अध्यक्ष : जल्दी टेंडर करके काम कराया जायेगा, माननीय मंत्री जी ने कहा है ।

तारांकित प्रश्न सं0-405(श्री पवन कुमार यादव,क्षेत्र संख्या-155,कहलगांव)
(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ के उन्नयन/मरम्मती हेतु एन0एच0-80(जानमोहम्मदपुर) से मुडकटिया चौक तक पथ के नाम से चयन की

कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । चयन के उपरांत ट्राफिक सर्वे के अनुसार प्राक्कलन तैयार किया जायेगा । तत्पश्चात् समीक्षोपरांत प्राथमिकता एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई जाना संभव हो सकेगा ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए ।

श्री पवन कुमार यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, कब तक रोड बनेगा ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, जल्दी इसपर प्रयास किया जायेगा, जल्द से जल्द इसपर कार्रवाई हो जाय ।

अध्यक्ष : जल्दी होगी ।

तारांकित प्रश्न सं0-406(श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी,क्षेत्र सं0-200,बक्सर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-407(श्री रामवृक्ष सदा,क्षेत्र सं0-148,अलौली(अ0जा0)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-408(श्री सिद्धार्थ सौरव,क्षेत्र सं0-191,बिक्रम)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-409(श्री प्रहलाद यादव,क्षेत्र सं0-167,सूर्यगढ़ा)

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए प्रहलाद जी ।

श्री प्रहलाद यादव : अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं देखे हैं सर ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, उत्तर पढ़ दीजिए प्रहलाद जी का ।
ग्रामीण कार्य विभाग के पथ को पथ निर्माण विभाग में लेने के लिए प्रश्न किया है? सरकार ने तय किया है कि अभी नहीं लेना है । ग्रामीण कार्य विभाग ने कहा है कि हम अपने पथों को बनायेंगे। यही निर्णय है सरकार का । क्या है माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : यह प्रश्न लगता है कि सुविचारित तरीके से आया है । जवाब मिल गया है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत है । पथ अधिग्रहण की नई नीति पत्रांक-1548 दिनांक 25.02.2020 के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अपने स्वामित्व वाले पथों का उन्नयन स्वयं कराया जाना है ।

अध्यक्ष : यही तो मैंने कहा है । नियम तो हमको मालूम था, यही हमने कहा है । ग्रामीण कार्य विभाग ही अपने पथों को बनायेगा ।

श्री प्रहलाद यादव : अध्यक्ष महोदय, चूँकि आपका पूरा जो रोड है, ओलीपुर चौक से पूरा रोड पथ निर्माण विभाग है, बहुत छोटा सा अंश बचा हुआ है । ग्रामीण कार्य विभाग से उस पथ की मरम्मती और अनुश्रवण सही ढंग से नहीं होता है, इसलिए माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, इनका भी क्षेत्र है और मेरा भी क्षेत्र है, दोनों आदमी का क्षेत्र है .....

अध्यक्ष : तब फिर क्या दिक्कत है ?

श्री प्रहलाद यादव : इसलिए हम आग्रह करेंगे कि इसपर निश्चित रूप से विचार कीजियेगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : माननीय सदस्य का कहना सही है महोदय, यह जनोपयोगी है और इसको ग्रामीण कार्य विभाग भेजेगा तो पथ निर्माण विभाग इसको प्राथमिकता में लेकर के करायेगी ।

श्री प्रहलाद यादव : बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी ।

तारांकित प्रश्न सं0-410(श्रीमती बीमा भारती,क्षेत्र सं0-60,रूपौली)

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए ।

श्रीमती बीमा भारती : महोदय, उत्तर नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग, उत्तर पढ़ दीजिए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : इसका सर्वे वगैरह करवा लिया गया है, जल्द ही इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी ।

अध्यक्ष : जल्द प्रक्रिया पूरी की जायेगी ।

श्रीमती बीमा भारती : कब तक होगा अध्यक्ष महोदय ?

अध्यक्ष : जल्दी ।

तारांकित प्रश्न सं0-411(श्री ललन कुमार,क्षेत्र सं0-154,पीरपैंती(अ0जा0)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगांव प्रखंड के कैरिया ग्राम के पास कौआ नदी तथा पीरपैंती प्रखंड के राजगांव अराजी ग्राम के पास मैनी नदी में माह जुलाई से मार्च तक जलश्राव उपलब्ध रहता है ।

प्रश्नगत स्थलों पर वीयर/अन्य संरचना का निर्माण कर आस-पास के ग्रामों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने की कार्य योजना की तकनीकी संभाव्यता की जॉच एक माह के अन्दर कर ली जायेगी । तकनीकी रूप से संभाव्य पाये जाने पर योजना का कार्यान्वयन करा लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए ।

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर के कहलगांव के कैरिया के कौआ नदी पर और पीरपैंती अंचल के राजगांव अराजी के मैनी नदी पर सुलिस गेट बनाने का और सरकार का उत्तर लेकिन के साथ है । बहुत सकारात्मक जवाब आया है कि टेकनिकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक महीने के अन्दर मंगवा लेंगे वो और उसके बाद इसपर काम करेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब सकारात्मक है लेकिन इसमें .....

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए ।

श्री ललन कुमार : महोदय, पूरक ही पूछ रहा हूँ कि आप इसको इम्पोर्टेंस को समझिए, अगर यह छोटी सी नदी है और इसपर अगर सुलिस गेट बन जायेगा, स्थायी रूप से हजारों किसानों को सिंचाई का पानी मिलेगा और अर्थ चार्ज भी होगा । चूँकि उस इलाके में लगातार पानी का जो लेवल नीचे जा रहा है, वह भी ऊपर आयेगा । जहां तक टेकनिकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट का सवाल है, अब तकनीक इतना ऊपर जा चुका है अध्यक्ष महोदय कि समुद्र पर पुल बन रहे हैं .....

अध्यक्ष : आप अपने प्रश्न का पूरक पूछिए न ।

श्री ललन कुमार : महोदय, हम इतना ही पूछना चाह रहे हैं सरकार से कि हम सरकार की बात से सहमत हैं कि जल्द से जल्द इस टेकनिकल रिपोर्ट को मंगाकर के इसको करेंगे। टेकनिकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बहाने इसको कहीं पेंडिंग में न पड़ जाय, हम यही कह रहे हैं ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री ललन कुमार : महोदय, इसको करना चाहते हैं, टेकनिकल रिपोर्ट मंगवाकर के दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : अब बैठिए, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हम तो विभाग के तरफ से ललन जी को धन्यवाद देते हैं कि एक सही योजना के कियान्वयन के लिए इन्होंने प्रश्न पूछा है । लेकिन उत्तर में हमने तो स्पष्ट कह दिया है कि कहीं पर कोई भी स्ट्रक्चर, वियर, बांध कुछ

भी बनेगा तो उसकी टेकनिकल रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट ली ही जाती है और वह भी महोदय, हमने ऑपेन नहीं छोड़ा है, हमने कहा है कि एक महीना के अन्दर मंगाकर के और अगर वहां पर कोई स्ट्रक्चर बनाकर के पानी जमा कर लेने से किसानों को सुविधा मिलेगी तो सरकार इसको जरूर कियान्वित करेगी ।

अध्यक्ष : अब बात हो गई ।

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, हम इतना ही चाहते हैं, धन्यवाद देते हुए क्षेत्र के लोगों के साथ, अब तकनीक बहुत ऊपर जा चुका है, सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इसको करवावे, बहुत ही बेहतर हित है । कल ही माननीय मंत्री जी का जल को लेकर इतना अच्छा संबोधन हुआ है सर सदन में और इसको करा लेंगे, हम इस उम्मीद के साथ सरकार को धन्यवाद देते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, हमेशा अच्छा ही बोलते हैं ।

श्री ललन कुमार : जी-जी, धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0-412(श्रीमती अरूणा देवी,क्षेत्र सं0-239,वारिसलीगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि नवादा जिलान्तर्गत प्रश्नगत पकरीवरांवा बाईपास का निर्माण, तकनीकी संभाव्यता, संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए ।

श्रीमती अरूणा देवी : सर, उत्तर तो मिल गया है लेकिन सही नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्रीमती अरूणा देवी : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि बाईपास जो है पकरीबरांवा प्रखंड में, कई बार लिखकर दिये हैं कि बनाना जरूरी है, क्योंकि वहां पर घंटो-घंटा जाम रहता है, पुलिस अनुमंडल है, वहां पर जनसंख्या भी अधिक है । घंटों-घंटा जाम रहने से हमलोगों को बहुत कठिनाई होता है और यहां पर बाईपास बनना जरूरी है। वहां का डिमांड है पब्लिक का, इसलिए कब तक बनेगा, समय सीमा बता दिया जाय ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : इनका प्रश्न था बाईपास का, स्पष्ट बताया गया कि नवादा जिलान्तर्गत प्रश्नगत पकरीवरांवा बाईपास का निर्माण, तकनीकी संभाव्यता, संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप विचार किया जायेगा और माननीय सदस्य का व्यस्ततम सड़क है, जाम रहता है, अगले वित्तीय वर्ष में हमलोग इसको प्राथमिकता में लेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-413(श्रीमती गायत्री देवी,क्षेत्र सं0-25,परिहार)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 1. स्वीकारात्मक है ।

2. स्वीकारात्मक है ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ राज्य योजना अन्तर्गत निर्मित बेतहा से सिरसिया पथ, लम्बाई 5.72 कि0मी0 का पथांश है । उक्त पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है । निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर पथ का मरम्मति/उन्नयन कार्य कराया जा सकेगा ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए ।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, जो सड़क है, जब्दी से लेकर बेतहा तक ग्रामीण क्षेत्र है और उसमें आवागमन बहुत बंद हो जाता है । मैं मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि इसको कब तक बनवा देंगे, बस एक समय सीमा तय कर दें ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, इसपर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जायेगा।

अध्यक्ष : धन्यवाद । अगले वित्तीय वर्ष में हो जायेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-414(श्री अचमित ऋषिदेव,क्षेत्र सं0-47,रानीगंज(अ0जा0)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्मित मध्य विद्यालय बेरिक से शर्मा टोला तक पथ के आरेखन पर अवस्थित है । इसके निर्माण हेतु टेक्नो फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है, जिसकी तकनीकी समीक्षोपरांत एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए ।

श्री अचमित ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत कोशकापुर दक्षिण वार्ड नं0-1 में लच्छा धार के दोनों ओर घनी आबादी में मुख्यमंत्री सम्पर्क योजना से निर्मित सड़क में ब्रीज गैप है, जिससे लोगों को आवागमन में कठिनाई होती है ।

अध्यक्ष : क्या पूछे आप ? कुछ पूरक पूछिए न ।

श्री अचमित ऋषिदेव : सर, बीच में दोनों साईड में रोड बना हुआ है अध्यक्ष महोदय, बीच में गैप है, जिसके चलते लोगों को आने-जाने में काफी कठिनाई होती है । माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इस गैप को पूरा कर दिया जाय ।

अध्यक्ष : आग्रह करोगे तो जवाब कैसे आयेगा भाई ? आप पूरक पूछिए कि जानना चाहते हैं, कुछ प्रश्न पूछिए ?

श्री अचमित ऋषिदेव : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कब तक इस गैप रोड को बनवा देंगे ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, इसका टेकनिकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगवाकर इसको देखा जायेगा और उसके बाद कार्रवाई की जायेगी ।

तारांकित प्रश्न सं0-415(श्री मुकेश कुमार यादव,क्षेत्र सं0-27,बाजपट्टी)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-416(श्री दिलीप राय, क्षेत्र सं0-26,सुरसंड)

(लिखित उत्तर)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत चोरौत प्रखंड कार्यालय सह अंचल कार्यालय सह आवासीय भवन के निर्माण हेतु जिला स्तर पर भी भूमि चयन किया गया है । जिला से विधिवत रूप से भूमि का प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए ।

श्री दिलीप राय : महोदय, सीतामढ़ी जिला के चोरौत प्रखंड सामुदायिक भवन में करीब 25 वर्षों से चल रहा है । सरकार इसको कब तक बनाने का विचार रखती है, वहां की जनता को सामुदायिक भवन में प्रखंड एवं अंचल कार्यालय होने के कारण काफी कठिनाई होती है, इसलिए एक समय सीमा बता दिया जाय ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है । भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी महोदय ।

श्री दिलीप राय : महोदय, भूमि अधिग्रहण का काम हो चुका है, जिलास्तर से हो चुका है, कमीश्नरी स्तर से हो चुका है । राज्यस्तर पर पेंडिंग है सर ।

अध्यक्ष : अगर आ गया है तो इसको देखवा लीजिए और इसको करवा दीजिए ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, मैंने कहा है कि नियमानुसार कार्रवाई होगी, अगर भूमि अधिग्रहण हो गया है तो आगे की कार्रवाई की जायेगी ।

टर्न-6/शंभु/21.02.24

तारांकित प्रश्न सं0-417(श्री उमाकांत सिंह)क्षेत्र सं0-7,चनपटिया

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : 1-स्वीकारात्मक है ।

2-स्वीकारात्मक है ।

3-वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न दो पथों से संबंधित है :- छावनी मैनाटांड मुख्य पथ से बेलवा गांव जानेवाली पथ- उक्त पथ की लंबाई 2.80 कि0मी0 है, जो शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाइ0 अन्तर्गत एल0ओ0-51 बैलथा डीह बेलबंदो बस्ती के नाम से निर्मित है । पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है । पथ की मरम्मति हेतु नई अनुरक्षण नीति, 2018 अन्तर्गत डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है । तद्नुसार निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रेतर

कार्रवाई की जा सकेगी । छावनी मैनाटाड मुख्य पथ से यादोछापर गांव जाने वाली पथ- उक्त पथ की लंबाई 2.50 कि0मी0 है, जो एल0डब्लू0इ0 प्रभावित जिला के आइ0ए0पी0 योजना अन्तर्गत मैनाटाड चौक रोड से यादवछापर भाया हरिजन बस्ती के नाम से निर्मित है । पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है । पथ की मरम्मति हेतु नई अनुरक्षण नीति 2018 अन्तर्गत निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए उमाकांत जी ।

श्री उमाकांत सिंह : महोदय, मैनाटांड रोड में चनपटिया प्रखंड के बेलवा जाने के लिए सड़क अति जर्जर हो गयी है तो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि राशि की उपलब्धता के बाद तो कब तक राशि आयेगी ? सड़क की स्थिति खराब है गांव में आने जाने का मुख्य मार्ग है । इसलिए मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूँ कि कब तक रोड को बना देंगे ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : डी0पी0आर0 बनाया जा रहा है अगले वित्तीय वर्ष में इसको देखा जायेगा ।

अध्यक्ष : अगले वित्तीय वर्ष में होगा ।

श्री उमाकांत सिंह : डी0पी0आर0 बन चुका है और उसका आ भी गया है ।

अध्यक्ष : अगले वित्तीय वर्ष के लिए बात की उन्होंने ।

तारांकित प्रश्न सं0-418(श्रीमती शालिनी मिश्रा)क्षेत्र सं0-15 केसरिया

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना के तहत बिहार के पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया और किशनगंज जिलों से होकर गुजरने वाली सड़क की कुल लंबाई 554.08 कि0मी0 है ।

सिर्फ पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत 12.3046 एकड़ लगभग 12 एकड़ भूअर्जन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । शेष जिलों में भूअर्जन पूर्ण कर लिया गया है। कुछ स्थानों पर अतिक्रमित भूमि को जिला प्रशासन के सहयोग से खाली कराकर कार्य कराया जा रहा है ।

भूअर्जन में हुए विलम्ब का मुख्य कारण पुराने भूअर्जन कानून से की जा रही भूअर्जन प्रक्रिया के दौरान वर्ष 2013 में नये भूअर्जन कानून का लागू होना है, जिसके कारण पूर्व में समर्पित भूअर्जन प्रस्ताव को नये सिरे से प्रारंभ किया गया । गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा परियोजना हेतु दिसम्बर, 2024 तक की समयवृद्धि दी गयी है ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब आया है और उन्होंने कहा है कि सिर्फ पूर्वी चम्पारण में 12 एकड़ जमीन का अधिग्रहण बाकी है । मैं उसमें करेक्शन करना चाहती हूँ कि 541 एकड़ मैंने क्वेश्चन में कहा था उसमें से लगभग ढाई सौ एकड़ जमीन अधिग्रहण हो गया 300 एकड़ लगभग अभी भी बाकी है और सिर्फ पूर्वी चम्पारण नहीं अररिया बेतिया सहित पूर्वी चम्पारण में बाकी है । मैं जानना चाहती हूँ ये जो गलत जवाब आया है उसकी माननीय मंत्री जी जॉच करवायेंगे और कब तक बाकी जमीन का अधिग्रहण करवा लेंगे ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये भूमि अधिग्रहण में विलंब का औचित्य पूछ रही हैं और जवाब स्पष्ट है कि भूअर्जन में हुए विलंब का मुख्य कारण पुराने भूअर्जन कानून से की जा रही भूअर्जन की प्रक्रिया के दौरान वर्ष 2013 में नये भूअर्जन कानून का लागू होना है जिसके कारण पूर्व में समर्पित भूअर्जन प्रस्ताव को नये सिरे से प्रारंभ किया गया । गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परियोजना हेतु दिसम्बर, 2024 तक की समय वृद्धि दी गयी है ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय मंत्री महोदय से मेरा सवाल दूसरा था, चूंकि उन्होंने भूअर्जन की बात की है 2013 से 2024 आ गया 11 साल में अगर नियम बदला भी है 2013 में तो सरकार को 11 साल क्यों लग रहे हैं नये भूमि अर्जन नीति के तहत भूअर्जन करने में किसानों से ये मेरी समझ से बाहर है । क्या माननीय मंत्री जी इसपर प्रकाश डालना चाहेंगे ?

श्री विजय कुमार सिन्हा,उप मुख्यमंत्री : बताया गया कि जब नीतिगत फैसला होता है और बदलता है कानून और प्रक्रिया उसमें समय लगता है ।

अध्यक्ष : कई बार लोगों ने जिनकी जमीन गयी पुराने रेट पर उनके अधिग्रहण का नोटिस हो गया, नया नियम लागू हो गया तो नया रेट मांगते हैं इस कारण से बहुत सारे मुकदमे हो गये कोर्ट में, ये सब कारण हो सकता है ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : मेरा अंतिम पूरक है इसमें जब प्राक्कलन की राशि हर साल बढ़ायी जाती है कंट्रेक्टर के लिए डिले होता है प्रोजेक्ट में तो किसानों के लिए भी मुआवजा की राशि क्यों नहीं बढ़ायी जाती है सरकार के द्वारा ? 11 साल का डिले काफी होता है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि इसपर भी विचार करना चाहेंगे ताकि किसानों को समुचित मुआवजा अभी के रेट पर मिले जैसे कंट्रेक्टर को प्राक्कलन की राशि अभी के रेट पर मिलती है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा,उप मुख्यमंत्री : माननीय सदस्या की चिंता उचित है विभाग में इसकी समीक्षा करके वे अलग से डिटेल में लिखकर दे देंगी हम समीक्षा करके उनको अवगत करायेंगे ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0-419(श्री बागी कुमार वर्मा)क्षेत्र सं0-215,कुर्था

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-420(श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी)क्षेत्र सं0-200,बक्सर

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-421(श्रीमती कविता देवी)क्षेत्र सं0-69,कोढ़ा

अध्यक्ष : पूरक पूछिए कविता जी ।

श्रीमती कविता देवी : अध्यक्ष जी, इसका उत्तर नहीं आया है हमें नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग इनका उत्तर पढ़ दीजिए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : पी0डब्लू0डी0 को ट्रांसफर कर दिया गया है ।

अध्यक्ष : ट्रांसफर हो गया पी0डब्लू0डी0 में, अगली तिथि को आयेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-422(श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता)क्षेत्र सं0-20,चिरैया

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन लोहा पुल पताही प्रखंड के बेलाहीराम ग्राम पंचायत के मिर्जा पेट्रोल पंप से बेलाही राम को जोड़ने वाली सड़क जो एम0एम0जी0एस0वाइ0 अन्तर्गत कालुपाकड़ से बेलाही कुशवाहा टोला पथ के नाम से निर्मित है, के प्रथम कि0मी0 में अवस्थित है । उक्त पुल की लंबाई 25 मीटर तथा चौड़ाई 3.30 मीटर है । वर्तमान में पुल की स्थिति अच्छी है तथा वाहनों का आवागमन चालू है । निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर उक्त लोहा पुल के स्थान पर उच्च स्तरीय आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए लाल बाबू जी ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : उत्तर मिला है सर, लेकिन सरकार की जो पौलिसी है जो आया है अपने रूम में बैठे-बैठे लोग रिपोर्ट कर देता है और वह पुल गिरने के कगार पर है और बाढ़ इलाका है बेलाहीराम पंचायत में वही एक रास्ता है और बाढ़ आने के बाद कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि उस गांव में आदमी जाय और हर साल बाढ़ आती है तो लोहिया पुल की सरकार की भी है कि लोहिया पुल को बदलना है तो हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इस पुल को बनवाने की कृपा की जाय जो लोगों को आनेजाने में सुविधा हो ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : इसको देखवा लेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय विधायक अपने क्षेत्र से आते हैं उनको ज्यादा अनुभव होता है कि किसकी क्या स्थिति है सड़क और पुल की, तो उनके जो विचार अभी आये हैं उसके आलोक में कृपया समीक्षा करा लेंगे ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : निश्चित रूप से आपका निदेश है तो हम देखवा लेंगे ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : मंत्री जी को धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0-423(श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह)क्षेत्र सं0-1,वाल्मीकिनगर

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल के एक तरफ अवस्थित बसावट सिसवाा एवं पिपरहवा रूपहि को पी0एम0जी0एस0वाइ0 पथ बरवा खास से पीपरहवा रूपहि से सम्पर्कता प्राप्त है एवं दूसरे तरफ उत्तर प्रदेश की सीमा है । पुल स्थल के अप स्ट्रीम में 6 कि0मी0 पर एवं डाउन स्ट्रीम में 5 कि0मी0 पर पुल निर्मित है । इस प्रकार बिहार क्षेत्राधीन बसावटों को एकल सम्पर्कता प्राप्त है । अतः पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह : अध्यक्ष जी के माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि इसमें जो उत्तर दिया गया है कि एक तरफ 6 कि0मी0 और दूसरे तरफ से 5 कि0मी0 पर मुझे लगता है कि ये उत्तर गलत है और यह पुल अति आवश्यक है । इसमें दिया गया है कि बिलकुल विचाराधीन नहीं है ये पुल हमारे क्षेत्र के लिए अति आवश्यक है। अतः मंत्री जी से आग्रह है कि अगर एक बार इसको सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए देखवा लें तो हमारे क्षेत्र की जनता की भलाई हो जायेगी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : माननीय सदस्य से अनुरोध है कि एक डिटेल हमको लिखकर दे दें।

अध्यक्ष : आप एक डिटेल लिखकर दे दीजिए उसको माननीय मंत्री जी देखवा लेंगे ।

श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह : धन्यवाद सर ।

तारांकित प्रश्न सं0-424(श्री संजय सरावगी)क्षेत्र सं0-83,दरभंगा

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा,उप मुख्यमंत्री : 1- अस्वीकारात्मक है ।

2- अस्वीकारात्मक है ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2023 में निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार पटना की ओर से 83 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की मान्यता रद्द करने के लिए केन्द्र सरकार को किसी भी प्रकार की अनुशंसा नहीं भेजी गयी है । विभागीय जॉच दल द्वारा अनुशंसित प्रतिवेदन डी0जी0टी0 भारत सरकार को भेजी जाती है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है, लेकिन खंड-3 में जवाब मिला है कि भारत सरकार को 83 आइ0टी0आइ0 की मान्यता रद्द करने के लिए भेजा नहीं गया है । मेरा क्वेश्चन ये है कि भेजने का निर्णय किया गया, लेकिन भेजा नहीं गया और यह है कि प्रत्येक वर्ष जो विभागीय जॉच दल जाता है क्षेत्र भ्रमण करने तो उसको शिक्षक, भवन, लैब नहीं मिलता है तो क्या विभागीय जॉच दल जो रिपोर्ट देता है सरकार को क्या इसकी समीक्षा सरकार करेगी । ये क्या हालत है निजी आइ0टी0आइ0 हमलोग देखते हैं न शिक्षक है, न लैब है, न भवन है, लेकिन सर्टिफिकेट बांटने का एक सेंटर बन गया है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा,उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं उनकी चिंता के अनुरूप विभाग में समीक्षा होते रहती हैं, जॉच के लिए भी पहले से निदेशित किया गया है, हर वर्ष जॉच होती है और जो आइ0टी0आइ0 जमीन पर नहीं है या उसमें जो आपकी चिंता है उसके अनुरूप व्यवस्था नहीं है उसकी भी समीक्षा होती है और उसको फिर रिपोर्ट भारत सरकार डी0जी0पी0 को भी भेजा जाता है और इस तरह के कार्य का उसकी समीक्षा कर ली जायेगी । उसपर बहुत सारे विगत के कालखण्डों में विगत वर्षों में जो मशीनरी की खरीद हुई है और उसमें अगर किसी तरह की धांधली है, प्रोब्लम है तो विभाग को हमलोग निदेशित कर चुके हैं कि इसकी जॉच करके तीन दिन के अंदर रिपोर्ट देने के लिए और इसकी जॉच भी करायी जा रही है ।

श्री संजय सरावगी : 83 आइ0टी0आइ0 जो निजी है जिसका हमने प्रश्न किया है । इसके बारे में माननीय मंत्री जी कुछ बतायें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा,उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने बताया कि जो भी है उसकी समीक्षा करके तीन दिन के अंदर हमलोग रिपोर्ट मांगे हैं और आपको अवगत करा दिया जायेगा ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन में आ गये।)

<u>तारांकित प्रश्न सं0-425(श्री मुरारी मोहन झा)क्षेत्र सं0-86,केवटी</u>

अध्यक्ष : पूरक पूछिए मुरारी जी ।

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, हमको इसका उत्तर नहीं मिला है ।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : महोदय, इसमें तो हमने कह दिया है कि दो महीने में हम रिपोर्ट मंगाकर आगे की कार्रवाई करेंगे ।

अध्यक्ष : हो गया, दो महीने में करेंगे ।

श्री मुरारी मोहन झा : इसपर जरा विशेष ध्यान रखियेगा मंत्री महोदय यह बहुत जरूरी है ।

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो उन्हें सदन पटल पर रख दिये जाएं । अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

टर्न-7/पुलकित/21.02.2024

श्री प्रहलाद यादव : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : पहले कार्य-स्थगन प्रस्ताव पढ़ लेते हैं उसके बाद आप पढ़ियेगा ।

श्री प्रहलाद यादव : महोदय, लखीसराय जिला के....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुनिये । कार्य-स्थगन प्रस्ताव हम पढ़ लेते हैं उसके बाद आप पढ़ लीजियेगा ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, उनकी बात वहां भी नहीं सुनी जा रही है....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 21 फरवरी, 2024 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ।

श्री भूदेव चौधरी, श्री सत्यदेव राम, श्री महबूब आलम, श्री मुकेश कुमार रौशन, श्री चन्द्र शेखर, श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन और दूसरा श्री अजीत शर्मा ।

आज सदन में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद, मतदान एवं सरकार के उत्तर का कार्यक्रम निर्धारित है ।

अतः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-172(3) एवं नियम-47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य श्री रणविजय साहू ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, यह सदन की गरिमा की बात है...

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

(व्यवधान)

श्री प्रहलाद यादव : अध्यक्ष महोदय, लखीसराय जिला के झुरौना गांव के नजदीक 21.02.2024 को 01:00 बजे रात्रि में एक टेम्पो से कैटरिंग का कार्य सम्पन्न करके अपने घर मुंगेर जिले के छोटी केशोपुर जमालपुर जा रहा था ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : कल तो हो गया था, अब क्या है ? कल तो बात समाप्त हो गयी, कल पूरा विमर्श हो गया । बार-बार एक ही विषय क्यों उठा रहे हों ।

श्री प्रहलाद यादव : टेम्पो चालक लखीसराय जिला के विधान सभा क्षेत्र के महटौना गांव का रहने वाला था। एकाएक हाईवा के द्वारा टेम्पो में धक्का मारने से छोटी केशोपुर जमालपुर, मुंगेर के आठ व्यक्ति एवं महटौना के एक व्यक्ति, मतलब नौ व्यक्ति स्पॉट पर मर गये ।

अध्यक्ष : कल का विषय समाप्त हो गया, इसी विषय को बार-बार बोलने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री प्रहलाद यादव : पांच व्यक्ति पी0एम0सी0एच0 में भर्ती है । मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो पी0एम0सी0एच0 में पांच व्यक्ति भर्ती है उसका सरकारी खर्चा पर इलाज हो और इन्हें मुआवजा सरकार शीघ्र दें ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बार-बार वेल में आयेंगे तो किसी का भी बोलना संभव नहीं है ।

शून्यकाल

माननीय सदस्य श्री रणविजय साहू ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री मोहम्मद अंजार नईमी ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री अजय कुमार ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री उमाकांत सिंह ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : कोई भी बात वेल में आकर के आप लोग नहीं कह सकते हैं इसलिए अपने-अपने स्थान पर जाइये ।

श्री उमाकांत सिंह : अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी चम्पारण जिला अंतर्गत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की जमीन बेतिया राज की महारानी जानकी कुंवर द्वारा दान में दी गयी थी । मैं सरकार से जी0एम0सी0एच0 का नाम बदलकर पुनः महारानी जानकी कुंवर कॉलेज एवं अस्पताल करने की मांग करता हूँ ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : पहले अपने-अपने स्थान पर जाइये । वेल में कही गयी कोई भी बात प्रोसीडिंग में नहीं जायेगी । अपने-अपने स्थान पर जाइये ।

माननीय सदस्या श्रीमती मंजु अग्रवाल ।

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री रामचन्द्र प्रसाद । रामचन्द्र जी, अपना शून्यकाल पढ़िये ।

(व्यवधान जारी)

वेल में कही गयी कोई भी बात प्रोसीडिंग में नहीं जायेगी । अपने-अपने स्थान पर जाइये, यह तरीका सही नहीं है ।

श्री रामचन्द्र प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड अंतर्गत 17.10.2023 को जहरीली शराब पीने से तीन लोगों की मृत्यु हो गयी, जिसका हायाघाट थाना कांड सं0-163/23 दर्ज है ।

अतः मैं सरकार से दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई एवं मृतक परिवार को मुआवजा देने की मांग करता हूँ ।

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला अंतर्गत सिंघवाड़ा प्रखंड अंतर्गत टेकटार रेलवे गुमती निकासी दास चौक तक वाली सड़क की स्थिति अत्यंत जर्जर हो चुकी है, जिस वजह से हजारों लोगों के आवागमन में काफी कठिनाई होती है ।

सरकार से जल्द से जल्द इस सड़क के निर्माण करने की मांग करता हूँ ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत नगर पंचायत मेहसी में भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-2505/04.07.2023 एवं जिलाधिकारी पूर्वी चम्पारण के पत्रांक-507/25.07.2023 के जांच का आदेश 8 महीना से लंबित है, सरकार से मांग करता हूँ कि लंबित पत्रांक की जांच करायी जाए ।

श्री राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा-1 प्रखण्ड में त्रिवेणी नहर, जुड़ा चौका पी0डब्लू0डी0 रोड से भैरोगंज बाजार जाने वाली सड़क में हरहा नदी पर पुल बनवाने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री महानंद सिंह ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री अजीत कुमार सिंह ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री विजय सिंह ।

श्री विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत बरारी प्रखण्ड के काढागोला घाट से पिरपैती तक गंगा में पुल नहीं रहने के कारण दो जिलों के लोगों को 130 कि0मी0 दूरी तय कर कहलगाँव एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर जाना पड़ता है ।

उक्त स्थानों के बीच गंगा-नदी पर पुल निर्माण कराने की सूचना देता हूँ।

श्रीमती ज्योति देवी : अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत प्रखण्ड मुख्यालय बाराचट्टी से बुमुआर एवं बुमुआर से ग्राम- लाडू (प्रखण्ड-मोहनपुर) तक की सड़क पूर्णतः गड्ढों में तब्दील हो चुकी है ।

अतएव अत्यंत लोकहित में उक्त सड़क का निर्माण शीघ्र करवाने की मांग सरकार से करती हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री इजहारूल हुसैन ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री विनय कुमार ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री अख्तरूल ईमान ।

श्री अख्तरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, कनकई नदी के ननदनिया मरिया, सिमलबाड़ी घाट, दास नदी के रहट बलिया, भागताहीर घाट एवं परमान नदी के बलुआ, गोटफोर खुटिया और सोती टोला माथोरापुर घाट पर पुल का निर्माण नहीं होने से काफी कठिनाई होती है ।

उपरोक्त सभी घाटों पर पुल निर्माण हेतु सरकार से मांग करता हूँ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : सदन अव्यवस्थित है आपके कारण, अपनी-अपनी सीट पर जाकर बैठिये । वेल में कही गयी कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जायेगी ।

श्री विद्या सागर केशरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज विधान सभा क्षेत्र में निर्माणाधीन अररिया-गलगलिया रेल लाईन के प्रस्तावित खवासपुर रेलवे स्टेशन से फारबिसगंज जं0 को जोड़ने के लिए नई रेल सम्पर्क लाईन का निर्माण हेतु रेल लिंक का सर्वेक्षण कराकर निर्माण कराने की केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की मांग सदन से करता हूँ ।

सुश्री श्रेयसी सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जमुई विधानसभा के दाबिल पंचायत में बरनर नदी किनारे बसे कहरडीह-चांगोडीह गांवों के राजस्व क्षेत्र का नदी से कटाव होता है, जिससे जनमाल की क्षति होने के आलोक में मैं कहरडीह रानीबांध से रामसजीवन बगीचा होकर पिपरी बगीचा से चांगोडीह खेल मैदान तक कच्ची बांध निर्माण की मांग करती हूँ ।

श्री कुंदन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिलान्तर्गत वीरपुर प्रखण्ड के मखवा से गोपालपुर टोला के बीच बैती नदी पर एवं पर्रा पंचायत के सरौंजा ग्राम में कुरनमा नदी पर पुल का निर्माण कराने हेतु, मैं सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री ललन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, एन0एच0-80, फोरलेन सड़क और एन0एच0-113 का जंक्शन प्वाईंट भागलपुर का पीरपैंती है जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है । जिला मुख्यालय से सुदूर एवं संभावित दुर्घटनाओं के मद्देनजर पीरपैंती में ट्रामा सेंटर युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनवाने की सरकार से मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राम रतन सिंह ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री अचमित ऋषिदेव ।

श्री अचमित ऋषिदेव : माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखण्ड के ग्राम पंचायत बगुलाहा वार्ड नं0-01 कर्पूरी ऋषि महादलित टोला में अबतक नल से जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं की गयी है ।

अत: उक्त महादलित टोला में जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग मैं सरकार से करता हूँ ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप लोग कार्य-संचालन नियमावली को पूरा जानते हैं, पुराने सदस्य हैं तब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ? जो लोग पहली बार सदन में जीतकर आये हैं उनका तो समझ में आता है लेकिन आपलोगों की बात समझ में नहीं आती ।

आप अपना शून्यकाल पढ़िये ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया प्रखण्ड के माहें पंचायत स्थित करेह नदी (बागमती नदी) पर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करवाने की मांग करता हूँ ।

श्री जयप्रकाश यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत नरपतगंज प्रखण्ड में भारत नेपाल सीमावर्ती सड़क घुरना से जयनगर खजूरी धनेशरी होकर सहरसा-मधेपुरा एन0एच0-107 को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क जिसकी लंबाई 90 किलोमीटर है को पथ निर्माण द्वारा अधिकृत कर पुनर्निर्माण करवाने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती नीतु कुमारी ।

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री रामबली सिंह यादव । रामबली बाबू अपने स्थान पर जाइये और अपनी शून्यकाल की सूचना को पढ़िये ।

(माननीय सदस्या द्वारा सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री महबूब आलम । महबूब साहब अपनी सूचना को पढ़िये ।

(माननीय सदस्या द्वारा सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री प्रणव कुमार ।

(व्यवधान जारी)

आप लोग यहां खड़े होकर अपनी ही पार्टी के माननीय सदस्यों को बोलने से वंचित कर रहे हैं । आप लोग कम से कम अपने नेता लोगों का ध्यान रखिये । जिस विषय पर कल पर्याप्त चर्चा हो गयी, सारी बात साफ हो गयी, दोबारा वही

विषय उठाने का कोई औचित्य नहीं है । इसलिए सदन का समय बर्बाद मत कीजिए । आप सदन की कार्यवाही में भाग लीजिए और अपने-अपने विषय को रखिये । अपने-अपने स्थान पर जाकर बैठिये ।

माननीय सदस्य अपनी सूचना को पढ़िये ।

टर्न-8/अभिनीत/21.02.2024

(व्यवधान जारी)

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, मुंगेर-मिर्जा चौकी फोरलेन अंतर्गत पिलर सं0-90/040 तथा 90/090 के बीच बनी पुलिया की ऊंचाई कम होने के कारण किसानों की फसल ट्रैक्टर से पार नहीं हो सकेगा ।

अत: सदन के माध्यम से सरकार से उक्त पुलिया की ऊँचाई बढ़ाने की मांग करता हूं ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में मध्याह्न भोजन बनाने हेतु रसोईया कार्यरत हैं । उनका मानदेय दैनिक मजदूरी से कम होने के कारण आर्थिक स्थिति दयनीय है । सरकार से मांग करता हूं कि रसोईया को न्यूनतम मजदूरी के आधार पर 10 हजार रुपये मासिक भुगतान की जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय..

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कार्य संचालन नियमावली के अनुसार सदन चलेगा । वेल में कही गयी कोई बात प्रोसीडिंग्स में नहीं जायेगी । पहले आप अपने स्थान पर जाइये ।

माननीय सदस्य खेमका जी, बोलिए ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पूर्णियां चुनापुर सैन्य हवाई अड्डा में स्वीकृत एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण तथा हवाई अड्डा से पक्की सड़क का निर्माण कार्य एवं 15 एकड़ अतिरिक्त जमीन का अधिग्रहण शीघ्र कर एयरपोर्ट अथॉरिटी को देने की मांग सरकार से सदन में करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती प्रतिमा कुमारी ।

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम ।

(माननीय सदस्य द्वारा सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री अमरजीत कुशवाहा ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री संदीप सौरभ ।

(माननीय सदस्य द्वारा सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री विनय बिहारी ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, भोजपुरी के दो ऐतिहासिक कलाकार पुरूबिया उस्ताद कहे जाने वाले अमर शहीद महेन्द्र मिश्र व विदेशिया के जनक भिखारी ठाकुर को पद्म श्री सम्मान से सम्मानित करने हेतु आग्रह करता हूं कि सदन भारत सरकार से इसके लिए पहल करे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती विभा देवी ।

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद ।

(माननीय सदस्य द्वारा सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्या श्रीमती रश्मि वर्मा ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : महोदय, बेतिया जिलांतर्गत नरकटियागंज नगर परिषद में एक नशामुक्ति एवं पुनर्वासन केंद्र की अति आवश्यकता है ।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से स्थानीय युवाओं के हित में एक नशामुक्ति एवं पुनर्वासन केंद्र शीघ्र खोलने की मांग करती हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री कुमार शैलेन्द्र ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री पवन कुमार यादव ।

(व्यवधान जारी)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री पवन कुमार यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलांतर्गत सन्हौला स्थित वारी आदर्श उच्च विद्यालय में 2010 से बनाये जा रहे दो मंजिला भवन सहित उसके बगल में भी कुछ वर्ष पूर्व बनाये जा रहे भवन का निर्माण अधूरा है ।

दोनों अर्द्धनिर्मित भवन के निर्माण को पूरा कराने की सरकार से मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं लिये जायेंगे ।

माननीय सदस्य श्री राम सिंह अपनी सूचना को पढ़ें ।

<u>ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उसपर सरकारी वक्तव्य</u>

श्री राम सिंह, श्री अनिल कुमार एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (गन्ना उद्योग विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री राम सिंह : महोदय, ''बिहार राज्य में गन्ना उत्पादक किसानों को उत्तम किस्म के गन्ना का 355/- रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य सरकार द्वारा दिया जाता है, जबकि भारत के अन्य राज्यों जैसे हरियाणा में 400/- रुपये प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य किसानों को प्रदान किया जाता है ।

अतएव बिहार के गरीब एवं असहाय गन्ना उत्पादक किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में बिहार राज्य में 9 चीनी मिलें कार्यरत हैं जिसमें से 7 निजी क्षेत्र एवं 2 एच0पी0सी0एल0 बायो फ्यूल्स लिमिटेड भारत सरकार के उपक्रम की ईकाई है । हरियाणा राज्य में अधिकांश सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलें कार्यरत हैं । हरियाणा राज्य सरकार द्वारा चालू पेराई सत्र में 2023-24 अंतर्गत उत्तम प्रभेद के गन्ना मूल्य की दर 386 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गयी है । बिहार राज्य में गन्ना मूल्य का निर्धारण पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में घोषित ईख मूल्य की दर गन्ने की पेराई के पश्चात प्राप्त रिकवरी प्रतिशत एवं गन्ना के प्रभेद की मात्रा आदि बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है । चूंकि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की जलवायु वातावरण में मिट्टी की गुणवत्ता लगभग समान है । पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का रिकवरी प्रतिशत बिहार राज्य के रिकवरी दर से लगभग 0.75 प्रतिशत अधिक रहता है । रिकवरी की दर में एक प्रतिशत का अंतर का मतलब है कि गन्ना मूल्य की दर में लगभग 35 रुपये का अंतर होगा ।

राज्य में पिछले तीन वर्षों का चीनी मिलों का औसत रिकवरी दर 10. 53 प्रतिशत रहा है जबकि उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों का चीनी का औसत रिकवरी दर 11.44 प्रतिशत है । चालू पेराई सत्र 2023-24 अंतर्गत गन्ना कृषकों एवं चीनी मिलों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा उत्तम प्रभेद के गन्ना पर 20 रुपये प्रति क्विंटल, सामान्य प्रभेद के गन्ना पर 20 रुपये प्रति क्विंटल एवं विभिन्न प्रभेदों के गन्ना पर 15 रुपये क्विंटल की दर से बढ़ोत्तरी की गयी है । पेराई सत्र 2023-24 अंतर्गत राज्य में ईख मूल्य की दर निम्नवत है:-

1. उत्तम प्रभेद :- 2022-23 में 335 रुपये प्रति क्विंटल और चालू पेराई वर्ष 2023-24 में दर 355 रुपये प्रति क्विंटल ।
2. सामान्य प्रभेद :- 2022-23 की जो दर है 315 रुपये क्विंटल है, अब बढ़कर 335 रुपये क्विंटल हो गया है ।
3. विभिन्न प्रभेद :- गत वर्ष 2022-23 में जो दर थी 285 रुपये क्विंटल अब 300 रुपये क्विंटल कर दी गयी है ।

महोदय, इस प्रकार से राज्य में गन्ना किसानों के हित के लिए राज्य सरकार ने बढ़ोत्तरी की है । मैं समझता हूं कि आगे गन्ना किसान और अच्छे से बेहतर काम करें और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो इसके लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है ।

श्री राम सिंह : महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि खासकर जो उत्तर प्रदेश से तुलना की गयी है, उत्तर प्रदेश और बिहार का एक मैप बताता है कि हम उत्तर प्रदेश से हैं और एक गन्ने के खेत का मैप बताता है कि मैं बिहार का हूं । क्या इस तरह का भेदभाव, भारत के अनेकों राज्यों में यह स्थिति है कि कहीं 400 और कहीं 375, आपने 2005 में माननीय मुख्यमंत्रीजी परिवर्तन यात्रा में गये थे तो मैं उस समय अध्यक्षता कर रहा था, उन्होंने कहा था कि सरकार बनाओ मैं ऐसा रेट दूंगा बिहार को कि उत्तर प्रदेश वाले कहेंगे कि बिहार की भांति हो लेकिन वह नहीं हुआ । हमेशा 35 रुपये, 25 रुपये कम मिलता रहा । ऐसा कबतक चलता रहेगा ? जबकि उत्तर प्रदेश में डीजल का दाम भी कम है, वहां खेती करने की लागत भी कम है, सिंचाई की सुविधा भी अच्छी है, हमारे यहां सिंचाई की सुविधा भी अच्छी नहीं है और डीजल का दाम भी ज्यादा है । हमारे यहां लागत खर्च अधिक लगने के बाद भी हमारे साथ, किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

टर्न-9/हेमन्त/21.02.2024

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है, सरकार उसको धीरे-धीरे करके दूर कर रही है और माननीय सदस्य कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के किसानों को ज्यादा सुविधा मिल रही है । माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लागू है और कृषि रोड मैप के माध्यम से किसानों को अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं । मशीन खरीदने में, खाद में, बीज में तरह-तरह की उनको सुविधाएं बढ़ायी जा रही हैं और यहां के किसानों की

हालत दिनोंदिन बेहतर होती जा रही है और बेहतर इतनी हुई है कि बिहार के किसानों ने चावल उत्पादन में भारत ही नहीं विदेशों को भी मात दी है । तो हमारे किसान आगे बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं यह अच्छी बात है । माननीय सदस्य की और भी जो चिंता होगी, आगे सरकार देखेगी ।

अध्यक्ष : श्री उमाकांत जी ।

(व्यवधान)

माननीय विनय बिहारी जी, आपका नाम नहीं है इसमें । आप नहीं बोलिये । माननीय सदस्य श्री उमाकांत जी ।

श्री उमाकांत सिंह : माननीय महोदय से कहना है कि पूरे बिहार में जितने चीनी मिल हैं उसका आधा से ज्यादा भाग पश्चिमी चम्पारण में है और पश्चिमी चम्पारण गन्ना पर, खेती पर ही निर्भर है । दोनों अगल-बगल, यू0पी0 से पश्चिमी चम्पारण सटा हुआ है । अब हमारी सरकार केंद्र में भी है और यहां भी है । अब हम लोग क्या जनता के बीच में जवाब देंगे ? जनता जब पूछती है, किसान पूछते हैं कि यू0पी0 में क्यों इतना रेट है और चम्पारण में क्यों इतना रेट है और उत्तर बिहार के बड़े-बड़े मिल चम्पारण में हैं । वहां के किसान गन्ना पर ही निर्भर हैं, दूसरी कोई फसल नहीं है । सुखाड़ की मार आती है, बाढ़ की मार आती है और दूसरा, गन्ना का रेट हम लोगों का यू0पी0 से बहुत कम रहता है । माननीय महोदय के द्वारा हम ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं माननीय मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का कि इस पर बैठकर जल्द ही, किसान का मामला है और चुनाव सामने है । अब हम क्या बहाना बनायेंगे कि केंद्र में और राज्य में दोनों जगह अलग-अलग सरकार है, दोनों सरकार आपकी है । इसलिए आग्रह करता हूं अध्यक्ष जी से कि माननीय मंत्री जी द्वारा इस पर विचार किया जाय और तुरंत ही इसका निष्पादन किया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के ध्यानाकर्षण के उत्तर में मैंने स्पष्ट बताया है और माननीय सदस्य की चिंता के बारे में आगे समीक्षा करेंगे और समीक्षा करके कार्रवाई करेंगे ।

श्री उमाकांत सिंह : बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी को ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपनी ध्यानाकर्षण सूचना को पढ़ें ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-10/धिरेन्द्र/21.02.2024

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 21 फरवरी, 2024 के पूर्वाह्न से श्री महेश्वर हजारी, उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने उपाध्यक्ष पद का त्याग कर दिया है । उपाध्यक्ष पद से त्याग की स्थिति में बिहार विधान सभा में उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-10(1) के तहत उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो अध्यक्ष नियत करें तथा सचिव हर सदस्य को उस तिथि की सूचना भेजेंगे । इस नियम के आलोक में उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा के निर्वाचन के लिए दिनांक 23 फरवरी, 2024 की तिथि निर्धारित की जाती है । उपाध्यक्ष पद के नामांकन की कार्रवाई कल दिनांक 22 फरवरी, 2024 को होगी । उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन की सूचना सचिव सभी माननीय सदस्यों को भेज देंगे ।

अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, सहकारिता विभाग के अनुदान की मांग पर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है, इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा :-

राष्ट्रीय जनता दल	-	59 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	-	58 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	-	33 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	-	14 मिनट
सी॰पी॰आई॰ (एम॰एल॰)	-	08 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	-	03 मिनट
सी॰पी॰आई॰(एम॰)	-	02 मिनट

सी॰पी॰आई॰	-	02 मिनट
ए॰आई॰एम॰आई॰एम॰	-	01 मिनट

कुल	-	180 मिनट

माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''सहकारिता विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 1209,36,44,000/- (एक हजार दो सौ नौ करोड़ छत्तीस लाख चौवालीस हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण श्री राजेश कुमार, श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, श्री अजीत शर्मा एवं श्री अजय कुमार सिंह से सहकारिता विभाग के संपूर्ण माँग पर प्रत्येक कटौती प्रस्ताव एवं माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा से अनुदान माँग के मद को मितव्ययिता के आधार पर घटाने का कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । ये सभी व्यापक हैं, जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं । संपूर्ण माँग पर प्राप्त प्रत्येक कटौती प्रस्ताव में माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार का प्रस्ताव प्रथम है एवं अनुदान के मदों पर माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा का कटौती प्रस्ताव प्रथम है । बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-173(6) के प्रथम परंतुक के तहत मितव्ययिता के आधार पर दी गई कटौती प्रस्ताव को पूर्वता दी जाती है ।

अत: माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री अजीत शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''इस शीर्षक के मुख्य शीर्ष-2425, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-105, उप शीर्ष-0101 के लिए 2,00,00,000/- रुपये की माँग 1,00,00,000/- रुपये से घटाई जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिये किया है क्योंकि मैंने जो बजट को देखा है उसमें विसंगति लग रही है और लगता है कि अनावश्यक रूप से अधिक धनराशि का प्रावधान इस शीर्ष सहित कई शीर्षों में किया गया है । महोदय, 2021-22 में इस मद में जो वास्तविक खर्च है वह है 04 लाख 86 हजार 302 रुपये । 2022-23 में मूल बजट जो इस सदन से पारित कराया गया था वह 38

लाख का था जिसे पुनरीक्षित कर 28 लाख 50 हजार किया गया और उसमें से जो वास्तविक खर्च हुआ वह 06 लाख 19 हजार 500 रुपये है । 2023-24 में जहाँ इस मद में 45 लाख रुपये का प्रावधान था उसे बढ़ा कर 2024-25 में इसे बढ़ा कर 02 करोड़ कर दिया गया है । यह मद अन्य प्रशासनिक व्यय का है । 2022-23 में जो बजट प्रावधान के विरुद्ध खर्च हुआ है वह 25 प्रतिशत से भी कम है फिर उसे 45 लाख रुपये और फिर उसे बढ़ा कर अगले वित्तीय वर्ष में 02 करोड़ किये जाने का कोई औचित्य मुझे प्रतीत नहीं होता है । इसके साथ-साथ महोदय, एक बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक समझता हूँ । बिहार गरीब राज्य है और यहाँ उद्योग धंधे भी इतने नहीं हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का आय बढ़े । ऐसी स्थिति में प्रशासनिक व्यय यदि घटायी जा सके तो उससे बेहतर कोई उपाय नहीं है । अध्यक्ष महोदय, कहावत है कि-

''आज पैसे को बचा लो, कल पैसा तुम्हें बचा लेगा''

जब दुनिया में मंदी आयी उस वक्त भारत के लोगों की बचत की प्रवृत्ति ने ही भारतीय अर्थव्यवस्था को थामे रखा । इस तरह से प्रशासनिक व्यय को लगभग चार गुणा करना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है । इसके अतिरिक्त महोदय, एक बात और मैं सदन को बताना चाहता हूँ । बिहार विधान मंडल द्वारा पारित बजट को खर्च करने के लिये बजट मैनुअल बना हुआ है । उसमें प्रावधान है कि किस तरह से खर्च होगा और खर्च की कब-कब समीक्षा होगी लेकिन यह सब किताबी बातें रह जाती हैं और बिना खर्च किये राशि को मार्च के अंतिम सप्ताह में सरेंडर किया जाता है जिससे दूसरे विभाग जो वित्तीय संकट से जूझ रहे होते हैं उन्हें अपेक्षित धनराशि खर्च के लिये नहीं मिल पाती है और योजनाएं अधूरी रह जाती हैं । महोदय, इसीलिये अधिक धनराशि का प्रावधान बजट मैनुअल का भी उल्लंघन है । प्रशासनिक व्यय को जितना कम किया जायेगा इस राज्य की आर्थिक सेहत उतनी अच्छी होगी । अध्यक्ष महोदय, एक बिंदु की ओर और ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि सभी विभागों के बजट की समीक्षा करने के उपरांत ही वित्त विभाग द्वारा बजट तैयार किया जाता है । बजट को जो मैंने देखा है मुझे उससे लगता है कि वित्त विभाग रटी रटायी पद्धति पर चल रहा है और गहराई से समीक्षा नहीं करता है जिसके कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है । अध्यक्ष महोदय, मैंने जो यह प्रस्ताव दिया है यह तो एक प्रतीक है । बजट में इस तरह के दर्जनों शीर्ष हैं जिनमें समीक्षा कर कटौती की जा सकती है और उसे इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया जा सकता है । इस बार माँगों पर बहस चार ही दिन है इसलिए जो विवाद हेतु स्वीकृत मुख्य चारों शीर्ष हैं इन पर ही कुछ बातें हो सकती हैं । मैं तो केवल

इंगित कर रहा हूँ कि जो अनुत्पादक खर्च है उसे रोक कर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाए ताकि राज्य आगे बढ़ सके । अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अभी बीते दिनों जो घटनाक्रम हुआ है उसमें आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हम लोगों का साथ छोड़ कर भाजपा का दामन थाम लिया है । हर दल की अपनी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है कि वह किस दल के साथ अपना गठबंधन करे इस पर किसी को कोई आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए । मैं तो इसे सहजता से ही लेता हूँ लेकिन मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी से इस सदन के माध्यम से इतना ही कहूँगा कि पाला बदलने के बाद व्यक्तिगत दुश्मनी जैसा ट्रीटमेंट नहीं किया जाए क्योंकि कल का किसी को पता नहीं है कि कब कौन-सा गठबंधन बन जाय । अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो इस पर मैं एक शेर कहना चाहूँगा ।

अध्यक्ष : शेर ही कह रहे थे आप ।

श्री अजीत शर्मा : दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाईश रहे ।
जब कभी हम दोस्त हो जायं तो शर्मिन्दा न हों ।।

अध्यक्ष : लेकिन यह शेर केवल इधर ही लागू नहीं होता है, उधर भी लागू होता है ।

श्री अजीत शर्मा : बिल्कुल, सर । अध्यक्ष महोदय, जो आप सदन में देख रहे हैं, जो शिक्षकों के मामले की बात, ऐसे आज सहकारिता का है लेकिन उस पर हमलोगों को आज बोलने नहीं दिया गया । चूंकि वह मामला है बच्चों की शिक्षा के लिए भी और बिहार के विकास के लिए भी । उस पर हमलोगों को नहीं बोलने दिया गया । इस पर....

अध्यक्ष : मैं तो देख रहा था, आपका मैंने ध्यानाकर्षण स्वीकृत किया था लेकिन आपके सदस्यों ने आपको बोलने नहीं दिया । इसमें मेरा क्या दोष है ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, इसके लिए धन्यवाद ।

अध्यक्ष : आपके ही लोगों ने आपको बोलने नहीं दिया ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस पर जो मैंने बातें कही हैं, जो बजट के बारे में बढ़ाकर घटाने की बात और उससे दूसरे डिपार्टमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम रूकता है । इसलिए इन बातों पर ध्यान देना चाहिए । यह कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ । आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूँ ।

अध्यक्ष : डॉ॰ सुनील कुमार । आपका 14 मिनट समय है ।

डॉ॰ सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने एन॰डी॰ए॰ सरकार की उपलब्धियों के समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया । सहकारिता विभाग अंतर्गत किसानों की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की अधिप्राप्ति के साथ-साथ किसानों के हित में अनेक लाभकारी योजनाएँ लायी

गयी हैं । जैसे- कृषि रोड मैप, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयत्र योजना, बिहार राज्य फसल सहायता योजना, सहकारी वित्त ऋण योजना, पैक्सों के माध्यम से उर्वरक वितरण केन्द्र की स्थापना, एल॰पी॰जी॰ वितरण की स्थापना, कॉमन सेवा केन्द्र की स्थापना । इस तरह की योजनाएँ सरकार ने किसानों के हित में लायी है ।

(क्रमशः)

टर्न-11/संगीता/21.02.2024

डॉ0 सुनील कुमार (क्रमशः) : चूंकि मैं पेशे से डॉक्टर हूं इसीलिए मैं बिहार सरकार के द्वारा, एन0डी0ए0 सरकार के द्वारा 2005 के बाद जो बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता लायी गयी और जो विकास किया गया उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं । 2005 के पहले बिहार में सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज थे- पटना मेडिकल कॉलेज, नालंदा मेडिकल कॉलेज, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, भागलपुर मेडिकल कॉलेज, एस0के0 मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर, मगध मेडिकल कॉलेज, गया । जबसे एन0डी0ए0 की सरकार बनी, तबसे लगातार मेडिकल कॉलेजों में वृद्धि हुई । अभी 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं । उन मेडिकल कॉलेजों की बात मैं करूं और गिनती करूं तो अभी पी0एम0सी0एच0, एन0एम0सी0एच0, आई0जी0आई0एम0एस0, एम्स, एम्प्लाईज स्टेट इन्श्योरेंस कॉरपोरेशन मेडिकल कॉलेज, डी0एम0सी0एच0, एस0के0एम0सी0एच0 मुजफ्फरपुर, अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज, गया, जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर, भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस पावापुरी, जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया । अभी राज्य सरकार ने करीब-करीब 9 अन्य मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है जिसमें छपरा, वैशाली, मधुबनी, सीतामढ़ी, जमुई अन्य जगहों पर मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं । आप सभी को मालूम होगा कि देश का सबसे बड़ा अस्पताल पी0एम0सी0एच0 कम्पाउंड में एन0डी0ए0 की सरकार ने बनाने का फैसला लिया है जिसका करीब-करीब 5462 बेड का यह अस्पताल होगा। अध्यक्ष महोदय, हाल ही में 551 करोड़ की लागत से समस्तीपुर में श्रीराम जानकी चिकित्सा चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की गई है जिसका उद्घाटन किया गया है । एन0डी0ए0 सरकार की सोच के अंतर्गत...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप सुनील जी, बोलिए । इधर देखकर बोलते रहिए ।

(व्यवधान)

बैठे-बैठे मत बोलिए ।

डॉ0 सुनील कुमार : एन0डी0ए0 सरकार की एस0के0एम0सी0एच0 में टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट मुंबई से मिलकर भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है । पटना में लोक निजी भागीदारी से जय प्रभा मेदांता सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल की स्थापना की गई है, जिसमें करीब-करीब 25 परसेंट बेड बिहार के गरीब मरीजों के लिए आरक्षित है । अध्यक्ष महोदय, राज्य के करीब-करीब 145 स्वास्थ्य संस्थानों में नि:शुल्क डिजिटल एक्स-रे और एक्स-रे किए जा रहे रहे हैं । राज्य के करीब-करीब 90 चयनित अस्पतालों में फ्री में अल्ट्रासाउंड किए जा रहे हैं । राज्य के करीब-करीब 38 जिलों में डायलेसिस की सेवा उपलब्ध करायी गई है । ऑटो एनालाइजर के माध्यम से सरकारी सभी अस्पतालों में पैथोलॉजी की सुविधा प्रदान की गई है । ग्रामीण क्षेत्रों में भी संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 10 हजार 251 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्थापना की गई है । ग्रामीण इलाकों के लोगों को किसी भी स्थिति में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने करीब-करीब हजार से ज्यादा एम्बुलेंस की व्यवस्था की है । जब एन0डी0ए0 सरकार का गठन हुआ था वर्ष 2005 में, तो एन0डी0ए0 सरकार के गठन के तुरंत बाद यह फैसला ले लिया गया था कि गरीब मरीजों के असाध्य रोगों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष दिया जाय और उसके गठन के बाद लगातार गरीब मरीजों को कैंसर, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज के मामले में उनको सहायता दी गई । अध्यक्ष महोदय, विश्व के किसी राष्ट्राध्यक्ष ने, किसी प्रधानमंत्री ने अपने देश की जनता को वह ताकत नहीं दिया जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हिन्दुस्तान के गरीबों को ताकत दिया ''आयुष्मान कार्ड'' की ताकत । यह कार्ड आज बिहार के करीब-करीब 40 लाख 55 हजार परिवारों को वितरित किया जा चुका है । महोदय, इस कार्ड के जरिए बिहार और हिन्दुस्तान के गरीब अपने परिवार के सदस्यों का 5 लाख तक का इलाज देश के किसी भी कर्णांकित, सरकार के द्वारा कर्णांकित अस्पतालों में करा सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ने बिहार के और देश के...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाए रखिए ।

डॉ0 सुनील कुमार : आम जनों के औषधि का खर्च कम करने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का जो प्रयास किया और पूरे देश में इस तरह के जन औषधि केंद्र खोले गए, उससे आम जनों को मेडिसिन खरीदने में काफी लाभ हुआ है । मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसी योजना लायी, ''बाल हृदय योजना'', आप सभी लोग जानते हैं कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं,

जिनके हृदय में छेद होता है, जिसका इलाज करना पहले बिहार में संभव नहीं था इसीलिए 13 फरवरी, 2021 को प्रशांत मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन के साथ अहमदाबाद के साथ एम0ओ0यू0 साइन किया और हवाई जहाज से यहां से बच्चों को भेजा गया और उनका इलाज कराया गया । अब यह हृदय के छेद का इलाज इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, पी0एम0सी0एच0 के कम्पाउंड में भी होता है और आई0जी0आई0एम0एस0 में भी होता है । अभी तक 1,117 बच्चों के हृदय का ऑपरेशन हो चुका है । अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

आपको जानकारी होनी चाहिए...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सुनील जी, ये लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप यहां देखकर बात करिए । आप बोलते रहिए ।

(व्यवधान)

डॉ0 सुनील कुमार : सदस्यों को जानकारी होनी चाहिए कि लाखों में कभी-कभी एकाध बच्चों के हृदय में छेद रह जाता है । ये कम से कम जो मेडिकल के बारे में नहीं जानते हैं उनको यह जानकारी होना चाहिए ।

अध्यक्ष : ये डॉक्टरी नहीं न पढ़े हैं ।

डॉ0 सुनील कुमार : नि:शुल्क दवाओं की उपलब्धता की बात करें...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप सुनील जी इधर देखकर बोलिए न । आप क्यों उनके चक्कर में हैं । आप इधर देखकर बोलिए ।

डॉ0 सुनील कुमार : नि:शुल्क दवाओं की बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं 2005 के पहले...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया, शांति बनाए रखिए ।

डॉ0 सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, 2005 के पहले बिहार के अस्पतालों में मरीज नहीं जाया करते थे, कुत्तों का बसेरा हुआ करता था लेकिन हमारे एन0डी0ए0 सरकार के गठन के बाद मुझे याद है वह 24 नवंबर, 2005 का दिन, जिस दिन गांधी मैदान में एन0डी0ए0 सरकार का गठन हुआ था और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि मैं कभी विधायक बनूंगा, हमारे पिताजी ने तो हमें डॉक्टर बनाया था । मैं तो इस जंगलराज का गठबंधन जो था, उसी में मुझे रिजाइन करना पड़ा और वहां के लोगों ने फैसला लिया कि अब डॉक्टर सुनील को

इस बदलाव में भागीदार बनना है और मैं धन्य मानता हूं बिहारशरीफ की जनता को, मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्नेह, प्यार और आशीर्वाद दिया और संगठित समर्थन दिया और 2005 से लगातार मुझे वहां से विधायक चुना । साथियों, नि:शुल्क दवाओं की उपलब्धता की बात करूं तो पहले कोई अस्पताल में दवाई नहीं मिलती थी । हमलोगों ने शुरूआत किया, 47 दवाओं के वितरण से शुरूआत किया...

(व्यवधान)

310 तरह की दवाएं गरीब मरीजों को, जो अस्पताल में भर्ती होते हैं उनको दिया गया । पहली बार बिहार में सुदूरवर्ती लोगों के इलाज के लिए टेली कंसल्टेशन की सुविधा प्रदान की गई । विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बिहार के दूर-दराज के लोगों को टेली कंसल्टेशन के माध्यम से उनको स्वास्थ्य सेवा मुहैया करायी जा रही है ।

(क्रमश:)

टर्न-12/सुरज/21.02.2024

डॉ0 सुनील कुमार (क्रमश:) : सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाये गये, जिससे लगातार महिलाओं को फ्री में सेनेटरी पैड मुहैया कराया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, आज पूरे बिहार के 85 अस्पतालों में जीविका दीदी की रसोई चल रही है । साफ-सुथरा खाना उपलब्ध कराने की दिशा में जीविका दीदी की रसोई स्थापित की गयी है, जो काफी पॉपुलर हो रही है । अभी पटना के राजेन्द्र नगर में सुपर स्पेशलिटी नेत्र अस्पताल 106 बेड का खोला गया है, जो करीब-करीब 86 लाख की लागत से बनायी गयी है । बिहार सरकार ने, एन0डी0ए0 की सरकार ने बिहार नेत्र ज्योति अभियान के तहत करीब-करीब 03 लाख 69 हजार लोगों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया है । अभी आई0जी0आई0एम0एस0 में करीब-करीब 12 सौ बेड का 513 करोड़ की लागत से अस्पताल का भवन बनाया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एन0डी0ए0 की सरकार ने बदलाव किया है, वह पूरे देश में काबिले तारीफ है । 116 रक्त केंद्र खोले गये हैं और 71 रक्त संग्रह केंद्र की स्थापना भी की गयी है ताकि गरीब मरीजों को फ्री में ब्लड मुहैया करायी जा सके । बिहार राज्य के उत्कृष्ट सेवा मुहैया कराने की दिशा में अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार को कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं । जिस तरह 112 की स्थापना की गयी है...

अध्यक्ष : केवल एक मिनट आपके पास है, कंक्लूड करिये ।

डॉ0 सुनील कुमार : जिस तरह 112 की स्थापना की गयी है ताकि कहीं छोटी-मोटी घटनायें हों तो उसकी सूचना दी जा सके, उसी तरह हेल्थ डिपार्टमेंट के लिये सेंट्रल हेल्थ हैब सेंटर की स्थापना करने का सुझाव देता हूं ताकि बिहार के गरीब मरीज किसी बिचौलिये के चक्कर में न पड़कर सरकारी अस्पताल में ईलाज करा सकें । हर जिले में आयुष्मान कार्ड बेरोक-टोक ईलाज मुहैया कराने के लिये एक नोडल ऑफिसर की पोस्टिंग करने का सरकार से आग्रह करता हूं । यह भी आग्रह करता हूं कि माडर्नाइजैशन ऑफ फूड के बाद दो बीमारियां बहुत प्रचलित है एक तो डायबिटीज और एक हार्ट का रोग । इसलिये सरकार से आग्रह करूंगा कि जितने भी जिला अस्पताल हैं, वहां एक-एक डायबिटोलॉजिस्ट और एक डी0एम0 कार्डियोलॉजिस्ट की पोस्टिंग होनी चाहिये और अच्छे आई0सी0यू0 बनाने चाहिये ताकि अगर किसी को हार्ट अटैक हो तो पटना आने के पहले कम से कम उनका प्रारंभिक ईलाज किया जा सके...

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये ।

डॉ0 सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, दो चीजें और मैं कहना चाहता हूं । जिला अस्पताल में दो इक्यूपमेंट जरूर अवेलेबल होना चाहिये । एक बाइपाइप जिसको मिनी वेंटिलेटर कहते हैं क्योंकि वेंटिलेटर चलाना सबके बस की बात नहीं है इसलिये मिनी वेंटिलेटर सभी अस्पतालों में उपलब्ध रहना चाहिये और एक्सटर्नल पेसमेकर । कभी-कभी ऐसा देखा गया है कि...

अध्यक्ष : समाप्त करिये अब ।

डॉ0 सुनील कुमार : एक मिनट में महोदय । कभी-कभी ऐसा देखा गया है कि गांव-देहात में हार्ट ब्लॉक होता है तो उसकी जान जाने के अलावा कोई उपाय नहीं होता है । जब तक वह पटना आयेंगे पेसमेकर की बदली होगी, तब तक उनकी जान चली जायेगी इसलिये एक्सटर्नल पेसमेकर कम से कम जिला अस्पतालों में उपलब्ध हो । दूसरा, एक ऐज के बाद 45 के बाद, 50 के बाद हर लोगों को मोतियाबिंद होता है इसलिये मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि हर जिला अस्पताल में एक आई स्पेशलिस्ट निश्चित तौर पर बहाल हों...

अध्यक्ष : धन्यवाद, समाप्त करिये ।

डॉ0 सुनील कुमार : और एक आई के अच्छे अस्पताल बने रहें...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य भूदेव चौधरी ।

डॉ0 सुनील कुमार : महोदय, मैं आपको दो पंक्तियां कहना चाहता हूं, कृपया सुन लीजिये...

अध्यक्ष : सुन लीजिये भूदेव जी, दो पंक्ति कह रहे हैं ।

डॉ0 सुनील कुमार : एन0डी0ए0 की ताकत का अंदाजा हमारे जोर से नहीं बल्कि विरोधियों के शोर से पता चलता है...

श्री भूदेव चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय...

डॉ0 सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, विरोधियों को मैं कहना चाहता हूं...

अध्यक्ष : बैठ जाइये । 23 मिनट समय है आपका ।

श्री भूदेव चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जिस गरिमामयी पद पर आसीन हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बोलिये भूदेव जी ।

श्री भूदेव चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप जिस गरिमामयी पद पर विराजमान हैं, इसके लिये मैं आपको दिल से बधाई देता हूं और मुझको पुख्ता यकीन है कि इस सदन की गरिमा, मर्यादा को अक्षुण्ण रखने में आपकी अहम भूमिका होगी...

अध्यक्ष : आप तो हमारे पुराने मित्र हैं ।

श्री भूदेव चौधरी : मित्र नहीं, मैं आपका शिष्य रहा हूं सर और मैं अपने वरिष्ठ नेताओं के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सरकार द्वारा अनुदान मांगों की कटौती प्रस्ताव के समर्थन में मुझको बोलने का अवसर दिया है । मैं सुन रहा था लंबे दिनों से एन0डी0ए0 के सभी सम्मानित विधायकों से यह बात सुनते रहा हूं । डॉ0 सुनील जी भी हमारे साथ एम0एल0ए0 रहे हैं, मैं करीब से इनको जानता हूं । इन्होंने कहते-कहते और खास करके एन0एन0डी0 के विधायक जब बोलते हैं सदन में तो 2000 पहले की बात को उजागर करते हैं । इसी पर मुझे एक शेर याद आती है कि:

''यू हीं शाख से पत्ते गिरा नहीं करते
जो बिछुड़ जाते हैं वह मिला नहीं करते
जो मौसम आया है उसे शुमार करो
गुजरे हुये दिनों को कोई गिना नहीं करते ।''

अध्यक्ष : भूदेव जी, एक मिनट तो पहले यह तय करिये कि अजीत जी की बात मान लें कि आपकी बात मान लें । अजीत जी ने कुछ और कहा है आपने कुछ और कहा है । आप तय कीजिये क्या मान लें ।

श्री भूदेव चौधरी : आप कस्टोडियन हैं, हमारे अभिभावक हैं । आप सबकी बात को मानें यह अधिकार आपको है ।

अध्यक्ष : जारी रखिये ।

श्री भूदेव चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आज मुख्य रूप से सहकारिता विभाग पर और इसके साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग पर और खेल विभाग पर, नगर विकास विभाग की भी

चर्चा है गिलोटिन में इसलिये मैं संक्षिप्त में सारे विषयों का जिक्र करना चाहता हूं । महोदय, सहकारिता का गठन 25 मार्च, 1904 ईसवीं को हुआ और तब से इसका जो उद्देश्य और मकसद था कि भिन्न-भिन्न जगहों में व्यक्ति हैं, उसको समाहित करके, एकत्रित करके एक को-ऑपरेशन, एक को-ऑपरेटिव का निर्माण कराया जाय, तब से इस को-ऑपरेटिव को हिंदुस्तान के लोगों ने अंगीकार किया है, चल रहा है । महोदय, जब बजट सत्र चलता है या फिर सदन चलता है तो बिहार के 13 करोड़ लोगों की नजर इस सदन पर रहती है । खास करके जो किसान हैं, जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, निसहाय है, दलित है । उनलोगों की नजर पड़ती है कि सदन के माध्यम से कुछ हमलोगों के जीवनयापन के लिये या मेरे तकदीर, मुकद्दर के बदलाव के लिये कोई योजना बनेगी और यह किसानों के हित में, पिछड़ों के हित में अगर इसका विकास संभव है तो इसका एकमात्र विभाग है, वह है सहकारिता । सहकारिता से लोगों को बड़ी उम्मीद है । अध्यक्ष महोदय, कह सकता हूं मैं कि 17 वर्षों के सुशासनकाल जो तथाकथित सुशासन कहलाते हैं, इन्होंने वंचितों पर, पिछड़ों पर, किसानों पर पर्याप्त रूप से कोई ध्यान नहीं दिया, यह कहने में मुझको कोई संकोच नहीं है । महोदय, जैसा कि आप और हम सभी लोग जानते हैं कि बिहार में 76 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो कृषि पर आधारित हैं, उसका जीविकोपार्जन, उसकी आजीविका सिर्फ कृषि पर निर्भर करती है । लेकिन यह भी कहने में बड़ा दु:ख होता है, भारी मन से कहना पड़ता है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे अगर कोई गरीब राज्य है तो उस राज्य का नाम है बिहार । बिहार में किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है । मैं गांव से आता हूं, देहात से आता हूं मेरा सुदूर क्षेत्र है मैं देखता हूं वहां के किसानों की हालत को तो आंख से आंसू निकलता है कि वह किसान जिसके पांव में जूते नहीं है, फटी हुई गंजी है, फटी हुई, मैली हुई धोती है, एक हाथ में अगर छड़ी है तो दूसरे हाथ में कुदाल है । वह दिन और रात कड़ी मेहनत करता है । हिंदुस्तान में सबसे अधिक अगर मेहनत करने वाला किसान है तो वह बिहार में है और यह बिहार हिंदुस्तान के हर किसानों से इसकी हालत बद से बदतर है । इसके पीछे सरकार की मानसिकता और सोच का ढीलापन है । (क्रमश:)

टर्न-13/राहुल/21.02.2024

श्री भूदेव चौधरी (क्रमश:) : महोदय, आपको मालूम है कि यहां 7-7 नदियां हैं । हिन्दुस्तान में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां इतनी नदियां हों किन्तु बिहार में हर कोने में 7-7 नदियां हैं । फिर भी यहां इतना ही नहीं 7 नदियों के अलावा हिंदुस्तान में बिहार

ऐसा राज्य है जहां की मिट्टी बड़ी ही उपजाऊ है । फसल भी उगती है, किसान भी मेहनत करते हैं लेकिन उसको अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं होता है जिसका एकमात्र कारण यह है कि बिहार में बाढ़ और सुखाड़ से निजात पाने की जरूरत है । अगर किसानों का हित चाहते, अगर किसानों की भलाई चाहते, अगर नौजवानों की भलाई करना चाहते तो इसका एक ही उपाय है कि उत्तरी बिहार में जो बाढ़ की विभीषिका से यह धरती त्रस्त होती है और दक्षिण बिहार में सुखाड़ से जो त्राहिमाम-त्राहिमाम करता है इसके संबंध में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है । विगत दिनों मुख्यमंत्री जी जब बांका गये थे तो हमने कहा था कि अगर आप किसानों के हित में चितिंत हैं तो 1965 के बाद एक भी नहर का निर्माण नहीं हुआ है । एक भी डैम का निर्माण नहीं हुआ है इसलिए हमने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि भागलपुर, जमुई, बांका की जमीन इतनी उपजाऊ है, वह इतनी ताकतवर है, इतनी ऊर्जा है उसकी जमीन में लेकिन पानी के अभाव में जल के अभाव में वह खेती नहीं कर पाता है और भूखा मरता है । सर, मुझको यह कहने में बड़ा दुख होता है कि इस बिहार के 2 करोड़ 50 लाख नौजवान जिसके हाथों में काम करने की ताकत है, जो खुदाल चला सकता है, जो हल जोत सकता है, जो खेती कर सकता है वह बूढ़ी मां को छोड़कर, बूढ़े बाप को छोड़कर, जवान पत्नी को छोड़कर दिल्ली पंजाब हरियाणा की धरती पर दर-दर की ठोकर खाता है। अगर पानी की सुविधा हो जाय, जल की सुविधा हो जाय तो मुझको तो गर्व है कि हिन्दुस्तान की सर्वश्रेष्ठ उपजाऊ जमीन, सबसे ऊर्जावान जमीन इसी बिहार में है और 7-7 नदियां हैं जिसके पानी का उपयोग अगर खेतों की सिंचाई में हो तो मुझको लगता है कि उन जवानों को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है । यहां बूढ़ा बाप, बूढ़ी मां दवा के लिए विचलित है, पानी के लिए, खाने के लिए मोहताज है, उसके खेत हैं, खलिहान हैं, उसमें काम करने की ताकत है लेकिन यहां काम नहीं है, खेतों में पानी नहीं है जिसकी वजह से वह बूढ़ी मां को, बूढ़े बाप को छोड़कर के बाहर चला गया । महोदय, मैं कह सकता हूं कि इस बार यहां फसल बहुत ही रिकार्ड हुई है, फसल काफी हुई है । अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रिकार्ड फसल हुई है तो वह बिहार में हुई है लेकिन किसान बड़े दुखी हैं, किसानों को पर्याप्त मूल्य में धान की कीमत नहीं मिल पायी । होता क्या है कि आप पैक्स में जाओ । किसान पैक्स में पहले तो ऑनलाईन करो, ऑनलाईन के बाद फिर पैक्स में जाओ । वह ट्रैक्टर लेकर जाता है, वह किसी का ठेला लेकर जाता है, वह किसी की ट्रॉली लेकर जाता है, उसका भाड़ा लगता है और 10 किलोमीटर वह जाता है और वहां जाने के बाद किसानों को 3-4 दिन तक इंतजार

करना पड़ता है । उसके इंतजार करने के बाद भी उसको इस तरह से खामियां, कमियां निकालते हैं । वे लोग कहते हैं कि इसमें नमी है, यह अच्छी फसल नहीं है इसलिए कम रेट में लेंगे । दुर्भाग्य है कि इस बिहार में आध्रंप्रदेश के लोग आ रहे हैं, तेलंगाना के लोग आ रहे हैं, बंगाल के लोग आ रहे हैं । वे लोग आते हैं और किसानों के खेतों में जाकर किसानों को एडवांस पैसा देते हैं और कम रेट में चूंकि किसानों को उसी खेती से बीमारी का भी ईलाज कराना है, उसी खेती से पढ़ाई का भी काम करना है, उसी ऊपज से, उसी धान से बेटी की भी शादी करनी है । इन मुसीबतों, इन दिक्कतों को देखते हुए वह कम रेट में धान दे देता है और यह कहने में मुझको जरा भी संकोच नहीं है कि हिन्दुस्तान में चाहे जितने भी राज्य हैं उनसे ज्यादा खूबसूरत और सस्ता धान इसी बिहार में मिलता है । इसको सरकार को गंभीरता से देखने की जरूरत है । अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है जब महागठबंधन की सरकार बनी थी । इस महागठबंधन की सरकार ने किसानों के धान की अधिप्राप्ति के लिए 45 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा था कि 45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद इस बार किसानों से की जायेगी लेकिन दुर्भाग्य कि इतने में सरकार बदल गयी और इस अदला-बदली का खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ा तो इसी बिहार के किसानों को भुगतना पड़ा और अभी तक उस 45 लाख मीट्रिक टन में मात्र 30 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया है यह 15 लाख मीट्रिक टन किसानों के खेतों में है, किसानों के घरों में है । किसानों के पास पर्याप्त भंडारण नहीं है कि वे रख सकें तो औने-पौने दाम में बिचौलियों के माध्यम से वह धान बेच रहा है चूंकि उसकी बेटी की शादी लग गयी है, उसके बच्चे बीमार हैं, उसके बच्चे स्कूल में ट्यूशन फी नहीं दे रहे हैं, उनके बच्चे लाचार हैं । इसलिए मैं सरकार से यही विनती और अपील करता हूं कि इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि औने-पौने दाम में किस तरह से बिचौलियों को खेत में उगी हुई फसल दे डालता है, मजबूरियां क्या हैं इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत पड़ेगी । आपको मालूम है कि इस बिहार में धान और गेहूं एम0एस0पी0 लागू है लेकिन आप दूसरे राज्यों में जाकर देखिये वहां देखा जाय तो वहां तिलहन में, दलहन में, मक्का में एम0एस0पी0 है लेकिन यहां के किसानों को गेहूं और धान के अलावा कोई एम0एस0पी0 नहीं है । उनके साथ कितनी लाचारी है । महोदय, जब किसानों के घरों में आप जायं तो देखेंगे कि उसके बिछावन ठीक नहीं हैं, उसकी दीवार ठीक नहीं हैं, वह पेंट नहीं करा पा रहा है । कहने को तो वह किसान है लेकिन उसकी स्थिति अच्छी नहीं है और स्थिति इसलिए अच्छी नहीं है कि आपने उनको मक्का पर एम0एस0पी0 नहीं दिया, उसको चना पर

एम0एस0पी0 नहीं दिया, उसको मसूर पर नहीं दिया और इसीलिए उसकी स्थिति बद से बदतर हो गयी है, उठ नहीं सकता है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन यह कहने में मुझको कोई कठिनाई नहीं है कि एक के0सी0सी0 चलता है, 10 वर्षों से के0सी0सी0 लोन किसी को नहीं मिला और इसके पहले भी अगर किसी को मिला है तो एक एकड़ पर 20 हजार, किसी ने 20 हजार ले लिया, किसी ने 40 हजार ले लिया, किसी ने 60 हजार ले लिया और विगत दो वर्षों में खेती नहीं हुई, अकाल पड़ गया । पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे बिहार में अकाल पड़ गया । बांका में तो 75-80 प्रतिशत खेत यूं ही परती रह गये चूंकि समय पर वर्षा नहीं हुई और दूसरा कोई साधन नहीं था इसलिए लोन ले लिया । 60 हजार ले लिया, किसी ने 40 हजार ले लिया । रात में भी एक टेलिफोन आया था पुलिस उसको पकड़ने के लिए आयी, किवाड़ तोड़ दिया, घर में पुरुष नहीं था तो उसकी पत्नी को भद्दी-भद्दी गालियां दी, मात्र 60 हजार के लिए । किसानों का 60 हजार तो रात के अंधेरे में पुलिस आती है, पदाधिकारी आते हैं, उसके दरवाजे तोड़ते हैं, उनकी पत्नी को गालियां देते हैं लेकिन जब बोलूंगा तो लोग कहेंगे 11-11 लाख करोड़ माफ हो जाते हैं क्योंकि वे दे नहीं पाते हैं । आप जरा गंभीरता से इसको सोचिये कि बेचारे ने लाचारी में, बेबसी में, दिक्कतों में, मुसीबतों में उन्होंने 60 हजार रुपया लिया, 40 हजार रुपया लिया लेकिन रात के अंधेरे में किस तरह से किसान अपमानित हो रहा है । कहते हैं कि किसान भगवान है, अन्नदाता है । भगवान ने तो मुझको पैदा किया मानता हूं लेकिन अन्न कौन दे रहा है ? अन्न दे रहा है किसान । वह भगवान का दूसरा रूप है लेकिन कह देने से अब भी वह चरितार्थ नहीं हो रहा है । अध्यक्ष महोदय, किसान साहब कोई नहीं कहता है, हम डॉक्टर साहब कहते हैं, एम0एल0ए0 साहब कहते हैं, एम0पी0साहब कहते हैं, क्लेक्टर साहब कहते हैं और अब तो ड्राईवर साहब भी कहने लगे हैं, कहते हैं लेकिन कहीं आपने सुना नहीं कि किसान साहब कहलाते हैं । क्या मुसीबत है, किसानों ने क्या दिक्कत की है ? आप तो गर्व के साथ बोलते हो कि किसान हमें रोटी देता है, किसाना हमारा पेट पालता है, किसान ही हमारा अन्नदाता है लेकिन वह साहब कहलाने से भी वंचित है । इसकी कितनी उपेक्षा होती है इस पर भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है । मैं तो यही कह सकता हूं कि जो बैंक हैं, को-ऑपरेटिव बैंक हैं, सेंट्रर्ल को-ऑपरेटिव बैंक हैं वे लोन मुहैया करते हैं, आपसे अपील है कि एक एकड़ पर कम से कम 3 लाख रुपया किसानों को बिना ब्याज के, शून्य ब्याज की दर पर किसानों को लोन देने की जरूरत है तभी उसके जीवन में तब्दीलियां आयेंगी, परिवर्तन आयेगा लेकिन कॉमर्शियल बैंक का क्या हाल

है आपको पता है । कॉमर्शियल बैंक तो हाथ उठा लेता है कि मेरे तो अधिकार से बाहर है लेकिन को-ऑपरेटिव बैंक से भी 10 वर्षों से के0सी0सी0 लोन नहीं मिला है । जितना दिये उसका एक्सटेंशन कर दिये और एक्सटेंशन क्या कर दिया मैंने कल डिस्कशन किया तो एक्सटेंशन क्या होता है कि 20 हजार रुपया अगर वह लोन लिया है और उसने चुकता नहीं किया है तो 10 हजार रुपया उसी में एड कर दो और रजिस्टर मेंशन कर दो कि मैंने 10 हजार रुपया इनको के0सी0सी0 लोन दिया है । दिया नहीं जाता है वह एक्सटेंशन कर दिया जाता है । वह तो गरीब, निस्सहारा, बेसहारा हिम्मत नहीं करता है कि जाकर के वहां रजिस्टर देखे और अपने बैंक के स्टाफ से वह झगड़ा करे । यह तो बेचारा है, किसान तो बेचारा है वह ट्रेनों में चलता है तो यह कहने में संकोच करता है कि हम किसान हैं ।

क्रमशः

टर्न-14/मुकुल/21.02.2024

(क्रमशः)

श्री भूदेव चौधरी : किसान को एक चपरासी बोल देगा, एक क्लर्क बोल देगा कि मैं सरकारी नौकरी करता हूं लेकिन उस किसान को शर्म आती है यह कहने में कि मैं किसान हूं । उनको ट्रेन में जगह नहीं मिलती है अगर वह कह दे कि मैं किसान हूं, मैं खेती करता हूं, उनको मान-सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती है । इसलिए मेरी सरकार से अपील है कि अगर आप चाहते हैं कि बिहार के किसानों का हित हो तो जो लोन मुहैया होता है उसको शून्य पर उनको मुहैया करवाइये और एक एकड़ जमीन जिनके पास है उनको कम से कम तीन लाख रुपया दीजिए तभी उसके तकदीर और मुकद्दर में परिवर्तन होगा, तभी उसके जीवन में खुशहाली आयेगी । महोदय, मुझे स्वास्थ्य से भी संबंधित कुछ विषयों पर कहने की जरूरत है । आपको मालूम है, अभी डॉक्टर सुनील साहब कह रहे थे कि डॉक्टर इतने हो गये-इतने हो गये, मैं उस पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं । लेकिन आपको तो मालूम है कि चंद महीने स्वास्थ्य मंत्री हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हुये थे और उन्होंने 60 दिन का एक अभियान चलाया, 60 दिन का संकल्प लेकर के उन्होंने काम शुरू किया और सभी लोगों को याद होगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : भूदेव जी, आप अपनी बात बोलिए ।

श्री भूदेव चौधरी : डॉक्टर साहब, मैं वैसे डॉक्टर की चर्चा करना नहीं चाहता हूं जो ऑपरेशन के समय में कैंची पेट में ही छोड़ देता है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : भूदेव जी, आप इधर देखकर बोलिए ।

श्री भूदेव चौधरी : मैं ऐसे डॉक्टरों की चर्चा करना नहीं चाहता हूं, मैं डॉक्टर सुनील जी को भी करीब से जानता हूं, इसलिए मैं उनके विषय में ज्यादा तारीफ करना नहीं चाहता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इधर देखकर बोलिए ।

श्री भूदेव चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि यह महागठबंधन की सरकार बने हुए 17 महीने हुए हैं, 8-9 अगस्त, 2022 को बिहार में एक नई सरकार बनी, एन0डी0ए0 नहीं बल्कि महागठबंधन की सरकार बनी और इन 17 महीनों में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने स्वास्थ्य विभाग अपने जिम्मे लिया और सबको मालूम है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, सबको मालूम है कि रात के अंधेरे में, सबको मालूम है सबने देखा होगा कि रात के अंधेरे में और उस ठंड की रात में जहां कोई घरों से निकलता नहीं था, जिनको ठंड लगने का डर था उस समय भी रात के 12 बजे, 1 बजे उस ठिठुरनभरी रात में, ठंड के मौसम में स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हॉस्पिटल घूमते थे ।

(व्यवधान)

माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हिन्दुस्तान के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे जो रात के अंधेरे में भी 12 बजे रात के अंधेरे में भी, ठंड के मौसम में अस्पताल का निरीक्षण करते थे ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : भूदेव जी, पहला स्वास्थ्य मंत्री मत कहिये, पहला मैं भी हो सकता था । मैं भी स्वास्थ्य विभाग में ढाई साल काम किया हूं तो मैं जानता हूं । पहला मत कहिये, बाकी अपनी बातों को बोलिए ।

(व्यवधान जारी)

श्री भूदेव चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माफी चाहता हूं । उन्होंने पद की जिम्मेवारी ली है । पहला नहीं, बल्कि उन्होंने हिन्दुस्तान में जिम्मेवारी ली जिसने इतिहास रच दिया कि 12 बजे रात में भी हॉस्पिटलों का निरीक्षण करने जाते थे ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष महोदय, इन 17 महीनों के अंदर, जरा उपलब्धि भी जाननी चाहिए । अध्यक्ष महोदय,

''गजब की बांसुरी बजती है, वृंदावन बसइया की ।

करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की ।।''

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुरलीधर यहां है, नंद किशोर मैं हूं ।

श्री भूदेव चौधरी : अध्यक्ष महोदय, किसकी तारीफ करूं, आपकी तारीफ करूं कि इनलोगों की तारीफ करूं, मैं तो असमंजस में हूं अध्यक्ष महोदय कि आपसे अनुरोध करूं कि उनलोगों से अपील करूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इधर देखकर बात कीजिए ।

श्री भूदेव चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 17 महीने के अंतराल में तेजस्वी यादव जी की इतनी अच्छी सोच थी कि उन्होंने हर प्रखंड में पी0एच0सी0 को सी0एच0सी0 में कन्वर्ट किया । जहां हर प्रखंड में 30 बेड का हॉस्पिटल बनना तय हुआ है ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय,....

अध्यक्ष : माननीय सत्यदेव राम जी आप क्यों भूदेव जी का समय बर्बाद कर रहे हैं, इनका समय बर्बाद मत कीजिए ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, कई विभागों के आज बजट आये हैं और ट्रेजरी बेंच पर केवल माननीय मंत्री श्रवण जी को छोड़कर कोई भी मंत्री नहीं हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य भूदेव जी, आप बोलते रहिए, आपके पास केवल 3 मिनट का ही समय है।

(व्यवधान)

श्री भूदेव चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अब मैं कह सकता हूं, जैसा कि डॉक्टर सुनील साहब...

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, सरकार तो सुन ही नहीं रही है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सत्यदेव राम जी सरकार पूरा सुन रही है ।

(व्यवधान जारी)

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, सरकार नहीं सुन रही है ।

अध्यक्ष : सत्यदेव राम जी, सरकार पूरा सुन रही है, सब कुछ नोट किया जा रहा है ।

(व्यवधान जारी)

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, ट्रेजरी बेंच खाली है ।

श्री भूदेव चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह आपके अधिकार क्षेत्र की बात है कि अगर यहां पर कोई मंत्री नहीं है तो यह आपको संज्ञान में लेना है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप ही इधर अकेले हैं, वे भी उधर अकेले हैं ।

श्री भूदेव चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ठीक है । डॉ सुनील साहब जी आई0जी0आई0एम0एस0 की बात कर रहे थे, मैं हर लोगों की बात बहुत गंभीरता से सुनता हूं । आई0जी0आई0एम0एस0 में जब स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी निरीक्षण करने गये और उन्होंने उस स्थिति को देखा है । अध्यक्ष महोदय, यह पहला

स्वास्थ्य मंत्री थे जिन्होंने उसी क्षण, उसी समय कहा कि अब आई0जी0आई0एम0एस0 में नि:शुल्क चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होगी । अध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि 114 प्रकार की दवाइयां मिलती थीं लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी की घोषणा के बाद अब 200 प्रकार की दवाइयां वितरण होने लगी हैं, यह तेजस्वी प्रसाद यादव जी की करामात है, यह तो मैं कह सकता हूं । अध्यक्ष महोदय, मैं नगर निगम की भी चर्चा करना चाहता हूं, चूंकि मैंने एन0डी0ए0 सरकार के नगर विकास को देखा है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके पास केवल 1 मिनट का समय है ।

श्री भूदेव चौधरी : अध्यक्ष महोदय, नगर विकास में हमने खुद देखा है कि यह पटना महानगर हल्की सी बारिश में डूब गया था, इतना ही नहीं इसके गवाह हैं हमारे तत्कालीन जो डिप्टी सी0एम0 माननीय सुशील कुमार मोदी जी थे उस बाढ़ में वे घर से बाहर हाफ पैंट पहनकर निकले थे । लेकिन 17 महीनों में जब नगर विकास की जिम्मेवारी तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथों में आई तो आज देखिए कितना खूबसूरत है, बारिश हुई और कहीं पर भी आपको पानी नहीं दिखाई दिया यह किसकी करामात है, यह करामात थी सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव जी की । मैं बड़ाई नहीं करना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय,

''हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है,
उनके होंठों की खामोशी भी सनद होती है,
चुप रहूं तो खत्म हो एजाज-ए-सुखन,
चुप रहने से कातिलों को भी मदद मिलती है ।।''

अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय न लेते हुए सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आपने मुझको समय दिया इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और एक छोटा सा शेर कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भूदेव जी मुझे लगता है कि मुझे भी अपना शेर आपको सुनाना पड़ेगा ।

भूदेव जी, बोलिए, बोलिए आप अपना शेर सुना दीजिए ।

श्री भूदेव चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं कल की घटनाओं का जिक्र नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि शैलेंद्र जी यहां पर बैठे हुए हैं । उसकी चर्चा पूरे बिहार में हो गई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग दलितों को, महादलितों को, पिछड़ों को बोलने से मना करते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना शेर बोलिए ।

श्री भूदेव चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि

''छेड़ने से मूक भी वाचाल हो जाता है,
टूटने से सीसा भी काल हो जाता है,
इस तरह दलितों को मत अपमानित करो,
जलने से कोयला भी लाल हो जाता है ।''

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : कोई अनुसूचित जाति के लोगों को जलील नहीं कर सकता ।

(व्यवधान)

आपलोग शांत रहिये, मेरी बात सुनिये । आज इस देश के अंदर सबको समान अधिकार है, कोई किसी का अपमान करने की कोशिश करेगा उसको समाज स्वीकार नहीं करेगा और सरकार भी स्वीकार नहीं करेगी ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, श्री राम विलास कामत जी । आपके पास 10 मिनट का समय है ।

श्री राम विलास कामत : अध्यक्ष महोदय, मैं सहकारिता विभाग के मांग के समर्थन में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं । आप आसन से मुझे अपनी बात को कहने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, आपका सम्मान करना चाहता हूं ।

क्रमशः

टर्न-15/यानपति/21.02.2024

श्री रामविलास कामत (क्रमशः) : अध्यक्ष महोदय, आज सहकारिता विभाग की मांग पर चर्चा हो रही है और हम समझ सकते हैं कि यह जो सहकारिता विभाग है वह बिहार में बिहार के किसानों को मजबूत करने के लिए, उसको समृद्ध और संपन्न बनाने के लिए सहकारिता विभाग की भूमिका काफी अहम होती है । हम कहना चाहते हैं कि यह हमारा राज्य बिहार है, यह किसानों का राज्य है, आज भी यहां पर आंकड़े बताते हैं कि 76 प्रतिशत हमारी आबादी किसानी पर निर्भर है, खेती पर आश्रित है और अपने परिवार का जीवन-यापन खेती से करती है । हम देखते आए हैं कि बिहार में जबसे हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार काम करना शुरू की है तो बिहार के चहुंमुखी विकास के साथ किसानों के हित के लिए भी, किसानों की समृद्धि के लिए भी, किसानों की तरक्की के लिए भी कई कार्यक्रम समय-समय पर लाते रहे हैं, उसको लागू करते रहे हैं ताकि बिहार के किसानों की उन्नति हो, उनकी समृद्धि हो, उनमें खुशहाली आए यह अनेक कार्यक्रमों के माध्यम

से सरकार करती रही है । हम याद दिलाना चाहते हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में 2008 में कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया गया था और कृषि रोड मैप जिसके माध्यम से बिहार के किसानों के लिए, उनके हित के लिए, खेती में गुणात्मक सुधार के लिए उस कृषि रोड मैप में कई कार्यक्रम ऐसे लागू किए और उस कार्यक्रम के माध्यम से खेती को मजबूती और किसानों को समृद्ध करने का काम शुरू किया गया । आज जब हम देखते हैं कि 2008 से आज 2024 तक में चौथा कृषि रोड मैप बनकर के तैयार हुआ है पिछले अगर हम कहें कि 18 अक्टूबर 2023 ई0 को हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा चौथा कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया गया और उसमें जो प्रावधान किया गया 1 लाख 62 हजार 268.78 करोड़ रुपया कृषि के क्षेत्र में आनेवाले पांच वर्षों में कृषि रोड मैप के माध्यम से खर्च करने का प्रावधान किया गया । मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने बिहार में आकर के इस महत्वूपर्ण कृषि सुधार के लिए जो कार्यक्रम बिहार सरकार चला रही है उसमें अपना समय देकर के और इन महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाने में यहां की सरकार को समर्थन दिया है उनकी हौसला अफजाई की है । हम कहना चाहते हैं कि बिहार की जो सरकार है वह कृषि के क्षेत्र, कृषि रोड मैप के माध्यम से कई कार्यक्रमों को लागू किए हैं और उसी के माध्यम से सहकारिता विभाग का भी उस कृषि रोड मैप में काफी बड़ी भागीदारी रही है सहकारिता विभाग के माध्यम से किसानों को समृद्ध करने के लिए, किसानों को मजबूत करने के लिए, उनकी आय को बढ़ाने के लिए, उनकी आय को दुगुनी करने के लिए और आज जब पूरे देश में जब आकलन होता है तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो राज्य के किसान हैं वह अपनी मेहनत से..

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री भूदेव चौधरी ने आसन ग्रहण किया)

अपनी लगन से कठिन परिश्रम के साथ और बिहार का कृषि रोड मैप जो उसमें हिस्सेदारी है, सहकारिता विभाग की भी हिस्सेदारी है वह अपने काम को अंजाम तक पहुंचाए हैं और आज हम कह सकते हैं हमारे साथी, हमारे विरोधी दल के जो साथी अभी बोल रहे थे उन्होंने भी इन बातों को दर्शाया है कि बिहार में इस बार जो फसल हुई है चाहे वह धान की फसल हो, चाहे गेहूं की फसल हो, चाहे मोटे अनाज मक्का की फसल हो वह रिकॉर्ड उत्पादन इस बार बिहार में किसानों का हुआ है और उसको संरक्षित करने के लिए, उसको संगठित रूप से एकत्रित करने के लिए उनके मूल्य की समृद्धि करने के कृषि रोड मैप के माध्यम से जो सहकारिता विभाग के द्वारा काम किया गया है वह सराहनीय रहा है । हम

कहना चाहते हैं कि बिहार में जो सहकारिता विभाग काम कर रही है, उनके जिम्मे जो जवाबदेही दी गई है, उस जवाबदेही का निर्वहन करते हुए किसानों की समृद्धि के लिए अनेक कार्यक्रम सहकारिता विभाग के माध्यम से आज चलाया जा रहा है । सहकारिता विभाग अपने इस कार्यक्रम में प्रथम उनका है कि पूरे बिहार के सभी पंचायतों में पैक्स का गठन हो और पैक्स का गठन आज हम कह सकते हैं कि बिहार के सभी पंचायतों में पैक्स का गठन कर दिया गया है और उस पैक्स के माध्यम से किसानों को जो लाभ देना है, उसमें जो प्रावधान किया गया है उसको समृद्ध और मजबूत करने के लिए जो कार्यक्रम सरकार के द्वारा तय किया गया है, वह सराहनीय काम है । आज हमारे किसान की फसल चाहे वह धान हो, चाहे गेहूं हो उनको बेचने के लिए, उनको एक सही मूल्य मिलने के लिए जो सहकारिता विभाग के पैक्सों के माध्यम से.....

सभापति : माननीय सदस्य, आप कंक्लूड करें, आपका समय समाप्त होनेवाला है ।

श्री रामविलास कामत : महोदय, हमारा समय कितने मिनट का है । पैक्स के माध्यम से किसानों को जो लाभ अभी दिया जा रहा है, पैक्स के माध्यम से धान खरीद करके और उस धान का मूल्य अधिक मिले इसके लिए बिहार सरकार ने चावल मिल की स्थापना की है, आज बिहार में अगर हम देखते हैं तो चावल मिल की स्थापना चार सौ से ज्यादा हुई है । इससे पहले हमारे राज्य में अगर जनवितरण के चावल की आवश्यकता होती थी तो दूसरे राज्यों से यहां चावल मंगाना पड़ता था लेकिन आज हमारे यहां धान की खरीद पैक्स से होती है और पैक्स के माध्यम से चावल का निर्माण होता है । इसके लिए हमारे यहां जो मिल की स्थापना की गई है, चावल मिल की स्थापना की गई है और उससे सीधे चावल जनवितरण की दुकान तक पहुंचता है यह बहुत बड़ी बात है । हम कहना चाहते हैं पैक्स और व्यापार मंडल के माध्यम से आधारभूत संरचना का विकास करने हेतु 200 मीट्रिक टन, 500 मीट्रिक टन और एक हजार मीट्रिक टन की क्षमता के गोदाम का निर्माण कराया गया है जो पैक्स और व्यापार मंडल के माध्यम से होना है ।

सभापति : अब आप समाप्त करें, कृपया आप समाप्त करें । माननीय सदस्य श्री मुकेश कुमार रौशन जी, अपना पक्ष रखें, 15 मिनट का समय है ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : माननीय सभापति महोदय, कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए हम खड़े हैं, इसके लिए हम अपने नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और अपने मुख्य सचेतक शाहीन साहब और महुआ विधान सभा जहां से हम जीतकर आते हैं वहां की महान् जनता के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं जिनके आशीर्वाद से आज हम यहां बोलने

के लिए खड़े हैं । महोदय, बहुत बड़ी बात है स्वास्थ्य विभाग, सहकारिता विभाग और कला संस्कृति विभाग पर आज बोलने का समय मिला है हमको । महोदय, पी0एम0सी0एच0 में स्थायी अधीक्षक का पद पिछले कई वर्षों से रिक्त है और वहां पर जो डॉ0 आई0एस0 ठाकुर को संविदा पर नियोजन किया गया है महोदय, वह बहुत भ्रष्ट डॉक्टर हैं और इतना ही नहीं, वहां के जो अधीक्षक हैं उनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग के आलाधिकारी को 25 लाख रुपया हर महीने उपहारस्वरूप दिया जाता है । 2022 में तत्कालीन मंत्री उस समय मंगल पांडे जी थे उस समय जब मैंने यह मामला उठाया था तो मंगल पांडे जी ने कहा था कि मार्च में बजट सत्र खत्म होगा, अप्रैल में वहां पर जो प्रभारी अधीक्षक हैं उनकी जगह स्थाई रूप से अधीक्षक की बहाली करूंगा ।

(क्रमशः)

टर्न-16/अंजली/21.02.2024

श्री मुकेश कुमार रौशन (क्रमशः) : लेकिन महोदय, आज तक स्थायी अधीक्षक का पद रिक्त ही है ।

(व्यवधान)

सुन लीजिए न पहले, क्या हुआ, सुनिये तो पहले । सुनिये पहले । आई0एस0 ठाकुर के ऊपर आयुष्मान भारत में घोटाला किया गया है उसका आरोप है, तीन सदस्यीय कमेटी के द्वारा जांच लंबित है और रात के अंधेरे में 31 जनवरी, 2024 को जब सरकार बनाने और बिगाड़ने का खेल चल रहा था, एन0डी0ए0 के द्वारा उस समय आधी रात को अंधेरी रात में वह फाइल लेकर और आला अधिकारी जो हैं आई0एस0 ठाकुर को नियोजन पर रख लेते हैं, संविदा पर । महोदय, एक चीज जान लीजिए महोदय, आई0एस0 ठाकुर के ऊपर कई सारे वित्तीय अनियमितता है । 31 जनवरी माननीय मुख्यमंत्री जी के...

(व्यवधान)

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : पंकज जी, आपको अनुमति लेने की जरूरत पड़ेगी तो आप अनुमति लेंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं है ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय, 31 जनवरी को रात के अंधेरे में फाइल पर जो खेला हुआ है, मोटी रकम लेकर के एक साल के लिए संविदा पर नियोजित किया गया है । महोदय, आप जान जाइए यह जांच का विषय है । आई0एस0 ठाकुर को वित्तीय प्रभार दिया गया है जबकि सरकार का संकल्प है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा कि जो संविदा पर रहेंगे उनको वित्तीय प्रभार नहीं देना है । वित्तीय प्रभार भी दिया गया, बगल के डेंटल कॉलेज, मैं भी एक दांत का डाक्टर हूं महोदय, मुझे जनता

के आशीर्वाद से पहली बार दांत के डॉक्टर के रूप में, बिहार विधान सभा के सदस्य के रूप में यहां आने का मौका मिला । महोदय, मैं दंत चिकित्सक भी हूं । डेंटल कॉलेज में जो पी0डी0सी0एच0 है उसमें जो प्रिंसिपल की बहाली की गई है वह भी संविदा पर हैं डॉ0 तनोज कुमार लेकिन उनको वित्तीय प्रभार नहीं दिया गया है । वित्तीय प्रभार दिया गया है पी0एम0सी0एच0 के प्रिंसिपल को, अब समझ जाइए कि ये भेदभाव आखिर पटना का इतना बड़ा, बिहार का अस्पताल है पी0एम0सी0एच0 और उसमें जिस पद पर रखा गया है, अधीक्षक का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है । महोदय, आप समझ सकते हैं कि जिस समय तेजस्वी यादव जी पी0एम0सी0एच0 गए थे और जांच किये थे उनके आला-अधिकारी उनको बचाने के लिए पूरा कसरत करने का काम किए लेकिन उसके बावजूद तेजस्वी यादव जी ने उनको एक्सटेंशन नहीं देने का काम किया महोदय और जैसे ही हमलोग सरकार से बाहर हुए उनको रात के अंधेरे में दे दिया जाता है एक्सटेंशन संविदा पर रख लिया जाता है, क्या बात है महोदय । अब बताइए । महोदय, ऐसे भ्रष्ट, अवैध, योग्यताधारी, फ्रॉड और जिन पर दर्जनों जांच के मामले लंबित हों संविदा पर नियोजन की गई, वह बिहार के सबसे बड़े अस्पताल के अधीक्षक के पद पर कैसे रह सकते हैं । महोदय, जबकि इनसे दक्ष, सुयोग्य, वरीयता सूची में नियमित पदस्थापित प्राध्यापक मौजूद हैं जिनमें अनुसूचित जाति, दलित, महिला प्राध्यापक सूची में हैं लेकिन उनको जो है न बनाकर और किसी ऑफिसर के दबाव में आकर के और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास उस समय स्वास्थ्य विभाग था, किस तरीके से डॉ0 आई0एस0 ठाकुर को बनाया गया, इस पर सरकार को गंभीरतापूर्वक बताना चाहिए कि आखिर क्या मोल-जोल हुआ है डॉ0 आई0एस0 ठाकुर से, क्या और कोई डॉ0 उसमें योग्य है या नहीं है । महोदय, जिस तरीके से बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का यह हाल है माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए बिहार के लोगों को कि बिहार के राजेंद्र नगर में आंख का अस्पताल इतना बड़ा अस्पताल है महोदय, जिस पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया और वह अपना आंख का इलाज दिल्ली कराने जाते हैं इससे बड़े शर्म की बात क्या होगी उनको अपने चिकित्सकों पर भरोसा नहीं है क्या महोदय । अब बताइए कि जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जब तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे मिशन-60 के तहत सभी अस्पतालों को चकाचक व्यवस्था करने का काम किये तो बी0जे0पी0 के लोगों को पेट में दर्द हो रहा था । रात के 12 बजे जब सदर अस्पताल हाजीपुर पहुंचते है जो चिकित्सक वहां पर अनुपस्थित पाये जाते हैं उनपर कार्रवाई करने का काम करते हैं पूरा स्वास्थ्य महकमा जो है वह हड़कंप मच जाता है । आज क्या

हाल है ? बिहार में कोरोना के समय जो कोरोना घोटाला हुआ जो माननीय विधायकों का दो-दो करोड़ रुपया जो राशि काटी गयी आखिर उसको खर्च कहां किया गया है ? 243 विधायक का दो-दो करोड़ और बगल में जो माननीय बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं उन लोगों का दो-दो करोड़ रुपया काटा गया । आखिर 600-700 करोड़ रुपया खर्च कहां हुआ इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए महोदय । महोदय, महुआ में महागठबंधन की सरकार जब 2015 में बनी, जब 2015 में सरकार बनी तो तत्कालीन उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी और वहां के उस समय तत्कालीन विधायक श्री तेज प्रताप यादव जी सब लोगों ने प्रयास किया और महागठबंधन की सरकार ने वहां पर मेडिकल कॉलेज देने का काम किया । महोदय, वर्ष 2016 में स्वीकृति होती है, 2020 में शिलान्यास होता है और 2024 आ गया ,यह आठ साल का समय है आखिर क्यों भेदभाव किया जा रहा है । बगल में सरायरंजन में काम शुरू हुआ 2020 में और वह बनकर तैयार हो गया 2024 में लेकिन हमलोग के यहां भेदभाव किया जा रहा है । अब बताइए, हमारे यहां सी0एच0सी0 बनाया गया है उसका भवन जो है 2020 में उद्घाटन किया और अभी जर्जर हो गया । वहां पर न एक्स-रे हो रहा है, न अल्ट्रासाउंड है और वहां चिकित्सकों की भी भारी कमी है । कई बार हमलोगों ने इसकी आवाज उठाई, बी0एम0एस0आई0सी0एल0 के द्वारा कहा गया कि जांच कराई जाएगी लेकिन आज तक जांच नहीं कराया गया है । महोदय, हमारे क्षेत्र में कई ऐसी चीज हैं जैसे एस0डी0एच0 जो सब-डिवीजनल हॉस्पिटल है उसमें लाया गया कि एन0आई0सी0यू0 बनाया जाएगा वहां पर उपकरण खरीद कर रखा हुआ है आज तक एन0आई0सी0यू0 नहीं बनाया गया है तो इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए । जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार में काम हो रहा था स्वास्थ्य व्यवस्था में काफी सुधार हुआ और जो अस्पताल में हमलोग देखतें कि जहां एन0डी0ए0 की सरकार में एन0एम0सी0एच0 में पानी लगा रहता था, सांप और बिच्छू हुआ करते थे, जहां पर कुत्ता बेड पर सोता था आज वहां मरीज का इलाज इसलिए हो रहा है कि तेजस्वी यादव जी ने मिशन-60 के तहत महागठबंधन की सरकार में काम करने का काम किया ।

(व्यवधान)

सुनिये, सब बताएंगे । आपके यहां ऑक्सीजन प्लांट का, आपलोगों ने शिलान्यास किया था आज तक बना नहीं...

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : मुकेश जी, इस तरफ देखकर आप बोलें ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : सभापति महोदय, कला संस्कृति विभाग के द्वारा एक अच्छी पहल की गई है जिसकी शुरूआत महागठबंधन की सरकार में हुआ । ''मेडल लाओ, नौकरी पाओ'' जिसके तहत सैकड़ों लोगों को नौकरी दिया गया । उस समय तत्कालीन उप मुख्यमंत्री हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी थे । तत्कालीन खेल मंत्री श्री जितेन्द्र राय जी थे, उस समय खेलो और मेडल लाओ, नौकरी पाओ का जो आविष्कार किया गया, आप सब लोग देख रहे हैं कि हमारे बिहार के लोग जो खिलाड़ी हैं खेलेगा बिहार तभी तो पढ़ेगा बिहार । मेरे क्षेत्र महुआ और चेहराकलां है महोदय, खेल मैदान के लिए कई बार हमने आवाज उठाया है और स्टेडियम का निर्माण कराने के लिए, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री अभी यहां बैठे थे, लगता है चले गए, तारकिशोर बाबू, 2021 में उन्होंने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द आपके यहां खेल का स्टेडियम निर्माण कराया जाएगा लेकिन कई बार एन0ओ0सी0 देने के बाद भी, जिला से एन0ओ0सी0 आ गया उसके बावजूद आज तक खेल का मैदान और स्टेडियम नहीं बना । महोदय, हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं सरकार से कि स्टेडियम का जो मानक है उसमें थोड़ी नरमी लायी जाय और जो नियम, कानून है उसके हिसाब से बनाकर, ऐसा बनाया जाय कि जो जिला से एन0ओ0सी0 आया है उस पर निर्माण कार्य हो । महोदय, सहकारिता विभाग का जो हाल है संपूर्ण बिहार में अभी जो धान अधिप्राप्ति चल रहा है डी0सी0ओ0 के द्वारा पर क्विंटल 15 रुपया घूस लिया जाता है और एम0डी0 के द्वारा और डी0सी0ओ0 के द्वारा 12 रुपया एम0डी0 के द्वारा और 13 रुपया बी0सी0ओ0 के द्वारा लिया जा रहा है, यह अभी डबल इंजन की सरकार में तीन-तीन जगह घूस लग रहा है । महोदय, एम0डी0, डी0सी0ओ0, बी0सी0ओ0 तो समझ जाइए कि तीन-तीन टेबल पर घूस लग रहा है । जिस तरीके से धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य जो है महोदय...

(व्यवधान)

बैठिये, सब को हम जानते हैं, बैठिये न । बैठिये । महोदय, इसकी जांच कराई जाय महोदय ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : बैठा जाय । बैठिये न ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : सहकारिता विभाग में जिस तरीके से धान अधिप्राप्ति में घूस लिया जा रहा है इसकी जांच कराई जाय । किसान परेशान हैं लेकिन प्रधानमंत्री जी को समय नहीं है किसान आंदोलन में जाकर और किसानों से बात करने के लिए,

उनको प्रियंका चोपड़ा के साथ फोटो खिंचाने के लिए समय है लेकिन किसानों से बात करने के लिए समय नहीं है ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : मौका मिलेगा आपको भी । आप अपने समय का उपयोग करेंगे, आप बैठिये ।

(व्यवधान)

बैठिये-बैठिये । मौका मिलेगा, आपको भी समय उपलब्ध कराया जायेगा । आप अपनी बात रखेंगे ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : सभापति महोदय, पैक्स की स्थिति को सुधार करने के लिए सहकारिता बैंक से पैक्स को कम से कम 25 लाख रुपया का सी0सी0 जो एक परसेंट ब्याज पर दिया जाय ताकि हमारे पैक्स का विकास...

(व्यवधान)

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : कृपया शांति बनाये रखें । बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : सभापति महोदय, वैशाली जिला सहकारिता बैंक में वर्ष 2012 के पहले घोटाला हुआ था महोदय, उसका कागज जो है अभी वर्तमान एम0डी0 और वहां के पदाधिकारियों के द्वारा जला दिया गया है ।

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : कृपया आप भी ध्यान दें मुकेश जी, जिन विषयों पर आपको चर्चा करना है उसी विषय को चुने ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : सभापति महोदय, यू0पी0ए0 की सरकार ने 2009 में 1 लाख 73 हजार करोड़ की राशि किसानों का जो ऋण था उसको माफ करने का काम किया था । (क्रमशः)

टर्न-17/आजाद/21.02.2024

..... क्रमशः ....

श्री मुकेश कुमार रौशन : अभी जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, हम उससे मांग कर रहे हैं कि किसानों को जिसके पास एक एकड़ जमीन है, उसको कम से कम 5 लाख रू0 जीरो परसेंट ब्याज पर दें ताकि हमारे किसान खुशहाल हो सकें । जब हमारे किसान खुशहाल होंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा महोदय । इन्हीं चन्द बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं । जयहिन्द-जय भारत ।

सभापति(श्री भूदेव चौधरी) : धन्यवाद ।

श्री शकील अहमद खाँ : सभापति महोदय, मैं आपका 30 सेकेंड चाहूंगा । यह क्या मजाक बन गया है कि इतने सबजेक्ट पर कटौती प्रस्ताव है और इतने सबजेक्ट पर आखिर कौन जवाब देगा .....

सभापति(श्री भूदेव चौधरी) : माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका जी, अपना पक्ष रखेंगे ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : सभापति महोदय, माननीय सदस्य पुराने सदस्य हैं और उनको जानकारी है भी लेकिन जानकारी को छिपाकर वे बात रखते हैं सदन में, उससे उत्तेजना फैलाने की कोशिश करते हैं । सरकार का जो विभाग है महोदय, सारा गिलोटिन में है और सहकारिता विभाग के माननीय मंत्री जवाब देंगे महोदय, धैर्य से ये सुनेंगे तब न ।

सभापति(श्री भूदेव चौधरी) : माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका जी, अपना पक्ष रखेंगे ।

श्री विजय कुमार खेमका : सभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व का .....

सभापति(श्री भूदेव चौधरी) : ध्यान रखेंगे खेमका साहेब, आपके लिए 13 मिनट निर्धारित है ।

श्री विजय कुमार खेमका : सभापति महोदय, ध्यान है । मैं अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ तथा पूर्णिया की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिसने दूसरी बार सदन में भेजकर के बोलने का अवसर दिया है और हमारे उप सचेतक जनक जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे समय बोलने का दिया है । सभापति महोदय, मैं भी सुन रहा था और आज जो है वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद और सरकार के पक्ष में, कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, अभी मैं सुन रहा था, हमारे अजीत जी अभी यहां नहीं हैं और आदरणीय सभापति महोदय, जब आप भी वहां बोल रहे थे, तब भी मैं सुन रहा था कि कितनी छटपटाहट है विपक्ष में, कितनी पीड़ा है 17 महीना और 15 साल को बिहार भूला नहीं है । 15 साल का जंगल राज और 17 महीने का जंगल राज पार्ट-2 बिहार की 13 करोड़ जनता को याद है । मैं सिर्फ चार लाईन से बोलना शुरू करता हूँ । इसलिए सभापति महोदय, जिस दिन एन0डी0ए0 की सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उस दिन वो फेल कर गये और उसके बाद से विपक्ष के नेता सदन में नहीं हैं । मैं बोलना चाहता हूँ, महोदय सुनिए-

जिनपर विश्वास नहीं है जनता को,
वो विश्वास खोजने निकले हैं,
देश तोड़ने वाले, देश को जोड़ने निकले हैं ।
वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार के दोनों युवराज,

घोटालों का हिसाब देने निकले हैं ।

आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि एन0डी0ए0 की सरकार में जो बजट आया है, उस पर हम कटौती प्रस्ताव लाये हैं । सभापति महोदय, मैं सुन रहा था और वहां हमारे साथी बोल रहे थे, पूर्णिया में भी दोनों युवराज गये थे, किसानों की कितनी चिन्ता किये, उसको मैं बताना चाहता हूँ । इसलिए कि सहकारिता जो है, वह किसानों की आत्मा है । सभापति महोदय, यह देश, यह राज्य किसानों पर आधारित राज्य है, अन्नादाता को अगर देश में और बिहार में सबसे ज्यादा सम्मान दिया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी ने किसान सम्मान योजना से उनको सम्मानित करने का काम किया और पूर्णिया में जो युवराज हैं, जो इटली जाते हैं और इटली से ज्यादा संबंध है । वो किसानों की गोष्ठी कर रहे थे और वहां किसानों की गोष्ठी में 50 लोग मजदूर बैठे थे और उनसे पूछ रहे थे कि यहां सब्जी कैसी है, उनसे पूछा कोई सब्जी बताईए तो वे बता नहीं सके कि जो किसान पैदा करता है, उसकी सब्जी का नाम क्या होता है और दो युवराज पूर्णिया के रंगभूमि में भाषण दे रहे थे तो जनता कह रही थी कि मोदी जिन्दाबाद-नीतीश जिन्दाबाद, यह जनता कह रही थी । महोदय, यह है इनके दोनों युवराज । सभापति महोदय, यह अभी कह रहे थे कि इधर से अनुसूचित जाति का अपमान हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अनुसूचित जाति, जनजाति और माइनोरिटी का सम्मान करने वाला इस देश में कोई भी पार्टी नहीं है । भारतीय जनता पार्टी ने महादलित के बेटे को बिहार का गवर्नर बनाने का काम किया और उसके बाद देश की सर्वोच्च कुर्सी पर देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी ने श्री राम नाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाने का काम किया और ये कहते है कि दलितों का अपमान । सभापति महोदय, थोड़ा सब्र से सुनना चाहिए । देश के प्रधानमंत्री ने एक महिला को महिला सशक्तिकरण को सामने में रखकर के आदिवासी महिला को द्रौपदी मूर्म को राष्ट्रपति बनाने का काम किया । सभापति महोदय, जरा इनको समझना चाहिए कि देश की सर्वोच्च कुर्सी पर देश के प्रधानमंत्री ने कलाम साहेब को भी बैठाने का काम किया है ।

सभापति महोदय, आज की चर्चा सहकारिता विभाग पर है और इसके साथ बहुत से विभाग जुड़े हुए हैं । सभापति महोदय, सहकारिता विभाग से आज किसान जो है, उन्नत हुआ है, समृद्ध हुआ है और सहकारिता के क्षेत्र में जो है, सहकारिता सक्षम हुई है । सभापति महोदय, सम्पूर्ण देश में पहली दफा हमारी एन0डी0ए0 की सरकार में और नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता विभाग केन्द्र में अलग से बनाया गया । आज देश और प्रदेश सहकारिता से तरक्की की ओर है । सभापति

महोदय, सहकारिता की आत्मा किसानों में बसी हुई है । आज काफी बड़ी संख्या में कृषक समितियों से जुड़े हुए हैं । सभापति महोदय, 2023 में जो आप बोल रहे थे, वहां से 6777 समितियों के द्वारा 1.69 लाख किसानों को 13.73 लाख मीट्रिक टन धान 12.01.2024 तक अधिप्राप्ति करके उनके खाते में 2565.61 करोड़ का सीधा भुगतान किया गया । 30 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचे, लक्ष्य तक नहीं पहुँचे तो वह 17 महीना की बीमारी है । सभापति महोदय, कृषि रोड से इसको जोड़ा गया और सहकारिता के क्षेत्र में लगभग 6973 पक्की गोदाम बनाकर के अनाज को सुरक्षित करने का काम किया गया । सभापति महोदय, पैक्सों को कृषि संयंत्र बैंक स्थापित किया गया और ..... क्रमशः .....

टर्न-18/शंभु/21.02.24

श्री विजय कुमार खेमका : ..क्रमशः.. और पैक्सों का कंप्यूटरीकरण किया गया है । महोदय, सहकारिता के क्षेत्र में सहकारी ऋण जो अभी बता रहे थे उधर से सहकारी ऋण का वितरण वर्ष 2023-24 में 45 हजार 761 किसान को 142.63 करोड़ का किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया है । सभापति महोदय, जो फसल सहायता योजना है उसमें वर्ष 2023 में मौसम के अनुसार 15 लाख 96 हजार 922 किसान ने आवेदन किया है । वर्ष 2023-24 में आवेदन की तिथि 31 मार्च तक है आपलोग भी करवाइयेगा तो उसका भी उनको लाभ मिलेगा । महोदय, पैक्सों में कॉमन सेवा केन्द्र की स्थापना हुई है और पैक्सों में जो प्रधानमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है जन औषधि योजना जो सबसे सस्ते दर में दवाई मिलती है उसको भी पैक्स से जोड़ा गया है । महोदय, पैक्स को पेट्रोल पंप हो ताकि किसान को सीधा लाभ हो, उर्वरक की दूकान हो उससे सीधा लाभ हो । इस तरह से सहकारिता के क्षेत्र में किसान सक्षम हुआ है, किसान हमारा समृद्ध हुआ है । महोदय, बहुत से विभाग हैं समय कम है सभापति महोदय, मैं एक दो विभाग पर सुझाव दूंगा और अपनी बात को समाप्त करूँगा । सभापति महोदय, मंत्री जी आये हुए हैं, प्रेम जी बैठे हुए हैं । मैं कहना चाहूंगा एक तो जो हमारा बिहार है और हमारा सीमावर्त्ती क्षेत्र जो है । इसमें मक्का फसल सबसे ज्यादा होती है । धान का कटोरा कहलानेवाला क्षेत्र अगर दक्षिण है तो उत्तर आज मक्का का हब बन गया है। इसलिए मक्का का भी एम0एस0पी0 जो हमारी एन0डी0ए0 की सरकार बिहार में है हम आग्रह करेंगे केन्द्र से बात करके मक्का का भी एम0एस0पी0 बिहार में लागू हो। महोदय, जो पैक्स

को कठिनाई है जो पैक्स है उसमें मिलिंग तक पहुंचाना और गोदामों तक पहुंचाना एफ0सी0आइ0 का ये दस साल पुराना रेट है जो 37 रू0 क्वींटल दिया जाता है उसको रिवाइज करके रेट बढ़ना चाहिए और मिलिंग का भी ।

सभापति(श्री भूदेव चौधरी) : अब कृपया समाप्त करें ।

श्री विजय कुमार खेमका : अभी सभापति महोदय, मेरा समय बाकी है । हेल्थ के क्षेत्र में सभापति महोदय मैं सिर्फ सुझाव देकर अपनी बात को समाप्त करूँगा पूर्णियां जो सीमावर्त्ती क्षेत्र है हमारे प्रधानमंत्री जी ने दो एम्स दिया और तीसरा एम्स पूर्णियां में खुले ताकि 15 जिला और बार्डर जिला को वहां लाभ मिल सके । आशा जो हमारी दीदी है उसकी राशि बढ़ायी जाय और पूर्णियां हास्पीटल में एम0आर0आइ0 की हमारी व्यवस्था होनी चाहिए । सभापति महोदय, कला संस्कृति के क्षेत्र में भी काफी हमारे यहां बिहार में काम हुआ है । मैं एक लाइन पढ़ना चाहता हूँ उसके बाद सुझाव दूंगा- आसमान तक चमक रहा अपनी संस्कृति का ध्रुव तारा, कला हमारी लहराती है रंग-रंग के त्योहार यहां हैं, भांति-भांति के मेले हैं । ये हमारा जो बिहार है इसमें.....

सभापति(श्री भूदेव चौधरी) : अब आप समाप्त करें । श्री महानन्द सिंह जी ।

श्री विजय कुमार खेमका : सभापति महोदय, एक मिनट सिर्फ एक-दो सुझाव । महोदय, अगर मेरा समय पूरा हो गया तो लास्ट में दो चार पंक्ति अटल बिहारी वाजपेयी जी की कहकर के अपनी बात को समाप्त करूँगा । हम तो छप्पन इंच जिनका सीना है उसके हम सैनिक हैं और अटल जी ने कहा कर्त्तव्य के पुनीत पथ को सुनिये.....

सभापति(श्री भूदेव चौधरी) : आप इधर बोलिये न आपको यहां से इजाजत मिली है ।

श्री विजय कुमार खेमका : कर्त्तव्य के पुनीत पथ को हमने स्वेद से सींचा है, कभी-कभी अपने अश्रुओं, प्राणों का अर्घ्य भी हमने दिया है, किन्तु हम अपनी ध्येय यात्रा में कभी रूकेंगे नहीं, किसी चुनौती के सम्मुख कभी झुकेंगे नहीं । इसी के साथ जय भारत, जय बिहार ।

सभापति(श्री भूदेव चौधरी) : अब श्री महानन्द सिंह जी अपना पक्ष रखेंगे ।

श्री महानन्द सिंह : सभापति महोदय, आज मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और बोलने के पहले मैं सुनाना चाहता हूँ कि किसको सुनाऊ हाल ए दिल बेकरार का, बेबसी का मैं सबूत हूँ इस सरकार का, जो न जन में है न सदन में है, उसको बता रहा हूँ हाल ए बिहार का । महोदय, सबसे महत्वपूर्ण जो विभाग है स्वास्थ्य विभाग उसको गिलोटिन में कर दिया गया है । इससे स्पष्ट होता है कि सरकार स्वास्थ्य के प्रति कितनी चिंतित है । महोदय, इस बार जो है 45 लाख मिट्रिक टन के के एगेंस्ट में महज 30 लाख मिट्रिक टन ही धान की खरीदारी हुई,

क्यों खरीदारी हुई इसकी सरकार को समीक्षा करनी चाहिए । दूसरा एम0एस0पी0 अब तो केन्द्र में भी इन्हीं की सरकार हो गयी है और किसान लड़ रहे हैं और जिस तरह से किसानों के साथ ये जो लोकतंत्र की हत्या करनेवाली सरकार जो केन्द्र में बैठी हुई है और जो अपनी मांग उठानेवाले किसानों के साथ दमन कर रही है । मैं समझता हूँ कि अब तो कम से कम यहां विधान सभा से यह सरकार एम0एस0पी0 लागू करने की बात करे और किसानों के उपर जो दमन हो रहा है उसपर रोक लगाये, कील ठोका गया है महोदय, किसान मांग कर रहे हैं एम0एस0पी0 की मांग कर रहे हैं । जिसे सरकार ने वादा किया था उस वादा को लागू करने की मांग कर रहे हैं । महोदय, हम यह सरकार से मांग करते हैं कि 80 प्रतिशत खेती करनेवाले लोग बटाईदार हैं इसलिए उनको कम से कम बटाईदारी का पहचान पत्र दिया जाना चाहिए । महोदय, मैं स्वास्थ्य विभाग के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ । स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ यहां की आशा कर्मी हैं और पिछले बार 34 दिनों तक उनका हड़ताल चला था और हड़ताल के बाद सरकार ने यह समझौता किया था । उस समझौते में दो महत्वपूर्ण मांग उन्होंने मान लिया था उसको लागू करने की बात हुई थी । एक हजार पहले और 1500 कुल मिलाकर 2500 का मानदेय- शब्द जो पारितोषिक है उसको बदलकर के मानदेय करने की मांग सरकार ने समझौता के तहत मान लिया था और 18 महीना का जो बकाया है उस बकाया को भी देने के लिए सरकार ने समझौता पत्र में ये स्वीकार किया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसको आगे नहीं बढ़ाये, ये कैबिनेट में पास होने के बाद भी उसपर हस्ताक्षर नहीं किये । इसलिए हम मांग करते हैं कि उन आशा कर्मियों की जो मांग है समझौता हुआ है उसको तो कम से कम सरकार लागू करे । दूसरा हम कहना चाहते हैं यहां अभी पूरा बात कर रहे थे कि सरकार में स्वास्थ्य का बहुत अच्छा महज 17 महीना ही इधर आया, 17 महीना में अभी क्या होता है बच्चा पैदा ही होता है और 17 महीना में वह बेहतर से खा-पी नहीं सकता है, लेकिन 17 महीना में महागठबंधन की सरकार ने बहुत कुछ किया, लेकिन 18 सालों तक जो सरकार चलाते रहे हैं और 2005 से ये जो पीछे की बात करते रहते हैं मैं समझता हूँ कि समीक्षा होनी चाहिए । ये 18 सालों की समीक्षा होनी चाहिए । महोदय, महंगे प्राइवेट अस्पतालों को पूरा फलने फूलने के लिए छोड़ दिया गया है वहां गरीब लोगों के लिए 25 प्रतिशत भर्त्ती का जो प्रावधान है वह प्रावधान लागू नहीं है केवल कागज पर है और सरकार से पैसा ले लिया जाता है । यदि ऐसा है तो वेबसाइट पर उन अस्पतालों का लोड करें कि कितना गरीब लोगों का वहां इलाज कर रहे हैं । आइ0जी0आइ0एम0एस0 में जॉच और दवा मुफ्त देने की

घोषणा की गयी थी, लेकिन अभी तक ऐसा लागू नहीं हुआ है । महोदय, पटना एम्स में आइ0सी0यू0 कम है जिस वजह से जहां जरूरतमंद मरीज होते हैं उनको वहां से हटा दिया जाता है । महोदय, एम्स में ओ0टी0 इतना कम है कि महीनों दिन लग जाता है । ये जो एक्सीडेंटल रोगी होते हैं ट्रामा सेंटर के तहत उन लोगों को ऑपरेशन कराने में महीनों दिन लग जाते हैं। महोदय, बिहार में 35 जिले में पारा मेडिकल खोला गया है, तीन सत्र का नामांकन हो गया है लेकिन अभी तक एक भी ट्यूटर, डेमोन्सट्रेटर या लेक्चरर की बहाली नहीं हुई है । इससे स्पष्ट होता है कि ये सरकार स्वास्थ्य के प्रति कितना सचेत है । महोदय, हम स्वास्थ्य के मामले में कहना चाहते हैं यहां 1 हजार आबादी पर 5 बेड का प्रावधान है, लेकिन यहां मात्र 30857 बेड ही हैं ।

क्रमशः

टर्न–19/पुलकित/21.02.2024

श्री महा नंद सिंह (क्रमशः) : जबकि यहां जरूरत 6 लाख 42 हजार 501 बेड की जरूरत है और जो यह बजट पेश किया है उसमें उसका कोई जिक्र नहीं है, उसकी चिंता नहीं है कि कैसे इलाज हो । पूरी कमाई को लोग इलाज में झोंक दे रहे हैं । महोदय, इतना महंगा इलाज हो गया है इसलिए हम आपसे, सरकार से अपील करते हैं कि इसका थोड़ा सा ख्याल रखा जाए । महोदय, ये जो एम्बुलेंस और अस्पताल में आउटसोर्सिंग के जरिए उन मजदूरों को रखा जाता है, महज तीन हजार रुपया दिया है । छह हजार रुपया मासिक आमदनी को गरीबी रेखा से नीचे की बात कही गयी है लेकिन महज तीन हजार रुपया देकर उन मजदूरों को खटवाया जाता है । उन मजदूरों के नाम पर दस हजार रुपया को आउटसोर्सिंग के जो बिचौलिया है वे लेते हैं इसकी जांच होनी चाहिए कि किस नेता का, किस मंत्री का उसके साथ संबंध है । किन पदाधिकारियों का उससे संबंध है, जो यह लूट जारी है, जो लूट की जा रही है । इसलिए हम आप लोगों से इस सदन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यह जो सरकार हैं, ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, बहुजन की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं और अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चंडीगढ़ में लोकतंत्र के मेयर का जो चुनाव हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हुई है । लेकिन वे हत्यारे कौन है ? महोदय, हत्या करने वाले कौन है ? जिसको मीडिया से लेकर सत्ता में बैठे लोग चुप है इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट को बधाई देते हैं कि लोकतंत्र पर जिस तरह से हमला जारी है और उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय इधर आये थे ।

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : अब कंक्लूड कीजिए ।

श्री महा नंद सिंह : उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए इधर आये थे और उस लोकतंत्र को खत्म करने में जो लोग लगे हुए हैं, उधर चले गये हैं । के0के0 पाठक इनकी बात नहीं सुनते हैं और इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि वह आते-जाते थे, जो शान बनकर कभी और के0के0 पाठक जैसे लोग जो पदाधिकारी हैं उनके सामने वे हवा हो गये, देखते-देखते । क्या से क्या हो गये, कभी इधर थे और कभी उधर हो गये, देखते-देखते ।

सभापति (श्री भूदेव चौधरी) : कृपया समाप्त करें ।

श्री महा नंद सिंह : महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि आपके नगर विकास के मामले में कि अरवल में जो ड्रेनेज, वहां के पार्क का मामला है और अन्य तरह के जो मामले हैं।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

वहां विकास के मामले वे सभी बाकी हैं । इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से लेकर के सारा, उसको वहां लागू किया जाए । निचले स्तर के जो अस्पताल हैं उनको ठीक किया जाए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिए ।

श्री महा नंद सिंह : महोदय, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जो मामला है, उस मामले में भी भाजपा एक शब्द नहीं बोल रही है । यह लोकतंत्र की हत्या है और उसको बचाने की कोशिश चल रही है इसलिए हम यह मांग करना चाहते हैं कि सदर अस्पताल को बेहतर बनाया जाए ताकि वहां भी आई0सी0यू0 की व्यवस्था हो । वहां डॉक्टर के रहने के लिए व्यवस्था हो ।

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए । माननीय सदस्य श्री अनिल कुमार ।

श्री महा नंद सिंह : ताकि डॉक्टर लोग वहां काम कर सकें । हम यह मांग करते हैं कि ए0पी0एस0सी0 से लेकर के सब सेंटर को भी व्यवस्थित किया जाए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अनिल कुमार जी आपका समय तीन मिनट है ।

श्री महा नंद सिंह : हम मांग करते हैं कि मरीजों का बेहतर इलाज हो ।

श्री अनिल कुमार : अध्यक्ष महोदय, आज मुझे सहकारिता विभाग के बजट के समर्थन में अपनी बात रखने का मौका मिला है । उससे पहले मैं चाहता हूँ कि बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली एन0डी0ए0 सरकार में विकास कार्यों की गति हमेशा तेज रही है और आगे भी जारी रहने वाली है । यह विश्वास हमारा और राज्य की जनता का भी है । सहकारिता विभाग वर्ष 2005 से राज्य में बेहतरीन कार्य कर रहा है और वर्ष 2005 के पूर्व सहकारिता विभाग को बिहार की जनता जानती भी नहीं थी, इस रूप में सिर्फ जानती थी कि पटना में

विस्कोमान है, एल0डी0बी0 बैंक है, कॉपरेटिव बैंक है । गांव से जुड़ा हुआ कोई मामला नहीं था । पहले पैक्स के बारे में कोई जानता नहीं था लेकिन आज पूरे गांव में अभी धान की फसल के समय, गेहूं की फसल के समय गांव-गांव में जो पैक्स हैं, पैक्स के पास हजारों की भीड़ देखिए तो किसानों और मजदूरों की भीड़ वहां पर पैक्स के गोदाम के पास खड़ी है । अपने ट्रैक्टर लेकर, अपने ट्रक लेकर, किसान अपनी धान उगाही करके, गेहूं के समय ये जो बातें हैं, वर्ष 2005 के बाद ही इस बिहार में बेहतरीन स्थिति पैदा हुई हैं, सहकारिता विभाग को लोग जानने लगे हैं कि सहकारिता विभाग किसानों के लिए हैं । किसानों की समृद्धि के लिए है, किसानों की उन्नति के लिए है, किसानों के विकास के लिए हैं और जन-जन में आज बिहार में हमारे मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को जानते हैं कि इन्होंने एक ऐसी स्थिति सहकारिता विभाग में पैदा की जो गांव-गांव में किसानों को समृद्ध और उन्नत बनाने का कार्य किया है । आज पहले पैक्स में, पूरे बिहार के किसानों का पैक्स, आज चारों ओर गोदामों के बनने का सिलसिला जारी है । गोदाम बने हुए भी हैं सहकारिता विभाग से इस साल 460 गोदामों का निर्माण होना है । इसके पूर्व भी भारी मात्रा में गोदामों का निर्माण हुआ है इस साल 969 विभिन्न पदों पर बहाली भी होने वाली है । इसमें कई पदों पर बहाली प्रक्रियाधीन भी है । पहले फेज में 4477 पैक्स का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है, अगले चरण में 1601 पैक्सों में कम्प्यूटरीकरण होगा । जिला प्रमण्डलीय स्तरीय कार्यालयों को एक छत के नीचे लाने के लिए सहकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है । 17 सहकार भवन का निर्माण पूरा हो चुका है । शेष 2024-25 में पूरे होने वाले हैं । राज्य में स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो गजब की स्थिति लगती है । लोग इस बात को बोलते हैं कि वर्ष 2005 से पूर्व बिहार में स्वास्थ्य की स्थिति क्या थी ? जर्जर थी, हम लोग भी वर्ष 2005 से विधायक हैं । वर्ष 2005 के पहले हमलोग इलाके में कहीं जाते थे तो अपने क्षेत्र की बात करें तो टिकारी में ही जो अस्पताल हैं उसमें ठेला पर मरीज आते थे । कहीं एम्बुलेंस का पता नहीं था, आज अपने ही अस्पताल की हम बात करें तो टिकारी में कम से कम चार एम्बुलेंस है । आज सुबह जब हम अपने क्षेत्र से गुजरते हैं तो वहां पर खड़े होकर देखते हैं कि 250 की संख्या में मरीज वहां पर अपनी रसीद कटवा रहा है और पूरी दवा लेकर खड़ा है । जिस तरह से अभूतपूर्व काम स्वास्थ्य विभाग में हुआ है । प्रखण्ड स्तर पर हो, अनुमण्डलीय स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो पहले न कहीं एम्बुलेंस थी और न कहीं चिकित्सक था, सारा राम भरोसे बिहार में काम हो रहा था । आज तो गजब स्थिति है आप जाकर पी0एम0सी0एच0 देखिए,

समाचार पत्र में भी पढ़ते होंगे विश्वस्तरीय अस्पताल । गजब की स्थिति है, सचमुच में देश के अंदर इतना बड़ा कोई अस्पताल दूसरा नहीं बना होगा जो पी0एम0सी0एच0 में बन रहा है । इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा-निर्देशन में जो कार्य हुआ है वह अकल्पनीय है । इसलिए हमारा सरकार से आग्रह हैं और साथ ही, हम कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं एक तो सरकार ने जो कल निर्णय लिया है कैबिनेट से 58 लाख परिवारों को 5 लाख तक मुफ्त कैशलैश इलाज जिस तरह से भारत सरकार द्वारा होता था, बिहार सरकार ने भी निर्णय लेने का काम किया है । यह भी बिहार की जनता के लिए सबसे लोकप्रिय निर्णय लिया गया है । इसलिए हम स्वास्थ्य विभाग में भी कुछ अपने क्षेत्र का भी मामला रखना चाहते हैं । टिकारी में कुछ अस्पताल हैं जहां सदियों से भवन नहीं बना है, किशंडा है, भोरी है, हाथी है, देवरा है इन जगहों पर जगह उपलब्ध है, भवन बनाने का कार्य किया जाए ।

अध्यक्ष : अब कंक्लूड करिये ।

श्री अनिल कुमार : महोदय, कुछ है और कुछ तो बनाना है । 75 प्रतिशत अस्पताल बन गये हैं, कुछ बनने बाकी हैं, उसके लिए बोल रहे हैं ।

अध्यक्ष : अनिल जी, इधर देखकर बोलिये ।

श्री अनिल कुमार : अध्यक्ष महोदय, नगर विकास विभाग में भी अभूतपूर्व काम हुआ है । वहां जो कार्य हुआ है, पूरे बिहार में, पूरे पटना में से उठाइये ।

(क्रमशः)

टर्न-20/अभिनीत/21.02.2024

..क्रमशः..

श्री अनिल कुमार : महोदय, पूरी राजधानी में सुबह-शाम हजारों जनता के घुमने के लिए बहुत बढ़ियां तरीके से पार्क का निर्माण किया गया है । शाम में निकलिए घुमने के लिए तो देखने में लगता है कि गजब तरह की पटना है..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त करिए ।

श्री अनिल कुमार : बंबई की तरह पटना में यह कार्य किया गया है । इसी तरह उद्योग के क्षेत्र में भी, अन्य क्षेत्रों में भी कई कार्य कराये गये हैं । जिस तरह से उद्योग के क्षेत्र में पूरे बिहार में जो काम हुआ है वह अविस्मरणीय है । हम अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं। नये नर्सिंग कॉलेज खोलने हेतु जो मापदंड निरूपित किये गये थे उसमें जी0एम0 तथा बी0एस0सी0 नर्सिंग के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने की जो अपरिहार्यता थी उसका पालन नहीं किया गया है । उसकी जांच की हम मांग करते

हैं और उसकी जांच होनी चाहिए । सरकार से आग्रह है उन विषयों को हम लिखकर लाये हैं, आपसे आग्रह है कि इसको प्रोसीडिंग्स का पार्ट बना दिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है, बैठ जाइये ।

माननीय सदस्य श्री अजय कुमार । आपके पास दो मिनट समय है ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, सहकारिता विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हूं । मैं यह बात साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि बजट में जो प्रावधान दिया गया, जरा इस बात पर गौर करना चाहिए कि सत्ता पक्ष के ही लोग बोल रहे थे कि धान की अधिप्राप्ति का लक्ष्य था 45 लाख मैट्रिक टन और खरीद हुआ 30 लाख मैट्रिक टन । वाट इज रीजन ? कारण इसके क्या हैं ? इसको टटोल कर देखने की जरूरत है । मार्केट में जो रेट है, ओपेन मार्केट में जब 18 सौ रुपये क्विंटल धान बिकेगा तो आपका सवा 19 सौ रुपये क्विंटल लोग कैसे खरीदेगा, यह तो सीधी बात है । मैं समझता हूं कि इसके बारे में अगर सरकार चाहे तो केवल अपनी टीम को भेजकर यह पता करे कि वहां सहकारिता विभाग कैसे काम करती है और किस तरीके से वहां जितने भी किसान उत्पादित वस्तु होते हैं, फसल, सब पर वहां पैक्स के माध्यम से धान और भी जो उत्पादन होता है वह खरीद होती है । वहां धान के ऊपर आपको मैं बताना चाहता हूं, केरल के अंदर 9 हजार रुपये प्रति एकड़ अनुदान के तौर पर दिया जाता है इसलिए वहां धान की फसल अच्छी होती है और किसान की हालत अच्छी होती है ।

सर मैं बताना चाहता हूं, कृषि यंत्र सहकारिता विभाग ने गांवों में जो पैक्स है उसको खरीद कर दिया है लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है । बिना रजिस्ट्रेशन कराये हुए किसी गाड़ी को चलाने का क्या बिहार सरकार इजाजत देती है ? जरा पता तो कर ले सहकारिता विभाग, आपने ट्रैक्टर दिया और दूसरे कृषि यंत्र दिए किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ । नतीजतन आपके करोड़ों रुपये खर्च होकर भी वे पड़े हुए हैं । दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि आपके पी0डी0एस0 जो हैं, आपने दिया था कि सभी पैक्स को पी0डी0एस0 दिया जायेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ । मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं कि समस्तीपुर के विभूतिपुर के पैक्स की उसने मांग की थी, लिखकर आवेदन दिया था उसको नहीं दिया गया । तीसरी बात मैं हेल्थ के बारे में कहना चाहता हूं । हेल्थ के बारे में बहुत लंबी बयान लोग दे रहे थे लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार इस बात का जवाब दे कि आपने जिला अस्पताल में हेल्थ के लिए वेंटिलेटर आपने दिया था कोरोना काल में लेकिन वह वेंटिलेटर आज खाट बनकर बैठा हुआ, चूंकि आपने तकनीशियन वहां नहीं दिया । बिना तकनीशियन का कैसे चलेगा वेंटिलेटर ? जब

जिला अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं होगा तो किसके सहारे आप छोड़े हुए हैं ? पीठ जितना डॉक्टर साहब थपथपा लीजिए लेकिन बिहार की जनता देख रही है और हिसाब पूछेगी । हिसाब पूछेगी और आपको भी हम कहना चाहते हैं कि कल ही सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, दिल को टटोल कर देखिए क्या आपने जनतंत्र को हाईजैक करने की कोशिश की थी । चण्डीगढ़ में मेयर के चुनाव को आपने हाईजैक किया था । जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार है क्या ? इलेक्टोरल बॉण्ड के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया और उस रूलिंग के आधार पर कोई तो जवाबदेही ले । जवाबदेही लेनी पड़ेगी, बोलकर सिर्फ चले जाने से नहीं होगा ।

एक अपील है मेरा आपदा विभाग से, क्या आपदा में जितनी भी बातें आती हैं, शीत लहर को भी बिहार के अंदर, गरीब लोग ठंड में ठिठुर-ठिठुर कर मर जाते हैं । क्या वह आपदा नहीं है ? आपदा की श्रेणी में गहरे ठंड से मरने वाले लोगों को भी उसमें जोड़ना चाहिए...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कंक्लूड कीजिए ।

श्री अजय कुमार : महोदय, मैं कंक्लूड कर रहा हूं । मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर जो आबादी है, आबादी के हिसाब से कितने लोगों पर केन्द्रीय स्वास्थ्य विभाग ने जो तय किया है डॉक्टर होना चाहिए, क्यूबा में एक सौ व्यक्ति पर एक डॉक्टर है लेकिन बिहार में कितने व्यक्ति पर डॉक्टर है ? मैं जहां से आता हूं विभूतिपुर से 21 डॉक्टर हैं, 2 लाख पर 21 डॉक्टर हैं यानी बिहार में तकरीबन आठ हजार लोगों पर एक डॉक्टर है । क्या आठ हजार लोगों का इलाज एक डॉक्टर कर सकता है ? नहीं कर सकता है । यह नाइंसाफी है, इसलिए यदि बिहार के स्वास्थ्य विभाग को ठीक करना चाहते हैं तो डॉक्टर के जितने पद खाली पड़े हुए हैं उस पर अविलंब भर्ती कीजिए । जितने भी रिक्त पद हैं सब पर आप भर्ती कीजिए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिए ।

श्री अजय कुमार : मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सूर्यकांत पासवान । दो मिनट ।

श्री सूर्यकांत पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, सहकारिता, 2000 से 2005 तक जो सहकारिता थी, उस समय बैंक चलता था, सहकारिता पैक्स गोदाम था उसमें बैंक चलता था और गांव के किसान उसमें अपने बचत का पैसा रखते थे और उससे खेती करते थे लेकिन आज उस सहकारिता से बैंक नदारद है, वह समाप्त हो गया । महोदय, स्वास्थ्य की बात, आज सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में परिवार कल्याण कार्यकर्ता को उच्चतर पद पर

प्रमोशन दिये जाने हेतु दो बार वरीयता सूची, अधिसूचना सं0-19300, दिनांक-13.10.2023 और अधिसूचना सं0-636, दिनांक- 10.01.2024 के माध्यम से निर्गत की गयी परंतु अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ है । महोदय, यह हाल है सरकार का, महोदय, स्वास्थ्य विभाग की चर्चा हमारे कई, बैठे हुए हैं हमारे सम्मानित डॉक्टर साहब, यह सच नहीं है कि बिहार के अंदर ठेका पर जो डॉक्टर को दिया गया है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो कर्मचारी दिये गये हैं वहां संख्या है आठ, आठ सफाई कर्मी सफाई करने के लिए दिया गया है, पैसा उनको दिया गया है लेकिन उपस्थित रहते हैं एक कर्मचारी, महोदय, इसकी जांच होनी चाहिए । महोदय, मैं ग्रामीण विकास विभाग की बात करना चाहता हूं, बैठे हुए हैं हमारे श्रवण बाबू...

(व्यवधान)

श्री सूर्यकांत पासवान : गिलोटिन हो रहा है ? महोदय, हम लिख लिए हैं । पंचायती राज विभाग है, पंचायती राज विभाग है महोदय..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब कंक्लूड कीजिए ।

श्री सूर्यकांत पासवान : मैं कहना चाहता हूं डंडारी, मेरे विधान सभा, बेगूसराय जिला के बखरी विधान सभा अंतर्गत डंडारी प्रखंड है, उसमें हमारा एक पंचायत है कटरमला उत्तरी पंचायत जिसको पंचायत समिति डंडारी से पास करके जिला पदाधिकारी बेगूसराय को दिया गया है कि उसको नावकोठी प्रखंड में सम्मिलित किया जाय । यह हमारा प्रस्ताव है जिससे वहां के हमारे जो पंचायत के लोग हैं उनको 15 किलोमीटर घूम कर, नदी पार करके डंडारी ब्लॉक जाना पड़ता है, इसलिए माननीय मंत्रीजी से हम आग्रह करेंगे कि इसको डंडारी प्रखंड से हटाकर नावकोठी प्रखंड में किया जाय । महोदय, समाज कल्याण भी आज है । आज हमारे आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका 72 दिनों तक अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल में गयी थी । महोदय, उनको उस अवधि का मानदेय मिलना चाहिए । यही हम सरकार से आग्रह करते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिए ।

श्री सूर्यकांत पासवान : महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अख्तरूल ईमान ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री भारत भूषण मंडल जी ।

टर्न-21/हेमन्त/21.02.2024

श्री भारत भूषण मंडल : अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा लायी गयी अनुदान मांग पर विपक्ष की ओर से दिये गये कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

अध्यक्ष महोदय, सहकारिता विभाग और बिहार सरकार का कृषि रोड मैप, दोनों किसान की जिंदगी बदलने में, किसान को खुशहाल करने में, उनको आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने में पूरी तरह विफल रहा है । आज किसानों की क्या स्थिति है देश में ? आपको मालूम है कि किसान आज घोर कर्जे के तले डूबा हुआ है । आज किसान रोज आत्महत्या करने को विवश है । जिस किसान के बलबूते यह देश आज खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर बना है, आज दिल्ली में पूरे सिंघु बॉर्डर पर लाखों-लाख किसान पहुंच गया है । किसान की क्या मांग है ? जो मोदी सरकार ने वादे किये थे, भाजपा नीति सरकार, भाजपा नीति गठबंधन ने, जो किसानों से वादा किया था कि हम किसानों की आर्थिक आमदनी दुगुनी करेंगे, किसानों की जिंदगी में खुशहाली लायेंगे । आज उन सपनों का क्या हुआ ? किसान को दिल्ली जाने से रोकने के लिए, यह किस प्रकार की तानाशाह सरकार है, दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में इस तरह का उदाहरण अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है । किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए उनके रास्ते में, इस डेमोक्रेटिक इंडिया में, कील गाड़ी गयी, उनके रास्ते में बेरिकेडिंग की गयी, मजबूत दीवारें खड़ी की गयी और जिस प्रकार से हिंदुस्तान के किसान के साथ, अन्नदाता के साथ जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से पेश आ रही है, आने वाले दिनों में भाजपा नीति गठबंधन सरकार की खैर नहीं है । किसानों ने चुनौती दी है कि यदि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया, यदि किसानों की एम0एस0पी0 पर कानून बनाकर गारंटी नहीं दी गयी तथा उनकी दूसरी मांगों को नहीं माना गया, तो इस बार किसान मोदी सरकार को उखाड़े बिना दिल्ली से लौटने वाले नहीं हैं । बिहार की सरकार के बारे में तो मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता । मैं यह मानता हूं कि यह सिद्धांतहीनता का अमृतकाल चल रहा है । ऐसी सिद्धांतहीनता इस देश में इससे पहले कभी देखी नहीं गयी । हॉर्स ट्रेडिंग के आधार पर सरकार गिरायी जा रही है । सरकार को अस्थिर किया जा रहा है । पैसे के बल पर कोर्ट को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है और चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जिस तरह से लोकतंत्र का गला दबाया गया, लोकतंत्र की हत्या की गयी, चंडीगढ़ में वह देखने लायक है । मित्रो, मोदी सरकार के रहते न तो संविधान की आत्मा बचेगी, न लोकतंत्र बचेगा । इसीलिए मैं सदन के माध्यम से हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों से अपील करता हूं कि इस सरकार के रहते न तो बहुजन का कल्याण होगा, न किसानों का कल्याण होगा, न कामगार का कल्याण होगा, किसी भी कमेरे लोगों का भला भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार नहीं कर सकती ।

अध्यक्ष : मंडल जी, बिहार के सहकारिता विभाग पर भी बोलना है । बिहार पर भी आइये ।

श्री भारत भूषण मंडल : बिहार का सहकारिता विभाग किसानों से जुड़ा हुआ है । इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि क्या हालत हुई, राजनैतिक भ्रष्टाचार की बात मोदी जी बड़े-बड़े शब्दों में कहा करते थे । राजनैतिक भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर । आपको मालूम है कि जो चंदा आता है औद्योगिक घराने से, बड़े पूंजीपति घराने से, कॉर्पोरेट हब से, साढ़े छः हजार करोड़ रुपये से भी अधिक चंदा एक पार्टी को मिला है, वह भारतीय जनता पार्टी को मिला है । जब इसका खुलासा होगा, देश ही नहीं विदेशों से आया है । यह भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है ? जो भी नेरेटिव भारतीय जनता पार्टी नीति सरकारों द्वारा हो रहा था, वह एक-एक करके ध्वस्त हो रहा है । पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है । पूरे देश में इतनी भ्रष्ट सरकार आजादी के बाद कभी नहीं थी । इसीलिए मित्रों, हम कहना चाहते हैं कि यह ठीक बात है कि सरकारें अदलती-बदलती रहती हैं, लेकिन जो काम तेजस्वी यादव ने..

(व्यवधान)

अरे जरा सुनिये भाई । रेणु देवी जी को तो उप मुख्यमंत्री पद से भी हटा दिया । भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं के साथ क्या न्याय कर रही है, आप सभी को मालूम है । मैं कहना चाहता हूं, आप इस बात को ध्यान से सुनिये । सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन लोगों के मुद्दे प्रखरता से सामने लाते हैं । आज क्या हो रहा है बिहार में ? तेजस्वी यादव ने 17-18 महीने में पूरे बिहार के और देश के राजनैतिक विमर्श को बदलकर रख दिया । जो काम 17 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार नहीं कर पायी, रोजगार देने का सवाल...

(व्यवधान)

अरे भाई साहब, बैठिये, ध्यान से सुनिये । तेजस्वी यादव जो काम कहते थे, महागठबंधन के मुखिया कि कहां से लाओगे पैसे, कहां से लाओगे रोजगार, तेजस्वी यादव ने अपनी कर्मठता के बूते पांच लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया । पूरे देश और दुनिया में तेजस्वी यादव की कर्मठता की मिसाल दी जा रही है । इसीलिए जो भी विभाग तेजस्वी यादव को मिला, उस विभाग ने आगे बढ़कर बिहार के लोगों के कल्याण के लिए काम किया । न केवल पांच लाख नौकरी दी गयी, बल्कि आरक्षण का दायरा, जो देश में कहीं नहीं है, 75 प्रतिशत आरक्षण का दायरा बढ़ाया, जातीय गणना करायी और गरीब लोगों के लिए खजाने का द्वार खोल दिया।

(व्यवधान)

आप घबराइये नहीं, आप जाने वाले हैं । अधिक दिनों तक देश की जनता आपको बर्दाश्त नहीं करेगी । इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के रहते इस मुल्क का भला नहीं हो सकता और धीरे-धीरे इस देश की जनता और बिहार की जनता इसको समझने लगी है । इसलिए हम कहना चाहते हैं कि केवल जुमलेबाजी से सरकार नहीं चलती । यह विकसित बिहार का नारा देने वाले लोग, जय बिहार का नारा देने वाले लोग, जी0डी0पी0 का चमत्कार का दावा करने वाले लोग, बिहार आज क्यों अंधकार में चला गया है । जिन लोगों के हाथ में आज बिहार की कमान है, भारतीय जनता पार्टी जिस गठबंधन सरकार के पीछे रहेगी वह कोई अच्छा काम आम लोगों के हित में नहीं कर सकती । इसलिए मैं इस सरकार को एक नेक सलाह देना चाहता हूं कि जितना जल्द हो सके भारतीय जनता पार्टी से किनारा करिये, नहीं तो बिहार के विकास को ऊंचाइयों पर नहीं ले जाया जा सकता है । इसीलिए हम कहने वाले हैं, आप लोग ध्यान से सुनिये कि सरकार तभी काम कर सकती है, जब उसको समर्थन देने वाले लोग सकारात्मक राजनीति करें । आज तो सारा बिहार और सारा देश तेजस्वी यादव के नेतृत्व कौशल की सराहना कर रहा है । अभी तो सभाएं हो रही हैं, नीतीश कुमार जी की नहीं, तेजस्वी यादव की । लाखों-लाख लोग उनकी सभाओं में जा रहे हैं । इसीलिए हम कहने आये हैं, जो अर्बन डवलपमेंट का सवाल है, क्या हो रहा है अर्बन डवलपमेंट में, जो मलिन बस्ती है, जो आश्रय स्थल है चाहे स्थायी हो, चाहे अस्थायी हो, चाहे और दूसरे शेल्टर होम हों उसकी स्थिति खराब हो रही है । वहां रहने वाले लोग नारकीय जीवन जीने को अभिशप्त हो रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि यह जो सरकार है यह लोगों से किये गये वादे के खिलाफ काम कर रही है । इन्हीं चन्द बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । इंकलाब जिंदाबाद ।

अध्यक्ष : सुनील जी, शांत रहिये, बैठिये । भारत भूषण जी, हम तो आपको और बुलवाना चाहते थे, आप बैठ गये । विषय खत्म हो गया आपका, रहा नहीं ?

अखतरूल ईमान साहब । आप कहां चले गये थे, हमने आपको पुकारा था ।

श्री अखतरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन मशवरे सिर्फ देना चाहूंगा, मेरे पास तो समय ही नहीं है । किसानों को पहले 300 रु0 प्रति क्विंटल बोनस दिया जाता था, अब नहीं दिया जा रहा है, उसको दिलाया जाय, कैरेज कोस्ट बढ़ाया जाय, पैक्स के कमीशन को बढ़ाया जाय और मक्का की फसल काफी कैश क्रॉप है और सीमांचल में काफी पैदावार है और उसकी एम0एस0पी0 निर्धारित हो, उसके लिए

अनुशंसा जाय भारत सरकार को । सर, देश पंचायत पर टिका हुआ है, ग्रामीण है । मुखिया का, सरपंच का, जिला परिषद के मेम्बरों का, उनका जो भत्ता है वह बढ़ाया जाय । अमौर पंचायत के लायक है, आपने उसे नगर पंचायत बना दिया और आज तक वहां पर जे0ई0 नहीं है, सारा काम वहां पर रुका हुआ है, वह काम वहां पर करवा दिया जाय । प्रखंड अमौर एवं बैसा में आपदा पीड़ित हमारे यहां काफी घनी नदियां हैं और काफी लोगों के घर कटे हैं सर । महानंदा, डोनक, कनकई, मेची, परमान लगभग ढ़ाई हजार से ज्यादा लोग आपदा प्रभावित हैं । उनको न तो आपदा की राशि मिली, न उनको भूमि मिली घर बनाने के लिए । मात्र 40 से 50 आदमी को मिला है, जबकि 2500 से ज्यादा लोग वहां पर विस्थापित हैं सर ।

(क्रमशः)

टर्न-22/धिरेन्द्र/21.02.2024

(क्रमशः)

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, संवेदनशील सरकार है तो संवेदना दिखनी चाहिए और सीमांचल के साथ तो वह इलाका सबसे गरीब है, आँकड़े भी कह रहे हैं । आपकी तवज्जो चाहूँगा, अस्पतालों की हालत हमारे यहाँ अच्छी नहीं है, वहाँ पर डॉक्टर दिये जाये। खासकर अमौर अस्पताल का मकान जर्जर है, रहने के लायक नहीं है, मतलब मरीज का ईलाज क्या करेगा डॉक्टर, डॉक्टर ही घबरा रहा है कि कब छत हम पर गिर पड़े, वह मकान बनवा दिया जाय । सर, प्रखंड बायसी में, हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है और वहाँ एक भी आउटडोर स्टेडियम नहीं है, एक स्टेडियम बनवा दिया जाय और जहाँ तक को-ऑपरेटिव सेक्टर का मामला है, पूरे तौर पर चरमराया हुआ है । किसान अपनी फसल का 25 प्रतिशत भी नहीं बेच पाता है, किसानों को उस वक्त की खरीददारी जो हो रही है और जो पेमेंट का मामला है, बड़ा लफड़ा उसमें लगा हुआ है, नतीजा यह होता है कि महाजनों के पास बेच देता है । बारह सौ, पंद्रह सौ में वह धान बेच देता है और उसके बाद उन्नीस सौ रुपया वाला मामला आता है तो वह नहीं बेच पाता है तो इस तरह की दिक्कतें किसानों की हैं और आप बड़े संवेदनशील हैं, मैं समझ रहा हूँ कि आप सरकार को निर्देशित करेंगे कि को-ऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ावा दिये बगैर बिहार के किसानों का भला नहीं होने वाला है और बिहार में चूंकि किसान ही सब कुछ है, आपका जो घरेलू उत्पाद है, उसका सबसे बड़ा स्रोत तो किसान है, यहाँ पर कल-कारखाने नहीं हैं तो किसानों की हालत को बेहतर बनाने के लिए को-ऑपरेटिव सेक्टर को चुस्त और दुरूस्त किया जाय बल्कि पिछले दिनों में जो मार्केटिंग को खत्म कर दिया आपने तो

मार्केटिंग व्यवस्था को खत्म करने से बड़ा नुकसान हुआ है । एम॰एस॰पी॰ का लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है, किसानों को बड़ी दिक्कत हो रही है और खासकर बटाईदार जो लोग हैं, बटाईदार पैदावार कर रहे हैं तो बटाईदार वालों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, वे फसल भी बेचना चाहते हैं तो फसल बेचने में उनको दिक्कत होती है, सी॰ओ॰ के यहाँ उसका कागज नहीं बन पाता है और एक बात और कहूँगा कि सरकारी चाकर मिले, सुविधा मिले उनको, मर जाय तो उनकी पत्नी को पेंशन मिले और इस राज्य में जो किसान अनाज उपजाये तो उसके लिए कुछ भी सुविधा नहीं हो, किसान खेतों में काम करता हुआ मरे तो उसका इंश्योरेंस होना चाहिए और एक बात मैं और कहूँगा जो हमारा कल-कारखाना जल जाय तो आप उसको इंश्योर करते हैं और उसको इंश्योरेंस का पैसा मिलता है और हमारी जमीन जब कट जाती है तो बिहार सरकार उसमें जल स्रोत के जरिये से आप उगाते हैं, आप बालू निकालते हैं, मछली पालते हैं, कश्ती चलाते हैं, मसूल-वसूल करते हैं तो हमारी भूमि का भी इंश्योरेंस होना चाहिए चूंकि कटाव रोकना सरकार का काम है इसलिए आपदा से बचाया जाय । आपने हमें समय दिया है, मैंने कोई सरकार को चिढ़ाने वाली बातें नहीं की हैं, वे सारी बातें हमने कही हैं जो बिहार की जनता की बुनियादी जरूरत है और जिनका सहकारिता से बड़ा ताल्लुक है । हम आशा करते हैं कि यह सरकार अपनी संवेदनशीलता का सबूत देगी और सीमांचल का कटाव एवं विस्थापित लोगों को उसका आपदा के अनुसार जो उनको राशि मिलनी चाहिए सरकार देगी और अभी सर, सिर्फ आकलन करा लिया जाय कि किशनगंज में, पूर्णियाँ में, कटिहार में, अररिया में जो लोग नदी में डूब कर मरें, उनको रुपये मिलने चाहिए और तीन-तीन साल हो गए, पाँच-पाँच साल हो गए उनको राशि नहीं मिली । जिन लोगों का घर जल जाता है, उनके पास कुछ नहीं बचता है...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिये ।

श्री अखतरूल ईमान : सर, उनको भी दिलवा दिया जाय । आपने समय दिया इसके लिए बड़ा आभारी आपका ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राणा रणधीर जी ।

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय, एक तो मुझे अभी सूचना मिली । सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद और बधाई देता हूँ और हम सब के लिए बड़ा ऐतिहासिक क्षण है, गौरव का क्षण है कि भारतीय जनता पार्टी का एक आम कार्यकर्ता जो युवा मोर्चा का कभी अध्यक्ष रहा हो, वह आज बिहार विधान सभा के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा

है तो आपसे हम सब लोग लगातार कुछ-न-कुछ सीखते रहे हैं तो आप ही की पंक्तियों से मैं आप ही का स्वागत करता हूँ फिर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा-

जहाँ रहेंगे वहीं रौशनी फैलायेंगे,

बिल्कुल आपके लिए समर्पित है अध्यक्ष महोदय कि-

जहाँ रहेंगे वहीं रौशनी फैलायेंगे,
किसी चिराग का कोई मकान नहीं होता ।

और आप ही की पंक्तियाँ रहीं कि-

थके हैं न कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है,
जज्बा है परिवर्तन का, जिंदगी में इसीलिए सफर जारी है ।

और आज उसी के साथ हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं अध्यक्ष महोदय कि सहकारिता विषय, स्वास्थ्य और बिहार की सरकार, भारत की सरकार । अध्यक्ष महोदय, 75 वर्ष आजादी के हो गए और इन 75 वर्षों में बिहार में 17 चुनाव हुए हैं और करीब-करीब 26 मुख्यमंत्री बने हैं और एक यात्रा जो हम लोगों ने शुरू की बिहार की, वह एक क्रांतिकारी परिवर्तन, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने, हम सब साक्षी हैं कि बिहार ने क्रांतिकारी परिवर्तन देखा है । सहकारिता के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में किस तरह से चौथा कृषि रोड मैप आया, सहकारिता जिसको आम लोगों तक पहुँचाने का काम किया गया, किस तरह से प्रधानमंत्री जी की जो सोच रही कि सहकारिता जिसके लिए हम सब मानते हैं और मैं तो चम्पारण की धरती का रहने वाला हूँ अध्यक्ष महोदय, जहाँ गांधी बाबा आयें और दीन दयाल उपाध्याय जी की जो, उनका जो दर्शन रहा एकात्व मानववाद का, जिन्होंने कहा और इसमें पूरा सदन इस बात से इत्तेफाक रखता है कि-

तेरे शहर का पेट मेरी गाँव की मिट्टी से पलता है,
गौरतलब रहे कि देश अपना गाँव में बसता है ।

और इस बात को चरितार्थ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक दूरदृष्टि रखी है, एक विजन रखा है और किस तरह से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, किस तरह से किसान भाइयों की आमदनी बढ़े, गाँव में रहने वाले लोगों की आमदनी बढ़े, उसकी चिंता करते हुए आज जिस तरह से सहकारिता विभाग धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य लगातार बढ़ा रहा है । अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2005 के समय कितना लक्ष्य था, आज 45 लाख एम॰टी॰ लक्ष्य है और जिसमें 30 लाख एम॰टी॰ धान की अधिप्राप्ति हुई, किस तरह से....

(व्यवधान)

किस तरह से आप देखते जाइये न, जिस तरह से मैंने कहा कि जो पॉजिटिव यात्रा शुरू है, उसको भी हम हासिल करेंगे । किस तरह से हमने गाँव-गाँव तक बिजली पहुँचाने का काम किया, गाँव में बिजली पहुँचाने का काम किया, खेतों तक सिंचाई पहुँचाने का काम किया और कल जल संसाधन विभाग पर चर्चा थी और किस तरह से एक विजनरी मुख्यमंत्री ने, एक विजन के तहत, एक दृष्टि के तहत किस तरह से जल स्रोतों को, पहले जल स्रोतों की जानकारी लेना और उस जानकारी के बाद उन जल स्रोतों को विकसित करना और उस तरह से गाँव में कैसे खेती किसान भाइयों को उनके सिंचाई का साधन, उनको खेती के लिए अलग से बिजली उपलब्ध कराना और किस तरह से एक व्यवस्थित तरीके से हमारे पैक्सों को जिस तरह से कॉमन सेंटर के रूप में डेवलप करने का जो विचार आया है कि कॉमन सेंटर हो गाँव में, किसान भाइयों को किस तरह से कृषि यंत्र बैंक, किसानों की चिंता की गई कि किस तरह से किसान भाइयों की खेती बढ़े, उनको हर तरह का सपोर्ट सिस्टम मिले और जो सबसे बड़ी बात सरकार के द्वारा की गई कि खेती में पशुपालकों को भी, चाहे गौ पालन करने वाले, बकरी पालन करने वाले, मुर्गी पालन करने वाले, डेयरी को, पशुपालकों को भी के॰सी॰सी॰ ऋण की सुविधा, जिसकी चिंता सभी माननीय सदस्य करते रहे हैं, वह भी सरकार ने सुनिश्चित करने का काम किया और के॰सी॰सी॰ ऋण की जो सुविधा है, वह न केवल खेती करने वाले बल्कि पशुपालकों को भी, डेयरी के लोगों को भी और फिर जो गोटरी, वहाँ तक भी जाने का काम किया हुआ है, जिस तरह से माइनूट लेवल पर और जिस तरह से जीविका के माध्यम से एक करोड़ तीस लाख हमारी बहनें इसमें आत्मनिर्भर होने का काम कर रही हैं और फिर उनके स्वास्थ्य की चिंता, किस तरह से आम आदमी के स्वास्थ्य की चिंता चूंकि हम सब इस बात में विश्वास करते हैं कि गाँव से ही ताकत मिलती है, जब तक हम गाँव के लोगों को समृद्ध नहीं करेंगे, भारत का विकास माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब तक और केवल कहा नहीं उस पर योजना-रचना बनाकर काम भी किया । किस तरह से किसानों की आमदनी बढ़े, अभी एक डाटा हमारे माननीय सदस्य, कोई मित्र बता रहे थे कि एक लाख तिहत्तर हजार करोड़ की ऋण माफ हुई है तो किसान सम्मान निधि के माध्यम से तीन लाख करोड़ के लगभग पैसा किसान भाइयों के खातों में जाने का काम हुआ है दस वर्षों के अंदर में । किसानों की चिंता, महिलाओं की चिंता, गाँव में रहने वाले गरीब आदमी की चिंता और नौजवानों की चिंता, क्योंकि भारत जो है वह एक युवा राष्ट्र है, हम युवाशक्ति वाले राष्ट्र हैं और उस तरह से, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है कि हम ज्ञान के माध्यम से, विकास के माध्यम

से, पूरी राजनीति जो है विकास को समर्पित किये हैं, ज्ञान को समर्पित किये हैं, गरीब लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को और किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, उनको समर्पित करने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और उसके साथ जो एक बड़ा आह्वान किया है कि हम युवाओं को आगे कर, क्योंकि युवाशक्ति राष्ट्र शक्ति होती है । किस तरह से हम अपने युवाओं को स्किल्ड बनाने का काम करें और इसी के तहत जो हम सब इस बात को भी मानते हैं, हमारी पाँच हजार वर्ष पुरानी संस्कृति है, जहाँ व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने का हमारा इतिहास रहा है, आत्मनिर्भरता का इतिहास रहा है और उस इतिहास के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार कही कि हमारे यहाँ कौशल विकास हो, स्किल्ड डेवलपमेंट हो और खासकर युवाओं का हो, गाँव में रहने वाले लोगों का स्किल्ड डेवलपमेंट हो और उसके लिए पहली बार भारत की सरकार ने डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की शुरुआत की और बिहार की सरकार ने युवाओं को ध्यान में रखकर, कैसे हमारे युवाओं के अंदर की जो शक्ति है, उनकी जो ऊर्जा है, वह सकारात्मक दिशा में जाय । उसके लिए अलग से खेल विभाग को भी स्थापित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह भी काम हुआ है....

(क्रमशः)

टर्न–23/संगीता/21.02.2024

श्री राणा रणधीर (क्रमशः) : और इसलिए आज यह बड़ा अवसर आया है कि हमारे साथ यह डबल इंजन की सरकार का जो फिर से अवसर हुआ और उस डबल इंजन के माध्यम से बिहार के गरीबों का, अन्नदाताओं का, गांव में रहने वाले लोगों का, युवाओं का और नारी शक्ति का उनका सशक्तिकरण भी होगा, उनका विकास भी होगा और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेते हुए नया भारत बनाना है । बढ़ता हुआ विकसित भारत बनाना है और सदन के मित्रों को इस बारे में जानकारी है कि कैसे भारत की इकोनॉमी कभी फ्रेजाइल फाइव में हुआ करती थी । हमारे मित्र जो दंत चिकित्सक भी हैं, मुस्कुरा रहे हैं उनको पता है पढ़ते रहते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, शकील साहब भी बहुत एक्टिव रहते हैं । कांग्रेस के जमाने में यह सदन के लिए बड़े गौरव का विषय है कि जो फ्रेजाइल फाइव इकोनॉमी से आज टॉप फाइव इकोनॉमी भारत की जो हुई है और आज जो नारा चला है 400 पार का मित्रों, आप साथ देकर देखिए आज, देश के प्रधानमंत्री जी को पूरी दुनिया को पता है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं इसलिए जुलाई में, अगस्त में, सितम्बर में, अक्टूबर में, नवम्बर में भी बाहर के देशों से माननीय प्रधानमंत्री जी को न्यौता आ रहा है मित्रों । यह पहली बार हुआ है कि

देश के प्रधानमंत्री के बारे में कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, पूरी दुनिया आश्वस्त है और आप भी आश्वस्त हैं और हम सब...

(व्यवधान)

आप इंतजार करिए बिहार के किसानों को, देश के किसानों का जो सम्मान हुआ है, अजीत जी, वह देश का किसान पूरी ताकत से नरेंद्र भाई मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा और बिहार की डबल इंजन सरकार को पूरी मजबूती देगा ताकि बिहार के विकास को नया बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है । 2047 तक आप चिन्ता नहीं करिए, आप साथ दीजिए, देश के किसान साथ देंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है, मित्रों, हमारे लिए बड़ा गौरव का क्षण आने वाला है कि जिस ब्रिटेन की सरकार ने डेढ़ सौ-दो सौ वर्षों तक हमपर शासन किया उसको हम पछाड़कर पांचवें नंबर पर आए हैं, हम जर्मनी को पछाड़ने वाले हैं । सुदामा जी बैठे हैं, जहां की विचारधारा लेकर आप काम करते हैं उनको पीछे छोड़कर हम दुनिया की चौथी नंबर की आर्थिक अर्थव्यवस्था वाला देश बनेंगे और 2029 तक हम दुनिया के तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था वाला देश होंगे मित्रों, और जिस प्रकार से काम हो रहा है, जिस प्रकार से योजना रचना बनी है, आने वाले 50-100 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा और 2047 तक हम विकसित भारत का सपना, विकसित बिहार के सपने के साथ हम पूरा करने का काम करेंगे भाइयों और बहनों । अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आप देख लीजिए किस तरह से हमलोगों ने गांवों में, हमारे सहकारिता मंत्री जी बैठे हैं, गांवों में किसान लोगों के और उनके आवाम की मदद के लिए वहां से दवाई, जन औषधि केंद्र हमने पैक्सों के सशक्तिकरण के लिए जन औषधि केंद्र से दवाई वहां से किसान भाइयों को गांवों में रहने वाले लोगों को मिलेगा । कॉमन सर्विस सेंटर हमलोगों ने बनाने का काम किया है । पैक्सों के माध्यम से पैक्सों को और कितना सुदृढ़ कर सकते हैं, उसकी पूरी योजना रचना हमने बनाकर रखी है, देश को आगे बढायेंगे, बिहार को आगे बढ़ायेंगे । बिहार के विकास की दर आप सबलोगों ने देखी है, आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार के विकास की दर आपने देखी है । किस तरह से बिहार आगे बढ़ रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, सम्राट चौधरी जी ने और विजय सिन्हा जी ने कि पहले ठहरा हुआ विकास से आगे बढ़ता हुआ विकास ले जाने का जो प्रण लिया है और डबल इंजन की सरकार ने उसको पूरा करने का भी काम माननीय अध्यक्ष महोदय, हमलोगों के बिहार की सरकार, एन0डी0ए0 की सरकार, जदयू0 और भाजपा की सरकार पूरा करने का काम करेगी । हमारे अभिभावक मांझी जी भी बैठे हैं, तो सबका साथ, सबका

विकास लेते हुए हम सब विकसित भारत भी बनायेंगे और विकसित बिहार भी बनाने का हम सब काम करेंगे । आपको यह भी बता देता हूं, यह सरकार कहीं भेदभाव नहीं करती और यह तो हमारा सौभाग्य है कि जिस तरह के अध्यक्ष हमको मिले...

(व्यवधान)

किस प्रकार से कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम, आप लगातार बोलते थे, आप याद करिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, हमारे माननीय अध्यक्ष जी विजय सिन्हा जी जो आज उपमुख्यमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाने का काम किया था और आपके नेता तेजस्वी यादव जी ने जो मांग की थी कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, आज उनके बुलावे पर प्रधानमंत्री जी ने यहां आकर जो काम किया और जाकर जो 23 जनवरी को उनके 100वें जन्म शताब्दी पर...

(व्यवधान)

आपने क्यों नहीं दिया, आपकी सरकार थी, देश में आपकी सत्ता चली है, आप गठबंधन के भागीदार थे, आपने कर्पूरी जी को तब भी नहीं सम्मान देने का काम किया और आज भी सम्मान जो है वह माननीय प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया है । कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी को सम्मान देने का काम किया है । कृषि के क्षेत्र में जो गुणात्मक सुधार हो रहा है, जो कृषि के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार करने वाले कृषि मंत्री कृषि के वैज्ञानिक स्वामीनाथन जी को भी भारत रत्न देने का काम किया है मित्रों और जो भारत की आत्मा है, जो भारत की संस्कृति है, पांच हजार वर्ष पुरानी संस्कृति जहां भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, आचार्य चाणक्य आए आज देश को, देश की सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को, देश की विरासत को देश की आत्मा को रामलला को अयोध्या में स्थापित करने का काम हुआ है मित्रों । इसलिए पूरा देश, देश की जनता माननीय अध्यक्ष जी, देश की जनता तैयारी में है और पूरा विश्व इंतजार कर रहा है, तभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी को मई में, जून, में, जुलाई में, अगस्त में दुनिया भर के देशों का निमंत्रण आ रहा है । अध्यक्ष महोदय, यह नया बिहार बनाने का, नया भारत बनाने का यह नया अवसर है और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है आप देखिएगा, कैसे हमलोग 2024 में 400 पार और 2025 में 200 पार के साथ फिर से बिहार के विकास में, बिहार की जनता के विकास में किसानों के लिए, गरीबों के लिए, अपने अन्नदाताओं के लिए और नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए हम और काम करेंगे । आप रहेंगे तो आपके साथ भी काम करेंगे । माननीय प्रधानमंत्री जी

का तो नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर काम करना है और हम सब इसमें विश्वास करते हैं, हम सब इस बात को मानते हैं । कर्पूरी जी ने कहा था, आज कर्पूरी जी को भारत रत्न मिला है हम सब लगातार उसके लिए पूरा देश, बिहार विशेष रूप से और हम सब चूंकि उसी उत्तर बिहार के इलाके से आते हैं इसलिए हमलोग तो विशेष रूप से इस अवसर के प्रति भारत सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई भी देते हैं...

अध्यक्ष : अब आप कन्क्लूड कीजिए ।

श्री राणा रणधीर : कपूरी जी का एक बहुत बढ़िया शेर है अध्यक्ष महोदय । कपूरी जी की पंक्तियां पढ़कर अपनी वाणी पर विराम दूंगा । कर्पूरी जी की पंक्तियां सुन लीजिए । कर्पूरी जी ने इसी सदन में कहा था :

''बहुत दिन चला हूं किनारे-किनारे अब जी चाहता है कि मौजों से खेलूं
मौजे तूफां मेरी लाज रखना अहले साहिल ने ठुकराया है मुझे ।''

आपने ठुकराया था, नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी जी को भारत रत्न देकर सम्मानित करने का काम किया । अध्यक्ष जी, आपने अवसर दिया आपको बहुत, बहुत धन्यवाद । जनक जी को धन्यवाद, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री राज कुमार सिंह । पांच मिनट आपके पास है ।

श्री राज कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, सहकारिता विभाग के आज 1209 करोड़ से अधिक की राशि पर जो अनुदान मांग आयी है उसके समर्थन में मैं यहां पर हूं और हम सब जानते हैं कि सहकारिता विभाग किसानों के, गांवों के लोगों से जुड़ा हुआ यह विभाग है और किसानों की समृद्धि के लिए लगातार इस विभाग के माध्यम से सरकार प्रयास कर रही है । कृषि रोड मैप के जरिए जिस तरीके से 200, 500 और 1000 मीट्रिक टन के भंडारण क्षमता का गोदाम बनाया जा रहा है उसमें अभी तक 113 गोदामों की संरचना निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और 2024-25 में 460 गोदाम और बनने हैं, वे निर्माणाधीन हैं । इस विभाग ने जो कार्य किए हैं उसमें कई तरह की चीजें हैं । उसमें जैसे कि पैक्स के माध्यम से और कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना हो रही है हरेक पैक्सों में जो 8 हजार 763 पैक्स हैं हमारे राज्य में, हरेक पैक्स में 15 हजार से अधिक के कृषि संयंत्र को रखना है उसमें 14 हजार से अधिक संयंत्रों की व्यवस्था हो चुकी है और बाकी के लिए भी व्यवस्था हो रही है । उसी तरीके से किसानों के लिए जो किसान फसल सहायता दी जाती है उसमें भी सरकार लगातार सिर्फ खरीफ के दरमियान में किसानों के लिए काफी सहायता दी गई है । इसके अतिरिक्त जो कार्य हो रहे हैं सहकारिता विभाग में, जो हमारे

किसान हैं, जो सब्जी की खेती करते हैं उसके लिए पटना, तिरहुत समितियों के द्वारा किसानों का फसल खरीदकर उसको थोक और बाजार मूल्य में उनका विपणन किया जा रहा है इससे किसानों की आय में भी वृद्धि हो रही है ।

(क्रमशः)

टर्न-24/सुरज/21.02.2024

श्री राज कुमार सिंह (क्रमशः) : इससे किसानों की आय में भी वृद्धि हो रही है । सहकारिता विभाग चूंकि अध्यक्ष जी आपने सिर्फ 5 मिनट का समय दिया है और फिर औंचक्क ही बोलने का मौका मिला है तो मैं अपनी बात को, एकाध शेर कहना बनता है । आप सुनें आप ही के लिये कहता हूं कि :

''वाकिफ नहीं हैं जो लोग सफर के उसूल से
साये की भीख मांग रहे हैं बबूल से
मैं अब तक सफर में हूं इस एतेमाद पर
उभरेंगी मंजिलें कदमों की धूल से ।''

मेरी सरकार अपने मंजिल की ओर लगातार बढ़ रही है । माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, एन0डी0ए0 की यह सरकार बिहार ही नहीं पूरे देश में इस बिहार को अग्रणी ले जायेगी और आपको तो अभी पता होना चाहिये कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरीके से हम कई क्षेत्रों में आकांक्षी राज्य हुआ करते थे, आज के समय में हम अग्रणी राज्य की भूमिका में आ चुके हैं । इस सरकार में जिन-जिन लोगों ने सरकार का साथ दिया है सरकार की बदौलत और उस नेतृत्व की बदौलत उन्होंने अपने काम को चमकाने का प्रयास किया है । सारा काम माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनकी योजनाओं का, उनकी कार्यशैली का रहा लेकिन साथ में आप हैं तो उसका श्रेय लेने की कोशिश आप निश्चित रूप से करेंगे लेकिन आपकी आत्मा भी जानती है और अंतरात्मा भी जानती है कि सरकार की जो नीति थी, जो योजनाएं थी लगातार पूर्व से चली आ रही थी उन्हीं योजनाओं को और उन्हीं नीतियों को सरकार ने लागू किया, जिसके कारण आज इतनी संख्या में नियुक्तियां हुई हैं, ये सारी चीजें सरकार ने की है । तो मैं अपनी बात को, चूंकि किसानों की बात है और जब इस देश के 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त अनाज देकर उनको भुखमरी से बचाया जा रहा है तो इस देश के किसानों का उसमें सबसे बड़ा योगदान है । हमें किसानों के मामले में बिल्कुल संवेदनशील रहना चाहिये और तमाम सरकारें हमेशा से रही हैं और हमारी सरकार भी, एन0डी0ए0 की सरकार भी, माननीय प्रधानमंत्री भी और हमारे मुख्यमंत्री तो हमेशा किसानों के प्रति संवेदनशील रहे ही हैं । अंत में सिर्फ मैं एक

बड़े ही मार्मिक, अगर अध्यक्ष जी की इजाजत होगी तो एक मार्मिक नज्म से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा । कई तरीके का तंज इसमें है, कुछ अधिकारियों के ऊपर भी है लेकिन यह हकीकत भी है । अगर अध्यक्ष जी की इजाजत हो तो मैं कहूं।

अध्यक्ष : जरूर बोलिये । मैं तो चाहता हूं कि शेरो-शायरी का पुराना दौर फिर से आ जाये लेकिन लोग ही नहीं है । एक आप कभी-कभी बोल लेते हैं, बोलिये ।

श्री राज कुमार सिंह : यह उन गरीब लोगों के लिये है और जो लगातार तंत्र की व्यवस्था से परेशान हो जाते हैं, उनके ऊपर है कि :

''खुद्दार मेरे शहर का फाको से मर गया
राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया
चढ़ती रही मजार पर चादर तो बेशुमार
बाहर जो एक फकीर था सर्दी से मर गया
रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली
फाका गरीब शहर के बच्चों में बंट गया
और चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने
हाकिम ने कह दिया कुछ खाकर मर गया ।''

यह विडंबना निश्चित रूप से रही है, इसमें हमलोगों को और समाज को भी संवेदनशील होने की जरूरत है । हमारी अफसरशाही को भी संवेदनशील होने की जरूरत है...

अध्यक्ष : समाप्त कीजिये ।

श्री राज कुमार सिंह : और तमाम सरकारों को भी संवेदनशील रहने की जरूरत है । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सरकार का उत्तर

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भगवात गीता के श्लोक से अपनी बात की शुरूआत कर रहा हूं :

''कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः ।''

यानी वासुदेव नन्दन परमात्मा स्वरूपी भगवान श्रीकृष्ण को वंदन है, हे गोविंद पुनः पुनः नमन है, वे हमारे राज्य के अन्नदाता किसान भाइयों को, मजदूरों को सभी समस्याओं का निराकरण करने में सहायता करें ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, आदरणीय श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी, बिहार के लोकप्रिय विकास पुरूष और माननीय मुख्यमंत्री जी का, भारत सरकार के और देश के लोकप्रिय हम सबों के नेता भारत के गृह मंत्री, आदरणीय अमित शाह जी के प्रति, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के प्रति, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी और माननीय अध्यक्ष हमारे नन्दकिशोर यादव जी के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं ।

(व्यवधान)

सुनें नहीं तो दोहरा देते हैं । हमने शुरू में ही कहा था...

अध्यक्ष : बीच में नहीं बोलिये, यह ठीक नहीं है । मंत्री जी को बोलने दीजिये ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिहार की राजनीति में मुझे 5 दशकों से काम करने का मौका मिला है । सन् 1974 के जे0पी0 आंदोलन में छात्र की भूमिका में जय प्रकाश जी के साथ काम करने का मौका मिला था । उस समय अटल बिहारी बाजपेयी जी हम सबों के नेता हुआ करते थे । आदरणीय आडवाणी जी, आदरणीय जोशी जी उनके नेतृत्व में हमलोगों ने काम किया है सन् 1974 से लगातार आज 2024 तक । हमें खुशी इस बात की है हमारे क्षेत्र की जनता के प्रति हम, अपने सारे मतदाता भाई-बहनों का, जो गया जी की धरती से मुझे लगातार 08 बार चुनने का अवसर दिया है, उनके प्रति भी हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, एन0डी0ए0 के नेताओं के सहयोग से और राज्य के किसानों, वंचितों, शोषितों, अतिपिछड़ों, स्वर्ण जाति के साथियों, पिछड़ी जाति के लोगों का हमें लगातार आशीर्वाद मिलता रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, आज वित्तीय वर्ष 2024-25 के सहकारिता विभाग के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांग पर चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों का जो सुझाव आया है । आदरणीय श्री अजीत शर्मा जी, डॉ0 सुनील कुमार जी, श्री भूदेव चौधरी जी, श्री राम विलास कामत जी, श्री मुकेश कुमार रौशन जी, श्री विजय कुमार खेमका जी, श्री महा नंद सिंह जी, श्री अनिल कुमार जी, श्री सूर्यकान्त पासवान जी, श्री भारत भूषण मंडल जी, भाई अखतरूल ईमान जी, पूर्व सहकारिता मंत्री राणा रणधीर जी, श्री राजकुमार सिंह जी सहित आप सबों का जो सुझाव आया है निश्चित तौर पर हम विश्वास दिलाते हैं, मंत्रालय संभाले हमलोगों को लगभग 15 दिन हो रहा होगा और 15 दिनों के अंदर महोदय हमने समीक्षा किया और हमारे माननीय सदस्यों का काफी अच्छा-अच्छा सुझाव आया है, विचार आया है । निश्चित तौर पर विभाग के माध्यम से आपके सुझावों

पर हम गौर करेंगे, विचार करेंगे और सबसे बड़ा जो मैं देखा हूं कि अभी धान की अधिप्राप्ति का मामला था, हम भी समीक्षा कर रहे थे । क्या वजह है कि राज्य में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजना (डी0सी0पी0) के अंतर्गत धान एवं गेहूं की अधिप्राप्ति की जाती है । धान एवं गेहूं की अधिप्राप्ति पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के माध्यम से की जा रही है । राज्य में धान एवं गेहूं अधिप्राप्ति ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें विभागीय पोर्टल अंतर्गत मोबाईल ऐप के माध्यम से ऑनलाईन व्यवस्था अंतर्गत सभी कार्य का निष्पादन किया जाता है । महोदय, उद्देश्य इसका है कि धान एवं गेहूं अधिप्राप्ति का उद्देश्य किसानों को आपात बिक्री (Distress Sale) से बचाते हुये उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार तय करती है । अधिप्राप्त धान से तैयार चावल एवं गेहूं का उपयोग राज्य खाद्य निगम द्वारा जन कल्याणकारी योजना अंतर्गत किया जाता है । हम देख रहे थे विगत तीन वर्षों का क्या अचीवमेंट विभाग में है ।

(क्रमशः)

टर्न-25/राहुल/21.02.2024

श्री प्रेम कुमार, मंत्री (क्रमशः) : मुझे भी लगा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में हम देख रहे थे लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन था, किसानों की संख्या-6.42 लाख थी । अधिप्राप्ति 99.78 परसेंट हुई थी । वर्ष 2022-23 में हम देख रहे हैं कि 93.42 परसेंट अधिप्राप्ति हुई लेकिन 2023-24 में हम देख रहे थे कि चालू वित्तीय वर्ष में हमें काफी लगा कि क्या वजह है कि आखिर 45 लाख मीट्रिक टन के विरूद्ध जो उपलब्धि मैं देख रहा था मात्र 68.44 परसेंट थी । यानी 45 लाख टन के विरूद्ध 30 लाख मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति हो पायी है । महोदय, विभाग में समीक्षा हमने की है इस वर्ष धान का बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर या उसके आस-पास रहने के कारण किसानों द्वारा सहकारी क्रय केन्द्रों के साथ-साथ खुले बाजार में निजी क्रेताओं को भी बिक्री की गयी...

(व्यवधान)

राज्य के आंतरिक, आर्थिक विकास के तहत...

अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : इथेनॉल इकाइयों की स्थापना होने के कारण इसकी मांग उसमें भी रहने के कारण धान का बाजार मूल्य बढ़ाने में अहम भूमिका रही है...

(व्यवधान)

महोदय, हम सदन को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि धान अधिप्राप्ति के मामले में माननीय सदस्यों के जो सुझाव आये हैं, जो उपलब्धि होनी चाहिए थी

और कम जो है उसके लिए मैं चाहता हूं, हमारा विभाग घोषणा करना चाहता हूं कि हम बिहार के वरीय अधिकारियों की टीम बनाकर धान प्राप्ति सहित सभी मुद्दों का अध्ययन करने के लिए भारत के अन्य राज्यों में जायेगी ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बर्हिगमन कर गये)

ताकि आने वाले समय में सहकारिता विभाग जो हमारा विभाग है वह राज्य के किसानों के हित में बेहतर काम करेगा । महोदय, मुझे खुशी है कि सहकारिता की बातों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत देश में पहली बार अलग से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया । देश के पहले एवं वर्तमान सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के निर्धारित लक्ष्य सहकारिता समृद्धि को प्राप्त करने में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार अग्रणी भूमिका निभा रहा है । महोदय, हम कह रहे थे कि जो सुझाव आये हैं और धान अधिप्राप्ति के मामले में थोड़ा पीछे थे उन कारणों की भी समीक्षा किये हैं और समाधान के लिए तय किये हैं कि विभाग के अधिकारियों की टीम बनाकर हम बिहार से बाहर भेजेंगे उससे अध्ययन करायेंगे और अन्य राज्यों में कैसा काम हो रहा है निश्चित तौर पर एक माह के अंदर में प्रतिवेदन आने के बाद सहकारिता विभाग आपके सुझावों को जोड़ते हुए बेहतर तरीके से राज्य के किसानों के लिए काम करने का काम करेगा । अध्यक्ष महोदय, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य किसानों तथा अन्य लोगों, मुख्य रूप से वंचित वर्ग के लोगों को संगठित एवं सक्रिय करते हुए स्वयं सहायता, परस्पर सहायता एवं सह-अस्तित्व के माध्यम से आर्थिक एवं समाजिक उत्थान करना है । ताकि न्याय के साथ समग्र विकास हो सके । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि :

''एक-दूजे से हाथ मिलायें, सब मिलाकर आगे आयें ।
एक और भाईचारे की नई मिसाल बनायें ।।''

महोदय, सहकारिता का यही उद्देश्य है । अध्यक्ष महोदय, देश के करोड़ों किसानों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों, गरीबों एवं महिलाओं के विकास का मार्ग केवल सहकारिता के माध्यम से ही प्रशस्त हो सकता है । सहकारिता के बिना गरीब कल्याण और अंत्योदय की कल्पना संभव नहीं है । सहकारिता आंदोलन भारत ग्रामीण समाज की प्रगति भी करेगा और एक नई सामाजिक पूंजी की धरा भी खड़ी करेगा । महोदय, सहकारिता क्षेत्र में भारत उन्नति का मुख्य स्थल बन सकता था लेकिन इतने दशक तक किसी ने सहकारी क्षेत्र के बारे में नहीं सोचा । ऐसे

समय पर जब सहकारिता आंदोलन की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदीजी ने एक स्वतंत्र नया सहकारिता मंत्रालय बनाकर सहाकारिता क्षेत्र की उपेक्षा के युग को समाप्त कर सहकारिता की प्राथमिकता से शुरुआत करने का काम किया है । महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि जब बिहार में एन0डी0ए0 की सरकार आयी थी और एन0डी0ए0 की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, पहले सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं थी हम जब सरकार में आये चाहे हमको भारत सरकार में आने का मौका मिला हो, चाहे बिहार में आने का मौका मिला हो । हमारी सोच रही है कि गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान यानी किसान हमारी प्राथमिकता है और भारत कृषि प्रधान देश है, बिहार भी कृषि प्रधान राज्य है और जो हमारे देश की इकोनॉमी है वह कृषि पर आधिरित है उसकी रीढ़ कृषि है और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उससे पहले भी सरकार थी, 2005 से पहले । अंधेरे का बिहार, गड्ढ़े का बिहार, बिहार में कानून नाम की चीज थी ही नहीं । हमें याद है क्या हालत थी और लंबे समय तक हम लोग संघर्ष करने का काम किये, हम सब लोग जान हथेली पर लेकर संघर्ष करते थे, सड़क से सदन तक संघर्ष करने का मौका मिलता था और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से मुझे वर्ष 1990 में विधायक बनने का मौका मिला और तब से लेकर लगातार 2005 तक संघर्ष करते-करते और सरकार बनाने का मौका मिला और बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एक अच्छी शुरुआत हुई । उस समय माननीय सुशील मोदी जी उपमुख्यमंत्री हुआ करते थे । हमारे तमाम नेताओं के सहयोग से बिहार बदलने लगा और हमारे जो तमाम माननीय मंत्री थे, एन0डी0ए0 के हमारे जो माननीय मंत्री थे सबका योगदान था, एक बड़ा चैलेंज, चुनौती उस समय हुआ करती थी । सड़क की हालत क्या थी, बिजली की हालत क्या थी ? उस चुनौती को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवसर में बदलने का काम किया । बिहार बदलने लगा, बिहार की चर्चा पूरे देश में होने लगी, बिहार विकास के मार्ग पर आगे जाने लगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 2008 में जब बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एन0डी0ए0 की सरकार बनी तो हमारी सरकार ने किसानों के लिए कृषि रोड मैप लाने का काम किया । पहला कृषि रोड मैप 2008-12 तक, दूसरा 2012-17 तक, तीसरा 2017-2023 तक संयोग से 2017 में बिहार में एन0डी0ए0 की सरकार फिर से बहाल हो गयी थी, मुझे कृषि मंत्री बनने का मौका मिला था । लोग तो बोले थे कि भाई प्रेम कुमार शहर का आदमी है किसानों के बारे में क्या जानेगा लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि तीन वर्षों में बिहार में पहला

मंत्री आप सबके आशीर्वाद से बनने का मौका मिला कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी से राष्ट्रीय कृषि कर्मण अवार्ड तीन बार प्राप्त करने का मुझे मौका मिला है और साथ ही साथ, मैं देख रहा हूं कि जो हमारा कृषि रोड मैप आया और चौथा रोड मैप जो आया है वह 2023-28 तक का है । महोदय, इसमें 12 विभाग हैं । कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन में सहकारिता विभाग की भूमिका किसानों के लिए फसल चक्र की समग्र आवश्यकताओं यथा कृषि उपादान (खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि साख आदि), भंडारण क्षमता का सृजन, कृषि उपकरण बैंक की स्थापना, कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण, खाद्यान्नों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की उपलब्धता तथा सहकारी प्रक्षेत्र में संस्थागत विकास हेतु प्रशिक्षण के रूप में परिभाषित की गयी है । इन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के संदर्भ में सहकारिता विभाग के द्वारा प्रशंसनीय उपलब्धियां प्राप्त की गयी हैं । पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण-सह-कार्यालय की स्थापना से सहकारी संस्थाओं को भौतिक पहचान मिलने के साथ-साथ व्यवसाय विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है । राज्य के कुल 6973 पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में गोदाम-सह-कार्यालय निर्माण कार्य पूरा हो चुका है जिसके माध्यम से लगभग 15.1295 लाख एम0टी0 भंडारण क्षमता का सृजन किया गया है । भंडारण क्षमता के सृजन के परिणामस्वरूप सहकारी समितियों के माध्यम से खाद, जनवितरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति का कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त 473 पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में राइस मिल की स्थापना की गयी है, जिसके माध्यम से अधिप्राप्ति धान की मिलिंग कर राज्य खाद्य निगम को आपूर्ति की जा रही है । अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहते हैं कि :

''बसंत ऋतु में एक बार फिर आई एन0डी0ए0 की सरकार ।
बिहार में फिर से बहने लगी खुशियों/विकास की बयार ।।
विकास की गति फिर से होगी दिन दूनी, रात चौगुनी ।
क्योंकि पी0एम0 मोदी, सी0एम0 नीतीश की जोड़ी आयी है ।।
सहकारिता की साख से देश में होगा बिहार नंबर वन ।
कृत संकल्प से सब कुछ होगा कहता हूं तत्क्षण ।।''

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि भारत की जनता के स्वभाव में सहकारिता घुल-मिल गयी है और संस्कार में सहकारिता कोई उधार लिया हुआ विचार नहीं है ।

(क्रमशः)

टर्न-26/मुकुल/21.02.2024

(क्रमशः)

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : इसलिए सहकारिता आंदोलन कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकता । माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन में इच्छा है कि छोटे से छोटे व्यक्ति विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार बने । सहकारिता की प्रक्रिया से हर घर को समृद्ध बनाना और हर परिवार की समृद्धि से देश को समृद्ध बनाना यही सहकार से समृद्धि का मंत्र है । महोदय, अगर छोटे-छोटे लोगों की बड़ी संख्या एक एकजुट होकर, एक लक्ष्य के साथ मधुर भाव से एक दिशा में काम करे तो एक बड़ी ताकत निर्मित हो सकती है, यही सहकारिता का मूल मंत्र भी है । माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि सहकारिता के बगैर देश का विकास असंभव है, यह सिर्फ सहकारिता से हो सकता है एवं इसी मॉडल को हमें आगे बढ़ाना है । किसी एक देश का आर्थिक विकास कई रास्तों से हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति तक आर्थिक विकास का कुछ न कुछ फायदा पहुंचे यह सिर्फ सहकारिता से ही संभव है । अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के 97वें संशोधन के फलस्वरूप देश के नागरिकों को सहकारी समितियों के गठन को मौलिक अधिकार दिया गया है । साथ ही, राज्य नीति निर्देशक तत्व में संशोधन करते हुए राज्य सरकारों को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित करने की भी बृहत्तर जिम्मेदारी सौंपी गई है । अध्यक्ष महोदय, भारत में आजादी प्राप्ति के पहले से चल रहा सहकारिता आंदोलन आज विराट रूप धारण कर चुका है और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । इसके चलते देशवासी आर्थिक रूप से समृद्ध तो हुए ही हैं, साथ ही बेरोजगारी, गरीबी की समस्या भी बहुत हद तक कम हुई है । एक अनुमान के अनुसार इस समय देश भर में करीब 5 लाख से अधिक सहकारी समितियां सक्रिय हैं, जिनमें करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है । ये समितियां समाज के अनेक क्षेत्रों में काम कर रही हैं । लेकिन कृषि उर्वरक और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में इनकी भागीदारी सर्वाधिक है । अब तो बैंकिंग के क्षेत्र में भी सहकारी समितियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है । लेकिन देश में सहकारी आंदोलन राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति का साधन बनकर अनेक विसंगतियों के जाल फंसा दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, समाज के बृहत्तर समुदाय, कमजोर वर्ग, वंचित वर्ग तथा महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को सहकारिता के माध्यम से फलीभूत करने के लिए आज के प्रतिस्पर्धी आर्थिक परिवेश में सहकारी समितियों को सबल और सक्षम बनाया जाना आवश्यक है ताकि वे अपने सदस्यों को सहकारिता से जुड़े कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के

कार्यान्वयन तथा सहकारी संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के लिए सतत प्रत्यनशील हों । अध्यक्ष महोदय, आपको यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं केन्द्रीय गृह-सह-सहकारिता मंत्री जी के नेतृत्व में देश में सहकारिता क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन लाने एवं इसके माध्यम से एक विकसित भारत के निर्माण के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं । देश के हित में नई सहकारिता नीति बनाई जा रही है, जिसके क्रियान्वयन से देश में एक नई सहकार क्रांति का सूत्रपात होगा तथा देश के किसानों एवं उपभोक्ताओं का बहुत ज्यादा लाभ होगा । अध्यक्ष महोदय, वहीं के बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में राज्य के किसानों को पारदर्शी तरीके से उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भारत सरकार तय करती है, उसको दिलाने के उद्देश्य से धान/गेहूं अधिप्राप्ति कार्य ई-प्रॉक्योरमेंट प्रणाली अन्तर्गत मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल द्वारा ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, अधिप्राप्ति कार्य कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधित किसानों के माध्यम से कराया जाता है । राज्य के चयनित पैक्स/व्यापार मंडल में निबंधित किसान धान/गेहूं की बिक्री कर न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से अपने खाते में निर्धारित समय के अन्तर्गत प्राप्त कर सकते हैं । किसानों को अधिप्राप्ति से संबंधित जानकारी देने एवं उनके शिकायतों के त्वरित निष्पादन हेतु आई0वी0आर0एस0 कॉल सेंटर 'सुगम' भी कार्यरत है, जिसके तहत पूरी व्यवस्था पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से संचालित होती है । राज्य सरकार द्वारा धान अधिप्राप्ति कार्य हेतु 8,000 (आठ हजार) करोड़ रुपये राजकीय गारंटी के रूप में बिहार राज्य सहकारी बैंक/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को स्वीकृति दी गई है, जिसका उपयोग धान अधिप्राप्ति हेतु पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा कैश क्रेडिट के रूप में किया जा रहा है । महोदय, वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रबंधकीय अनुदान हेतु एक अरब पचास करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था । जिसके तहत ससमय सी0एम0आर0 की आपूर्ति करनेवाले पैक्सों को 30 रुपये प्रति क्विंटल से 20 रुपये प्रति क्विंटल तक प्रोत्साहन के रूप में प्रबंधकीय अनुदान देने का प्रावधान है । अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार ने किसानों के लिए पहली बार, मैं देख रहा हूं कि हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना की शुरुआत की है । महोदय, इसका उद्देश्य है कि किसानों को कम पैसे खेती करने में कृषि यंत्रों का जो वे उपयोग करते हैं उनको उसका लाभ मिल सके । अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने ऐसे तमाम पैक्सों को, हमारी सरकार ने जो तय किया है कि

ऐसे तमाम पैक्सों को 15 लाख रुपये की राशि दे रही है । महोदय, 15 लाख रुपये की राशि में हमारा करीब 7.50 लाख रुपये अनुदान है । महोदय, इसके अलावा मैं देख रहा हूं कि 7.50 लाख रुपया अनुदान है और 7.50 लाख रुपया लोन के रूप में है जिसको उनको 10 किस्तों में भुगतान करना है, कम इंट्रेस्ट रेट पर दिया गया है, जिससे राज्य की कृषि में मात्रात्मक एवं गुणात्मक अभिवृद्धि संभव हो । योजनान्तर्गत राज्य के सभी 8463 पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना की जानी है । महोदय, मैं बता रहा हूं कि योजनान्तर्गत प्रथम चरण में 2927 पैक्सों में प्रति पैक्स 15 लाख रुपये की दर से कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित था, जिसके लिए कुल 439.05 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिकी सब्जी सहकारी समितियों को भी आच्छादित करने की योजना है । अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग के द्वारा राज्य सरकार के निर्णय के मुताबिक पहली बार, आप देख रहे होंगे कि बड़े पैमाने पर बिहार में दूध के क्षेत्र में सुधा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, वह कोऑपरेटिव है । गांव के किसानों को संगठित करके और उससे जुड़े जो किसान भाई हैं उनकी समिति बनाकर और आज पूरे बिहार में सुधा का बेहतर प्रदर्शन हो रहा है उसकी जितनी भी तारीफ की जाय वह कम है । अध्यक्ष महोदय, उसी तरह हमलोगों ने तय किया है कि बिहार में लोग सब्जी का इस्तेमाल करते हैं और यहां पर बड़े पैमाने पर सब्जी का उत्पादन भी होता है । किसानों को सही मूल्य कैसे मिले उसके लिए हमारी सरकार ने बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना की शुरुआत की है । हम सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य के जो किसान हैं, चाहे सब्जी उत्पादकों हों, उनको लाभकारी मूल्य दिलाना एवं ग्राहकों के लिए गुणवत्तापूर्ण तथा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर सब्जी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना की शुरुआत की गई है । जिसके तहत राज्य में शीर्ष स्तर पर सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन भी गठित एवं कार्यरत है । फेडरेशन के अन्तर्गत पटना, तिरहुत एवं मिथिला कुल तीन संघ का गठन किया गया है । पटना संघ के अन्तर्गत पटना, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भोजपुर एवं बक्सर जिलों में प्रखंड स्तरीय प्राथमिकी सब्जी उत्पादक सहकारी समितियां (पी0वी0सी0एस0) गठित हैं । तिरहुत संघ के अंतर्गत पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, सारण, सिवान एवं गोपालगंज जिलों में पी0वी0सी0एस0 का गठन किया गया है तथा मिथिला संघ के अंतर्गत दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिले के पी0वी0सी0एस0 गठन है । इस प्रकार वर्तमान में योजना का आच्छादन 3 संघों के माध्यम से राज्य के 20 जिलों में किया जा चुका है । इन 20 जिलों में

कुल 300 प्रखंड स्तरीय पी0वी0सी0एस0 का गठन हो चुका है । शीर्ष स्तर पर अब तक 38532 सब्जी उत्पादक किसान सदस्य बन चुके हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि इसका काफी बेहतर प्रदर्शन हो रहा है और इससे किसानों को फायदा हो रहा है, साथ ही राज्य की आम जनता को भी इसका फायदा मिल रहा है । महोदय, इस योजना का ब्राण्ड तरकारी है । संघों द्वारा संस्थागत खुदरा बिक्री के माध्यम सब्जी बिक्री का कार्य संचालित है । राज्य के विभिन्न सरकारी संस्थानों/प्रतिष्ठानों में सब्जी की आपूर्ति की जा रही है । इसका उद्देश्य था कि बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के तहत किसानों को सही दाम दिलाना और राज्य की जो जनता है जिनको जरूरत है उनकी जरूरतों को ससमय उपलब्ध कराने के ख्याल से इस योजना की शुरुआत की गई है । अध्यक्ष महोदय, उसी तरह से मैं देख रहा हूं कि पहली बार आजादी के बाद इस देश के किसानों की हालत क्या थी, सरकारें बहुत रहीं और लंबे समय तक इस देश में कांग्रेस की हुकूमत रही ।

क्रमशः

टर्न–27/यानपति/21.02.2024

श्री प्रेम कुमार, मंत्री (क्रमशः) : महोदय, लगभग 75 वर्षों तक किसान के सामने जो संकट हुआ करता था, देश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ में, देश का बड़ा हिस्सा सुखाड़ में डूबा रहता था, ओलावृष्टि का प्रभाव, कीट–मकोड़े का प्रभाव पड़ता था और पिछली सरकार के समय किसान आत्महत्या कर रहे थे । कांग्रेस के राज्य में जब यहां आर0जे0डी0 की सरकार हुआ करती थी, किसानों की हालत क्या थी । हम सरकार में जब आये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा फैसला लिया है । 2014 में और उससे पहले मैं देख रहा हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब आई थी तो किसानों ने वाजपेयी जी से मिलकर कहा और जो किसान क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता थी किसानों ने वाजपेयी जी से कहा कि हम सबों को खेती करने के लिए पैसों की दरकार होती है और यदि पैसा नहीं रहता है, हम बाजार से जाकर पैसा लेते हैं और बाजार से जब पैसा लेते हैं तो काफी महंगा होता है । एड्रेस काफी महंगा होता है और आदरणीय वाजपेयी जी ने पहली बार 1998 में महोदय और पहली बार हमारी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की शुरूआत जनता पार्टी की सरकार में शुरू हुई । उसके बाद महोदय हम कहना चाहते हैं कि आज इस तरह से किसानों के सामने जो संकट था, प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को काफी नुकसान होता था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरूआत की । हम सरकार में उस समय थे और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और पहली बार बिहार राज्य फसल सहायता योजना की शुरूआत की गई थी यानी कि बिना प्रीमियम के, बिहार पहला राज्य है जहां पर हमलोगों ने, हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में बिहार राज्य फसल सहायता योजना शुरू किया था । और इस तरह महोदय खरीफ-2022 मौसम में कुल जो लाभान्वित किसान मैं देख रहा हूं 2 लाख 86 हजार 637 किसान हमारे हैं और उन्हें भुगतान किया गया है रबी के मौसम में जो भुगतान किया गया है और लगातार मैं देख रहा हूं किसानों के द्वारा ऑनलाइन निबंधन कराया जाता है । इसके जांचोपरांत मार्च-अप्रैल 2024 में जो भुगतान किया जाना है और महोदय इस तरह से एक अच्छी योजना है । इसके कारण आज एन0आई0सी0 के तकनीकी सहयोग से विकसित बिहार राज्य फसल सहायता योजना पोर्टल को कंप्यूटर सोसाईटी ऑफ इंडिया के द्वारा ई-गवर्नेंस के लिए अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस प्रदान किया गया । तो इस तरह महोदय राज्य के किसान भाइयों के लिए हमारी सरकार ने एक अच्छी पहल की थी कि आनेवाले समय में किसानों का जो नुकसान होता है, बाढ़ से, सुखाड़ से, प्राकृतिक कारणों से उसकी भरपाई करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो पहल की गई महोदय इसकी चारों ओर तारीफ हुआ करती थी । महोदय, उसी तरह हमलोगों ने पैक्स को कंप्यूटराइज कर रहे हैं ताकि आनेवाले समय में सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) हेतु कंप्यूटरीकृत योजना शुरू की गई है । महोदय, इसका उद्देश्य है कि जो भी हमारा यहां पर पैक्स है उसको पारदर्शी बनाना है । किसान भाइयों के साथ-साथ पैक्स सदस्य हैं जिन्हें योजनाओं की जानकारी देनी है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, कहीं आप यह तो नहीं कहना चाहते हैं कि देश की आजादी के बाद बिहार में पहली बार भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सहकारिता विभाग बनाया है जिसके कारण लाभ हो रहा है ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, आपने सही कहा, आपकी बातों का स्वागत करते हैं और आज भारत सरकार ने पैक्सों को कंप्यूटराइज करने के लिए पैसे भी देने का काम किया है और बड़े पैमाने पर मैं देख रहा हूं, पैक्सों में काम लगा हुआ है । पैक्स जो हमारे काम कर रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि कुल मिलाकर इनका जो उद्देश्य है वह यह है कि आनेवाले समय में हम पैक्सों के कार्यों को सुगम एवं पारदर्शी बनाने के साथ-साथ उनकी दक्षता एवं लाभ में वृद्धि करते हुए भविष्य में उन्हें

मल्टी सर्विस सेन्टर के रूप में विकसित करना है । महोदय, काम लगा हुआ है प्रथम चरण में हमलोगों ने कुल मिलाकर 4477 पैक्सों में कम्प्यूटरीकरण की कार्रवाई हमलोगों ने कर दी है ताकि आनेवाले समय में दूसरे चरण की भी शुरूआत करेंगे तो कुल मिलाकर हमलोगों का प्रयास है कि राज्य में हमारे जो किसान भाई हैं । हम राज्य में कहना चाहते हैं कि दूसरी तरफ जो हम अच्छा फैसला करने जा रहे हैं उसके लिए सहकारिता विभाग ने एक योजना बनाई है । योजना के तहत मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना लागू किया गया है । इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ प्रतियोगिताओं के आधार पर पैक्सों को आदर्श पैक्स के रूप में विकसित करना है । योजनाओं के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले के तीन पैक्सों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में 5 लाख, 3 लाख एवं 2 लाख राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, यह पहली बार शुरू हुआ है ताकि पैक्स अच्छा काम कर सके, प्रोत्साहित करने के लिए मानीनय मुख्यमंत्री जी ने शुरूआत की और राज्य स्तर पर भी तीन पैक्सों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार देने की व्यवस्था है और पैक्सों का चयन किया जा रहा है और आनेवाले समय में राज्य के हमारे जो किसान हैं और जो अच्छा पैक्स हमारा काम कर रहा है । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार बड़े पैमाने पर किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री कृषि रोड मैप बनाने के लिए काम किया है । बड़े पैमाने पर किसानों के लिए काम किया गया है, कई योजनाओं की चर्चा हमने की है । सहकारिता में सर्वसमावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की अपार क्षमता है । इसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 6 जुलाई 2021 को भारत सरकार द्वारा सहकार से समृद्धि के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था और इसमें महोदय राष्ट्रीय सहकारिता डाटाबेस की तैयारी की जा रही है, पैक्सों को कॉमन सर्विस केंद्र की व्यवस्था की जा रही है और पैक्सों के द्वारा किसानों को संगठित करके एफ0पी0ओ0 बनाने का काम चल रहा है । राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में 1100 अतिरिक्त एफ0पी0ओ0 के आवंटन का निर्णय लिया गया है । पैक्स भी अब एफ0पी0ओ के रूप में कृषि संबंधित अन्य आर्थिक कार्यकलाप करने में सक्षम है । इसके माध्यम से सहकारी समिति और सदस्यों को आवश्यक बाजार लिंकेज प्रदान कर उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में भी सहायक होगी । उसी तरह भारत सरकार ने पैक्सों में पेट्रोल पंप के रीटेल आउटलेट ताकि किसानों को आसानी से यह सुविधा प्राप्त हो सके । पैक्सों में दवा जन औषधि केन्द्र की स्थापना की जा रही है और भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से पैक्सों में जन

औषधि केन्द्र खोले जाने का निर्णय लिया है । इसके तहत सस्ती जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता सामान्य एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक आसानी से हो जायेगी । इस योजना के तहत उत्पाद बास्केट में 1759 दवाएं और 280 सर्जिकल उपकरण शामिल हैं । जो जन औषधि केन्द्र के माध्यम से बेचा जा सकता है । महोदय, मुझे जानकारी मिली है कि जो जन औषधि केन्द्र हैं, जो दवा का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, आम जनता कर रही है सस्ती दवा मिलती है । देखा गया है कि पूरे देश में चालू वित्तीय वर्ष में 26 हजार करोड़ का इसमें बचत हुआ है । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार ने एक ओर जहां बिहार की सरकार किसानों के लिए सहकारिता के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है वहीं प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र के रूप में पैक्स जोड़ा गया है । भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में कार्यशील पैक्सों को उर्वरक खुदरा विक्रेता के रूप में कार्य करने हेतु पात्र बनाया जाय । प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्रों पर खाद, दवा, छिड़काव के लिए ड्रोन जो हमलोग चर्चा करते हैं नमो दीदी ड्रोन उद्यमियों के रूप में भी कार्य करने का निर्णय लिया गया है । उसी तरह महोदय, पैक्सों में माइक्रो ए0टी0एम0 एवं सदस्यों को रूपे किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जायेगी । महोदय, कुल मिलाकर भारत सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा लगातार राज्य के किसानों के हित में काम किया जा रहा है । अब आनेवाले समय में जिन माननीय सदस्यों ने जिन बातों की चर्चा की उसपर हम कहना चाहेंगे पहली बार आजादी के बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और केन्द्र सरकार ने पहली बार छोटे-छोटे किसानों को उसमें देश में 12 करोड़ से अधिक किसानों को सीधे डी0बी0टी0 के माध्यम से प्रतिवर्ष 6 हजार की राशि दी जा रही है । पहली बार किसान सम्मान निधि की योजना की शुरुआत की गई है । बिहार में मैं देख रहा हूं 83 लाख 54 हजार 905 किसानों को 17456 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है । इसलिए महोदय, हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार ने किसानों के लिए किसान मानधन योजना की शुरूआत की गई अब महोदय चाहेंगे कि जो बातें छूट रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ गए हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उनके कुशल नेतृत्व में हमलोगों को लंबे समय से 2005 से काम करने का मौका मिला है और मुझे सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी गई है । हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपका कुशल नेतृत्व और हम सब मिलकर बेहतर करने का काम करेंगे जो बातें छूट गई हैं महोदय, प्रोसीडिंग का पार्ट बनवा दीजिए । माननीय सदस्य चले गये हैं, कटौती का प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

(परिशिष्ट - द्रष्टव्य)

टर्न-28/अंजली/21.02.2024

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''इस शीर्षक के मुख्य शीर्ष-2425, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-105, उप शीर्ष 0101 के लिए 2,00,00,000/- रुपये की मांग 1,00,00,000/- रुपये से घटाई जाय ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''सहकारिता विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिये 1209,36,44,000/- (एक हजार दो सौ नौ करोड़ छत्तीस लाख चौवालीस हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 21 फरवरी, 2024 के लिये स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-43 है, अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक-22 फरवरी, 2024 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की जाती है ।

सहकारिता

"कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने"

"प्रणत: क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।"

*सहकारी संगठन एक स्वैच्छिक तथा खुली सदस्यता के वाला संगठन है जो बिना किसी भेदभाव के सेवाओं का उपयोग में समर्थ है,सहकारिता के सदस्य बनने की रजामंदी स्वीकार करता है।

*संगठन पर सदस्यों को लोकतांत्रिक निर्यंत्रण रहता है। *सहकारिता में सदस्यों का आर्थिक भागीदारी पूंजी रूप में होता है जिसका नियंत्रण लोकतांत्रिक तरीके से सदस्य करते हैं।

*सहकारी समिति अपने सदस्यों द्वारा निर्यंत्रित स्वत और आत्मनिर्भर संगठन है।सदस्यों,निर्वाचित प्रतिनिधियों प्रबंधको और कर्मचारियों को समय-समय पर शिक्षा और प्रशिक्षण और जानकारी देते रहती है।

*स्थानीय,क्षेत्रीय,राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर सहकारी संगठन कार्य में सहयोग करती है।

*सहकारी समिति अपने सदस्यों द्वारा अनुमोदित नीतियों के माध्यम से अपने समुदाय के विकास के लिए कार्य करती रहती है।

*सहकारिता विभाग क्रय_विक्रय शीत गृह निर्माण, श्रम, उपभोक्ता, सहकारी ऋण एवं ऐसे ही अन्य कार्य करती है।

*कृषकों,ग्रामीण कारीगरों,भूमिहीन मजदूर एवं समुदाय के कमजोद तथापिछड़े वर्गों के कम आय वाले व्यक्तियों, अर्द्ध रोजगार तथा बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराती है।

सहकारिता विभाग का हेल्पलाइन नंबर:_1800 1800 110 है।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना:_ खरीफ 2023_24 कुल आवेदन_15,96,950

*रैयत कृषक 78,256

गैर रैयत कृषक 8,58,934

रैयत एवं गैर रैयत दोनों कृषक 6,59,760

बिहार राज्य फसल सहायता योजना:_रबी 2023_24

*कुल आवेदन 3,91,876

*रैयत कृषक 17,825

*गैर रयत कृषक 1,94,191

*रैयत एवं गैर रैयत कृषक दोनों 1,79,860

धान अधिप्राप्ति 2023_24

*कुल आवेदन 6,46,000

*रैयत कृषक 3,03,776

*गैर रैयत कृषक 3,4,224

सहकारिता विभाग अब ग्रामीण परिवहन के क्षेत्र में,कृषि, स्वास्थ्य,खनिज के साथ सर्विस के सेक्टर में अपना विस्तार कर रही है।

कृपया उपस्थिति-
P 70

① पर, जाने क्यों, नियम एक अद्भुत जग में चलता है।
भोगी सुख भोगता, तपस्वी और अधिक जलता है॥
हरियाली ~~है~~ जहाँ, जलद भी उसी खंड के वासी।
मरु की भूमि मगर, रह जाती है प्यासी की प्यासी॥
"रश्मिरथी", दिनकर

② मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन?
धरती की तो है क्या बिसात? आ जाय अगर बैकुंठ हाथ।
रश्मिरथी, दिनकर

③ धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं।
भुजबल से कर संसार-विजय, अगणित समृद्धियों का संचय॥
वैभव-विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं।
बस, यही चाहता हूँ केवल, दान की देव-सरिता निर्मल॥
रश्मिरथी, दिनकर

④ रण-खेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको।
रश्मिरथी, दिनकर।

⑤ जो अगणित लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे।
जल-जलाकर बुझ गए किसी दिन, माँगा नहीं स्नेह मुँह खोल।
कलम, आज उनकी जय बोल।

नोट — विपक्षियों के टोकने पर कृपया उपरोक्त पाँचों कविता समयानुसार पढ़ना चाहिए।

माँग संख्या–09 पर
मंत्री, सहकारिता विभाग
का वक्तव्य

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से, मैं सहकारिता विभाग के वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए व्यय हेतु रू० 12,09,36.44 लाख (बारह अरब नौ करोड़ छत्तीस लाख चौवालीस हजार) रूपये मात्र के माँग संख्या–09 को सदन में विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार जी का आभारी हूँ कि देश के बहुसंख्य किसानों के हित से जुड़े सहकारिता विभाग का बजट प्रस्तुत करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। सहकारिता के महत्व को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत देश में पहली बार अलग से सहकारिता विभाग का गठन किया गया है। भारत के पहले एवं वर्तमान सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह जी के निर्धारित लक्ष्य "सहकार से समृद्धि" को प्राप्त करने में माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार अग्रणी भूमिका निभाएगा।

अध्यक्ष महोदय, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य किसानों तथा अन्य लोगों मुख्य रूप से वंचित वर्ग के लोगों को संगठित एवं सक्रिय करते हुए स्वयं सहायता, परस्पर सहायता एवं सह–अस्तित्व के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान करना है ताकि न्याय के साथ समग्र विकास हो सके।

एक दूजे हाथ मिलाए, सब मिलाकर आगे आए,
एकता और भाईचारे की नई मिशाल बनायें।

अध्यक्ष महोदय,

- देश के करोड़ो किसानों, वंचितों, पिछड़ो, दलितों, गरीबो, उपेक्षितों, महिलाओं का विकास का मार्ग केवल सहकारिता के माध्यम से ही प्रशस्त हो सकता है।
- सहकारिता के बिना गरीब कल्याण और अंत्योदय की कल्पना संभव नहीं है।
- सहकारिता आंदोलन भारत के ग्रामीण समाज की प्रगति भी करेगा और एक नई समाजिक पूंजी की अवधारणा भी खड़ी करेगा।
- सहकारिता क्षेत्र कृषि व भारत की उन्नति का मुख्य स्तम्भ बन सकता था, लेकिन इतने दशकों तक किसी ने सहकारी क्षेत्र के बारे में नहीं सोचा।
- ऐसे समय पर जब सहकारिता आंदोलन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक स्वतंत्र नया सहकारिता मंत्रालय बनाकर सहकारिता क्षेत्र की उपेक्षा के युग को समाप्त कर सहकारिता की प्राथमिकता की युग की शुरूआत की है।

(02) →

- भारत की जनता के स्वाभाव में सहकारिता घुल–मिल गई है और संस्कार में सहकारिता है और यह कोई उधार लिया हुआ विचार (Concept) नहीं है इसलिए सहकारिता आंदोलन कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकता।
- माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के मन इच्छा है कि छोटे से छोटे व्यक्ति को विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाना, सहकारिता की प्रक्रिया से हर घर को समृद्ध बनाना और हर परिवार की समृद्धि से देश को समृद्ध बनाना यही सहकार से समृद्धि का मंत्र है।
- अगर छोटे–छोटे लोगो की बड़ी संख्या एक लक्ष्य के साथ एकजुट होकर, एक लक्ष्य के साथ, बंधुत्व भाव से एक दिशा में

काम करें तो एक बड़ी ताकत की निर्मिति हो सकती है यही सहकारिता का मूलमंत्र भी है।

- माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि सहकारिता के बगैर देश का समविकास असंभव है। हर व्यक्ति का समान विकास न कम्युनिस्ट, न पुंजीवादी थ्योरी से हो सकता है। यह सिर्फ सहकारिता से हो सकता है व इसी मॉडल को हमें आगे बढ़ाना है।
- किसी एक देश का आर्थिक विकास कई रास्तों से हो सकता है मगर हर व्यक्ति का आर्थिक विकास में योगदान और हर व्यक्ति तक कुछ न कुछ आर्थिक विकास का फायदा पहुँचे ये सिर्फ सहकारिता से हीं संभव है।

अध्यक्ष महोदय, भारत में सहकारिता की यह निश्चित व्याख्या सन् 1904 में अंग्रेजों ने कानून बनाकर की थी। कानून बनने के बाद अनेक पंजीकृत संस्थाएं इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए उतरीं। सहकारिता में समाजहित को देखते हुए सरकार द्वारा भी इसकी वृद्धि के प्रयास हुए। पुनः सहकारी समिति अधिनियम, 1912 अधिनियमित कर वर्ष 1904 अधिनियम के दोषों को दूर किया गया।

भारतीय संविधान के 97वें संशोधन के फलस्वरूप देश के नागरिको को सहकारी समितियों के गठन को मौलिक अधिकार दिया गया है। साथ ही राज्य के नीति निदेशक तत्व में संशोधन करते हुए राज्य सरकारो को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित करने की बृहत्तर जिम्मेवारी भी दी गई है।

अध्यक्ष महोदय, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से चल रहा सहकारिता अन्दोलन आज विराट रूप धारण कर चुका है और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके चलते देशवासी आर्थिक रूप से समृद्ध तो हुए हीं है साथ हीं बेरोजगारी की समस्या भी बहुत हद तक कम हुई है। एक अनुमान के अनुसार

इस समय देश भर में करीब 5 लाख से अधिक सहकारी समितियाँ सक्रिय है, जिनमें करोड़ो लोगो को रोजगार मिल रहा है। ये समितियाँ समाज के अनेक क्षेत्रो में काम कर रही है। लेकिन कृषि उर्वरक और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में इनकी भागीदारी सर्वाधिक है। अब तो बैंकिंग के क्षेत्र में भी सहकारी समितियो की संख्या निरंतर बढ़ रही है। लेकिन देश में सहकारी अन्दोलन राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति का साधन बनकर अनेक विसंगतियों के जाल फँसा दिया गया है।

⇒ (03) →

अध्यक्ष महोदय, समाज के बृहत्तर समुदाय, कमजोर वर्ग, वंचित वर्ग तथा महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को सहकारिता के माध्यम से फलीभूत करने के लिए आज के प्रतिस्पर्धी आर्थिक परिवेश में सहकारी समितियों को सबल और सक्षम बनाया जाना आवश्यक है ताकि वे अपने सदस्यों को सहकारिता से जुड़े कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा सहकारी संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के लिए सतत् प्रत्यनशील हो।

अध्यक्ष महोदय, आपको यह बताते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं केन्द्रीय गृह–सह–सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में देश में सहकारिता क्षेत्र में आमूल–चूल परिवर्तन लाने एवं इसके माध्यम से एक विकसित भारत के निर्माण के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गए हैं। देश के हित में नई सहकारिता नीति बनाई जा रही है, जिसके कार्यान्वयन से देश में एक नई सहकार क्रान्ति का सूत्रपात होगा तथा देश के किसानों एवं उपभोक्ताओं का बहुत ज्यादा लाभ होगा।

❖अधिप्राप्ति

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में राज्य के किसानों को पारदर्शी तरीके से उनके उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने के उद्देश्य से धान/गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य E-Procurement प्रणाली अन्तर्गत मोबाईल ऐप एवं वेब पोर्टल द्वारा ऑन लाईन व्यवस्था के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है।

अधिप्राप्ति कार्य कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधित किसानों के माध्यम से कराया जाता है। राज्य के चयनित पैक्स/व्यापार मंडल में निबंधित किसान धान/गेहूँ की बिक्री कर न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ PFMS के माध्यम से अपने खाते में निर्धारित समय के अन्तर्गत प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को अधिप्राप्ति से संबंधित जानकारी देने एवं उनके शिकायतों के त्वरित निष्पादन हेतु IVRS Call Center "सुगम" भी कार्यरत है जिसके तहत् पूरी व्यवस्था पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से संचालित होती है।

राज्य सरकार द्वारा धान अधिप्राप्ति कार्य हेतु 80,00.00 (आठ हजार) करोड़ रूपये राजकीय गारंटी के रूप में बिहार राज्य सहकारी बैंक/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को स्वीकृति दी गई है, जिसका उपयोग धान अधिप्राप्ति हेतु पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा कैश क्रेडिट के रूप में किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रबंधकीय अनुदान हेतु रू० 1,50,00.00 लाख (एक अरब पचास करोड़) रूपये का प्रावधान किया गया है। जिसके तहत ससमय सी.एम.आर. की आपूर्ति करनेवाले पैक्सों को 30रू० प्रति क्वींटल से 20रू० प्रति क्वींटल तक प्रोत्साहन के रूप में प्रबंधकीय अनुदान देने का प्रावधान है।

❖**कृषि रोड मैप**

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार जी की परिकल्पना से वर्ष 2008 से कृषि रोडमैप बनाकर राज्य का विकास

किया जा रहा है। राज्य के कृषि रोड मैप (वर्ष 2023–28) अन्तर्गत कृषि के समग्र विकास हेतु तैयार महत्वाकांक्षी योजना के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति में सहकारी समितियों को भी महत्वपूर्ण स्थान देते हुए इसे प्रमुख घटक के रूप में शामिल किया गया है। इसके तहत् पैक्सों/व्यापार मंडलों में आधारभूत संरचना के विकास हेतु 200 मीट्रिक टन, 500 मीट्रिक टन एवं 1000 मीट्रिक टन गोदाम का निर्माण कराया जा रहा है।

पैक्स/व्यापार मंडलों में भंडारण क्षमता की आवश्यकता को देखते हुए वर्ष 2022–23 में जिलों को 271 गोदाम के निर्माण हेतु 120.45 करोड़ रू० जिला को उपलब्ध करा दिया गया है। वर्ष 2023–24 में अबतक 113 गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है जिससे 0.654 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि हुई है एवं 463 गोदाम निमार्णधीन है जिसके पूर्ण होने पर 2.68 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि होगी।

वर्तमान में पैक्सों एवं व्यापार मंडलो में कुल 15.1295 लाख मे०टन का भण्डारण क्षमता सृजित किया गया है। जिसमें और भी वृद्धि की जा रही है।

निजी भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु निजी नवनिर्मित गोदामों को निविदा में प्राप्त दर पर दस वर्षों या उससे ज्यादा समय के लिये पैक्सों के माध्यम से किराये पर लेने की गारंटी की योजना विचाराधीन है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में गोदाम निर्माण हेतु रू० 1,19,87.30 लाख (एक अरब उन्नीस करोड़ सतासी लाख तीस हजार) रूपये का प्रावधान किया गया है।

❖मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना

राज्य के लघु एवं सीमांत कृषकों को कम शुल्क पर आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत उपकरण बैंक स्थापित किया जा रहा है।

जिससे राज्य की कृषि में मात्रात्मक एवं गुणात्मक अभिवृद्धि संभव हो। योजनान्तर्गत राज्य के सभी 8463 पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित की जानी है। योजनान्तर्गत प्रथम चरण में 2927 पैक्सों में प्रति पैक्स 15 लाख रूपये की दर से कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित था, जिसके लिए कुल रू० 439.05 करोड़ रूपये प्राप्त हुए। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक सब्जी सहकारी समितियों को भी आच्छादित करने की योजना है।

❖बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना

अध्यक्ष महोदय, सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य के सब्जी उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाना एवं ग्राहकों के लिए गुणवत्तापूर्ण तथा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर सब्जी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना प्रारम्भ की गई है। जिसके तहत राज्य में शीर्ष स्तर पर सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन (VegFed) भी गठित एवं कार्यरत है। फेडरेशन के अन्तर्गत पटना, तिरहुत एवं मिथिला कुल तीन संघ का गठन किया गया है। पटना संघ के अन्तर्गत पटना, नालन्दा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भोजपुर एवं बक्सर जिलों में प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियाँ (PVCS) गठित है। तिरहुत संघ के अन्तर्गत पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, मुजफ्फपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, सारण, सिवान एवं गोपालगंज जिलों में PVCS का गठन किया गया है तथा मिथिला संघ के अन्तर्गत दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिले के PVCS गठन है।

इस प्रकार वर्तमान में योजना का आच्छादन 3 संघों के माध्यम से राज्य के 20 जिलों में किया जा चुका है। इन 20 जिलों में कुल 300 प्रखंड स्तरीय PVCS का गठन हो चुका है। शीर्ष स्तर पर इन

300 PVCS में अबतक 38532 सब्जी उत्पादक किसान सदस्य बन चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में समितियों द्वारा पटना शहर में "तरकारी ब्राण्ड" नाम से ऑनलाईन सब्जी बिक्री कार्य भी किया जा रहा है जिसके माध्यम से अब तक कुल 33,820 आर्डर की सफलतापूर्वक आपूर्ति की गई है। तीनों संघ यथाः– पटना संघ, तिरहुत संघ एवं मिथिला संघ द्वारा अब तक किये गये सब्जी बिक्री का टर्न ओवर लगभग 107.45 करोड़ रूपये है।

अब तक कार्यान्वित योजना से प्राप्त अनुभव एवं आवश्यकता के आधार पर योजना का सम्पूर्ण राज्य में विस्तार प्रक्रियाधीन है।

PVCS में आधारभूत संरचनाओं के विकास किया जा रहा है। जिसमें 10 मे॰ टन का कोल्ड स्टोरेज, 20 मे॰टन का गोदाम, सब्जी मंडी, कार्यालय एवं कृषकों की सुविधा हेतु अन्य आवश्यक निर्माण की योजना को स्वीकृत दी गई है, जल्द हीं 10 जगहो पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस योजना हेतु 70,00.00 लाख (सत्तर करोड़) रूपये का प्रावधान किया गया है।

❖बिहार राज्य फसल सहायता योजना

अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य फसल सहायता योजनान्तर्गत खरीफ 2022 मौसम में कुल 286536 लाभान्वित किसानों को 296.83 करोड़ रू० की सहायता राशि का भुगतान किया गया है। रबी 2022–23 मौसम में भुगतान प्रक्रियाधीन है। खरीफ 2023 मौसम हेतु कुल 1596922 किसानों का निबंधन हो चुका है, इनमें से जाँचोपरांत भुगताान मार्च–अप्रैल 2024 में किया जाना है। रबी 2023–24 मौसम में दिनांक– 06.02.2024 तक कुल 3.01 लाख किसानों का निबंधन कराया गया है। निबंधन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 तक निर्धारित है।

NIC के तकनीकी सहयोग से विकसित बिहार राज्य फसल सहायता योजना पोर्टल को कम्प्यूटर सोसाईटी ऑफ इण्डिया के द्वारा E-Governance के लिए Award of Excellence प्रदान किया गया।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस योजना हेतु रू० 5,41,00.00 लाख (पाँच अरब एकतालीस करोड़) रूपये का प्रावधान किया गया है।

❖पैक्स कम्प्यूटराईजेशन

सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली द्वारा लागू केन्द्र प्रायोजित प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) हेतु कम्प्यूटरीकरण योजना को सहकारिता विभाग के संकल्प संख्या–9581, दिनांक–30.11.2022 द्वारा राज्य में लागू किया गया है।

राज्य में विद्यमान ग्राम पंचायत के सह–अंतक (Co-terminus) सभी पैक्सों को चरणबद्ध रूप से वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2026–27 की अवधि में कम्प्यूटरीकृत करने हेतु केन्द्रांश के रूप में कुल 149.40 करोड़ (एक अरब उन्चास करोड़ चालीस लाख) रूपये एवं राज्यांश के रूप में कुल 99.60 करोड़ (निन्यानवे करोड़ साठ लाख) रूपये कुल 249.00 करोड़ (दो अरब उनचास करोड़) रूपये व्यय किया जायेगा। भारत सरकार से स्वीकृति उपरांत प्रथम चरण में 4477 पैक्सों में कम्प्यूटरीकरण की कार्रवाई की जा रही है। द्वितीय चरण में 1601 पैक्सों का चयन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस योजना हेतु राज्यांश मद में रू० 6,42.00 लाख (छः करोड़ बियालीस लाख) रूपये एवं केन्द्रांश मद में रू० 27,63.00 लाख (सताईस करोड़ तिरसठ लाख) रूपये अर्थात कुल रू० 34,05.00 लाख (चौतीस करोड़ पाँच लाख) रूपये प्रावधानित किया गया है।

आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना में पुरस्कार स्वरूप राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने वाले पैक्सों को क्रमशः 15 लाख, 10 लाख एवं 7 लाख रूपये का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। इसी प्रकार जिला स्तर पर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने वाले पैक्सों को क्रमशः 5 लाख, 3 लाख एवं 2 लाख रूपये का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है।

❖सहकार भवन का निर्माण

प्रत्येक प्रमंडल/जिले में सहकारिता विभाग के प्रशासनिक कार्यालयों, अंकेक्षण कार्यालयों तथा सहकारी बैंकों को आपस में समन्वय स्थापित कर एक साथ कार्य करने तथा जिले के विभिन्न सहकारी समितियों में अनेक प्रकार के उत्पादों के विपणन हेतु स्थान उपलब्ध कराने तथा एक परिसर में सारी सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रमंडल/जिले में एक सहकार भवन बनाने की योजना है। अभी तक में 17 (सत्रह) सहकार भवन का निर्माण हो चुका है तथा पूर्णियाँ, सुपौल एवं जहानाबाद में निर्माणाधीन है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस योजना हेतु मांग संख्या–03 के अंतर्गत रू० 15,00.00 लाख (पंद्रह करोड़) रूपये का प्रावधान किया गया है।

❖पैक्सों के व्यवसाय का विविधीकरण

भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से पैक्सों के द्वारा की जाने वाली आर्थिक गतिविधियों का विविधीकरण किया जा रहा है। लगभग 5662 पैक्सों में सी० एस० सी० केन्द्र की स्थापना हो चुकी है। जन औषधि केन्द्र के रूप में कार्य करने हेतु 105 पैक्सों का चयन किया गया है, जिसमें से 11 पैक्सों को अनुज्ञप्ति भी प्राप्त हो चुकी है। 3394 पैक्स जन वितरण प्रणाली के अनुज्ञप्ति धारक है। 1637 पैक्स खाद–बीज का व्यवसाय कर रहें है। इन्हें प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र के रूप में विकसित किया

जा रहा है। राज्य के 02 पैक्सों में पेट्रोल/डिजल आउटलेट की स्थापना की गई है। इन गतिविधियों को सुगमतापूर्वक चलाने हेतु पैक्सों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

❖सहकारी बैंकों का आधुनिकीकरण

बिहार राज्य सहकारी बैंक एवं सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के द्वारा उपयोग की जा रही बैंकिंग सॉफ्टवेयर को उत्क्रमित करने की कार्रवाई चल रही है, जिससे से बैंक ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा उत्कृष्ट सेवायें दे सकें एवं वाणिज्यिक बैंकों से प्रतिस्पर्द्धा कर सकें।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में केन्द्रीय सहकारी बैंकों को अनुदान मद में रू० 16,00.00 लाख (सोलह करोड़) रूपये एवं निवेश मद में रू० 0.10 लाख (दस हजार) रूपये प्रावधानित किया गया है।

महोदय, मैं, आपके माध्यम से, सदन से अनुरोध करता हूँ कि माँग संख्या–9 के अन्तर्गत सहकारिता विभाग के लिए वर्ष 2024–25 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय, केन्द्र प्रायोजित स्कीम, केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम तथा राज्य स्कीम मद के अन्तर्गत व्यय हेतु रू० 12,09,36.44 लाख (बारह अरब नौ करोड़ छत्तीस लाख चौवालीस हजार) रूपये मात्र की माँग पारित की जाय।

⇒ (04) ⇒ —

⇒ (05) ⇒ —

⇒ (06) ⇒ —

मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना

योजना का आरंभ– मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना का आरंभ सितम्बर, 2020 में सहकारिता विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या–2325 दिनांक 17.09.2020 के माध्यम से राज्य में लागू किया गया।

योजना का उद्देश्य :– राज्य के पैक्सों में कृषि उपकरण बैंक स्थापित करना है, जिसके माध्यम से लधु एवं सीमांत कृषकों को आधुनिक कृषि उपकरण कम दर पर उपलब्ध हो सके तथा राज्य की कृषि में मात्रात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि संभव हो। साथ ही पैक्सों में भी आय सृजन हो और वे व्यावसायिक विविधीकरण के माध्यम से आर्थिक रूप से सबल हो सके।

योजना क्या है :– बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य की कृषि व्यवस्था के यांत्रिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसमें चयनित पैक्सों के द्वारा पारदर्शिता एवं मितव्ययिता के दृष्टिकोण से जेम पोर्टल के माध्यम से कृषि संयंत्रों का क्रय किया जाता है। योजनान्तर्गत प्रत्येक पैक्स से उपलब्ध करायी गयी 15 लाख रुपये में 50 प्रतिशत ऋण एवं 50 प्रतिशत अनुदान है। पैक्सों से ऋण के रूप में उपलब्ध करायी गयी राशि 05 वर्षों में 10 अर्द्धवार्षिक किस्तों में 10.36 प्रतिशत ब्याज दर के साथ वसूल किया जाना है।

योजना की प्रगति :–

- योजनान्तर्गत 2,899 पैक्सों को कृषि संयंत्रों के क्रय हेतु प्रति पैक्स मो॰ 15 लाख रुपये की दर से 434.85 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये है।
- अभी तक विभिन्न पैक्सों में 16,926 कृषि यंत्रों के क्रय हेतु GeM Portal पर आमंत्रित किए गए निविदा के विरूद्ध 14,282 कृषि यंत्रों की आपूर्त्ति किया जा चुका है।
- वर्तमान में 118 पैक्सों के अनुरोध पर 17 करोड़ 70 लाख की राशि इस योजनान्तर्गत कृषि संयंत्रों के क्रय हेतु उपलब्ध करायी जा रही है। अन्य किसी भी योग्य पैक्स द्वारा आवेदन किये जाने पर इस योजनान्तर्गत राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

योजना का कार्यान्वयनः– योजना अंतर्गत पैक्सों में स्थापित कृषि संयंत्र बैंक से किसानों को प्रतिस्पर्द्धात्मक दर पर यंत्रों को किराये पर उपलब्ध कराया जा रहा है। यंत्रों के किराये का निर्धारण प्रमण्डलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ की अध्यक्षता में गठित कमिटि द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसानों को यंत्रों की बुकिंग हेतु Mobile App की सुविधा प्रदान की गई है।

योजना का विस्तार :– इसके अतिरिक्त बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत गठित प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों को भी इस योजना में जोड़ा गया है। जिसमें प्रथम चरण में 100 सब्जी उत्पादक समितियों को कृषि संयंत्र हेतु 15 लाख की दर से राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

भारत सरकार की योजनाएँ

सहकारिता में सर्वसमावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की अपार क्षमता है। इसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 6 जुलाई 2021 को भारत सरकार द्वारा 'सहकार से समृद्धि' के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक अलग 'सहकारिता मंत्रालय' का गठन किया गया। मंत्रालय के गठन के उपरांत इसने 'सहकार से समृद्धि' के तहत सहकारिता के विकास के लिए कई योजनाओं पर कार्य करना शुरू किया।

राष्ट्रीय सहकारिता डाटाबेस

राष्ट्रीय सहकारिता डाटाबेस के निर्माण का प्राथमिक लक्ष्य और उद्देश्य सूचना आधारित एक प्रणाली विकसित करना है, जहाँ एक क्लिक पर समितियों से संबंधित सभी सूचनाएँ प्राप्त की जा सके।

इसके तहत किए जा रहे कार्य निम्नवत हैः

- इसके तहत प्रथम चरण में पैक्स, डेयरी एवं फिशरीज सहकारी समितियों को सहकारी पोर्टल पर मैपिंग किया गया।
- द्वितीय चरण में सभी राष्ट्रीय सहकारी समितियों एवं संघों को सहकारी पोर्टल पर मैपिंग किया गया।
- तृतीय चरण में अन्य प्रकार की सभी सहकारी समितियों को सहकारी पोर्टल पर मैपिंग किया गया।
- राज्य के सभी पंचायतों को सहकारी समितियों यथा पैक्स, डेयरी इत्यादि से आच्छादित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
- सहकारी समितियों से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के कुल 26640 समितियों से संबंधित डाटा का ऑनलाईन पोर्टल पर संग्रहण किया जा चुका है।

पैक्सों में कॉमन सर्विस केन्द्र की स्थापना

ई–सेवाओं की बेहतर पहुंच के लिए पैक्सों में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की जा रही है। इस योजना के तहत पैक्स ग्रामीण नागरिकों को बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन, स्वास्थ्य सेवाएँ, कानूनी सेवाएँ, कृषि उपकरण जैसे कृषि उपादान, पैन कार्ड, आईआरसीटीसी, रेल, बस, हवाई टिकट बुकिंग, आरटीपीएस पर उपलब्ध सेवाओं जैसी 300 से अधिक सेवाएँ प्रदान कर सकेंगे। पैक्स कम्प्यूटरीकरण योजना पैक्सों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में काम करने में मदद करेगा। अब तक 5534 पैक्सों में कॉमन सर्विस केन्द्र की स्थापना किया जा चुका है, जिसमें से 2240 पैक्सों का आई0डी0 क्रियाशील हो चुका है।

पैक्सों के द्वारा नए किसान उत्पादक संगठन (FPOs) का गठन

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में 1100 अतिरिक्त एफपीओ के आवंटन का निर्णय लिया गया है। पैक्स भी अब FPO के रूप में कृषि संबंधित अन्य आर्थिक कार्यकलाप करने में सक्षम होगी। इसके माध्यम से सहकारी समिति अपने सदस्यों को आवश्यक बाजार लिंकेज प्रदान कर उनकी उपज के उचित मूल्य दिलाने में भी सहायक होगी। वित्तीय वर्ष 2023–24 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से 100 पैक्सों में FPO निबंधित करने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें से 98 पैक्सो का चयन हो चुका है।

पैक्सों में पेट्रोल पम्प के रिटेल आउटलेट

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पैक्सों में रिटेल आउटलेट खोलने की सहमति दे दी गई है। वर्तमान में तीनों कम्पनियों के द्वारा CC2 कैटेगरी के तहत पैक्सों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पैक्सों में पेट्रोल पम्प के रिटेल आउटलेट की स्थापना के साथ ही पैक्सों के मुनाफे में वृद्धि होगी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगें। इसके माध्यम से पैक्सों को बहुद्देश्यीय व्यावसायिक संस्था के रूप में विकसित किए जाने में सहायता मिलेगी।

अभी तक 11 पैक्सों द्वारा आवेदन दिया गया है, जिसमें से 3 पैक्सों को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 द्वारा लाइसेंस प्राप्त हो चुका है।

पैक्सों में जन औषधि केन्द्र की स्थापना

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से पैक्सों में जन औषधि केन्द्र खोले जाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत सस्ती जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता सामान्य एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक आसानी से हो जाएगी। इस योजना के तहत उत्पाद बास्केट में 1759 दवाएं और 280 सर्जिकल उपकरण शामिल हैं, जिन्हे जन औषधि केन्द्र के माध्यम से बेचा जा सकता है। इसके लिए सक्षम प्राधिकार से ड्रग लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इससे ग्रामीण स्तर पर सस्ती जेनरिक दवाइयाँ आम लोगों को उपलब्ध हो सकेगा। इसके अतिरिक्त पैक्सों के आर्थिक सुदृढीकरण के साथ–साथ रोजगार के अतिरिक्त अवसर भी सृजित हो सकेंगें।

अभी तक इस योजना के तहत 36 पैक्सों द्वारा ड्रग लाइसेंस हेतु आवेदन किया गया है, जिसमें से 11 पैक्सों को ड्रग लाइसेंस प्राप्त हो चुका है।

प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र के रूप में पैक्स

भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में कार्यशील पैक्स को उर्वरक खुदरा विक्रेता के रूप में कार्य करने हेतु पात्र बनाए जाने, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्रों व उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन उद्यमियों के रूप में भी कार्य करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही ड्रोन का उपयोग संपत्ति सर्वेक्षण के लिए भी किया जा सकेगा। इन प्रयासों से किसानों को पैक्स स्तर पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चत होगी तथा पैक्स के लिए व्यवसाय के नए अवसर सृजित होंगें।

बिहार में 3106 पैक्सों को खाद बीज व्यवसाय का अनुज्ञप्ति प्राप्त है। जिसमें से अभी तक 1716 पैक्सों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र के रूप में विकसित किया जा चुका है।

पैक्सों में Micro-ATM एवं सदस्यों को Rupay किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा

पैक्सों को व्यापार में सुगमता, पारदर्शिता, वित्तीय समावेश सुनिश्चित करने हेतु नाबार्ड के सहयोग से 'घर बैठे वित्तीय सेवाएं' प्रदान करने के लिए Micro-ATM दिए जाने की योजना है। इससे बैंक और पैक्सों के आर्थिक क्रियाकलापों में वृद्धि होगी।

ग्रामीण सहकारी बैंकों की पहुंच तथा क्षमता का विस्तार करने तथा पैक्सों के सदस्यों को यथावश्यक चल निधि उपलबध कराने हेतु संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में पैक्स सदस्यों के खाते खोले जा रहें हैं तथा नाबार्ड के सहयोग से खाताधारकों को Rupay किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। Rupay किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैक्स सदस्यों को उचित दर पर ऋण की सुविधा उपलबध होगी। साथ ही इस कार्ड का उपयोग अन्य वित्तीय भुगतान के लिए भी किया जा सकेगा।

"पैक्स कम्प्युटरीकरण योजना"

- "प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) का कम्प्युटरीकरण योजना" एक केन्द्र प्रायोजित योजना है।
- इस योजना का कुल व्यय 249.00 करोड़ (दो सौ उनचास करोड़) रुपये है। जिसमें केन्द्रांश 60 प्रतिशत (149.40 करोड़ रुपये) एवं राज्यांश 40 प्रतिशत (99.60 करोड़ रुपये) है।
- इस योजना के अन्तर्गत राज्य में विद्यमान ग्राम पंचायत के सह–अंतक (Co-terminous) सभी पैक्सों को चरणबद्ध रुप से वित्तीय वर्ष–2022–23 से 2026–2027 की अवधि में कम्प्युटरीकृत किया जाना हैं।
- कम्प्युटरीकरण योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायत स्तर पर गठित पैक्स के कार्यो को सुगम एवं पारदर्शी बनाने के साथ–साथ उनकी दक्षता एवं लाभ में वृद्धि करते हुए भविष्य में उन्हें मल्टी सर्विस सेन्टर के रूप में विकसित करना है।
- इस योजना के अन्तर्गत प्रति पैक्स 3.91 लाख रुपये का व्यय निर्धारित है।
- इस योजना के अन्तर्गत पैक्सों हेतु हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा डिजिटाईजेशन, ट्रेनिंग एवं हैंड होल्डिंग सपोर्ट आदि की व्यवस्था शामिल है।
- केन्द्रांश के रूप में कुल 32.95 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त है।
- केन्द्रांश की राशि एवं उसके समतुल्य राज्यांश की राशि सहित कुल राशि 54.92 करोड़ रुपया योजना हेतु SNA (Single Nodal Account) खाता में ट्रांसफर किया जा चुका है।
- योजनान्तर्गत सिस्टम इन्ट्रीग्रेटर (System Integrator) के कार्य हेतु मेसर्स च्वाईस कसंलटेन्सी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी का चयन किया गया है। उक्त कम्पनी द्वारा 4477 पैक्सों में कार्य किया जा रहा है।
- प्रथम चरण में 4477 पैक्सों में कम्प्यूटीकरण की कार्रवाई की जा रही है। पुनः 1601 पैक्सों का द्वितीय चरण में कम्प्युटरीकरण हेतु भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।

कृषि रोडमैप

परिचय

कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन में सहकारिता विभाग की भूमिका किसानों के लिए फसल चक्र की समग्र आवश्यकताओं यथा कृषि उपादान (खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि साख आदि), भंडारण क्षमता का सृजन, कृषि उपकरण बैंक की स्थापना, कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण, खाद्यान्नों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की उपलब्धता तथा सहकारी प्रक्षेत्र में संस्थागत विकास हेतु प्रशिक्षण के रूप में परिभाषित की गई है। इन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के संदर्भ में सहकारिता विभाग के द्वारा प्रशंसनीय उपलब्धियाँ प्राप्त की गई है।

पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण–सह–कार्यालय की स्थापना से सहकारी संस्थाओं को भौतिक पहचान मिलने के साथ–साथ व्यवसाय विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। राज्य के कुल 6973 पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में गोदाम–सह–कार्यालय निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिसके माध्यम से लगभग 15.1295 लाख एम.टी. भंडारण क्षमता का सृजन किया गया है। भंडारण क्षमता के सृजन के परिणामस्वरूप सहकारी समितियों के माध्यम से खाद, जनवितरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति का कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 473 पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में राईस मिल की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से अधिप्राप्त धान की मिलिंग कर राज्य खाद्य निगम को आपूर्ति की जा रही है।

अधिप्राप्ति

राज्य सरकार के द्वारा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ सुनिश्चित कराने के लिए खाद्यान्न अधिप्राप्ति (धान एवं गेहूँ) का कार्य पैक्सों एवं व्यापार मंडलों को सौंपा गया है। खाद्यान्न अधिप्राप्ति वर्ष 2021–22 में 6.42 लाख किसानों को 44.90 लाख एम.टी. धान की अधिप्राप्ति के विरूद्ध 8710 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया। अधिप्राप्ति वर्ष 2022–23 में 5.77 लाख किसानों को 42.04 लाख एम.टी. धान की अधिप्राप्ति के विरूद्ध कुल 8577 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। वर्तमान अधिप्राप्ति वर्ष 2023–24 में 3.73 लाख किसानों से 30.79 लाख मे.टन धान की अधिप्राप्ति की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के क्षेत्र में सहकारी समितियों की सघन एवं सार्थक भागीदारी के फलस्वरूप किसानों की आय में वृद्धि हुई है तथा बाजार की अनिश्चितताओं पर काबू पाने में सहायता मिली है।

किसान क्रेडिट कार्ड

राज्य के सहकारी बैंकों के माध्यम से पैक्स के सदस्य किसानों के बीच अल्पकालीन कृषि ऋण का वितरण किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) के माध्यम से किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड पर भुगतेय ब्याज दर 9 प्रतिशत है, जिसपर ब्याज में 2 प्रतिशत अनुदान तथा समय पर ऋण भुगतान हेतु 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य के सहकारी बैंकों के द्वारा 92573 किसानों के बीच 271.60 करोड़ रूपए की राशि अल्पकालीन कृषि ऋण के रूप में वितरित की गई है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य के सहकारी बैंकों द्वारा 62367 किसानों के बीच 182.58 करोड़ की राशि वितरित की गई है।

साथ ही राज्य के सहकारी बैंकों द्वारा अधिप्राप्ति कार्य हेतु कैश क्रेडिट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना

लघु एवं सीमांत किसानों को प्रतिस्पर्द्धात्मक दर पर आधुनिक कृषि तकनीक का लाभ सुनिश्चित कराने तथा कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु सहकारिता विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राज्य के 2899 चयनित पैक्सों में कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने हेतु प्रति पैक्स 15 लाख रुपये की दर से 434.85 करोड़ उपलब्ध कराया गया है।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना

बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ 2018 से राज्य में लागू है। उक्त योजना के अंतर्गत कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधित रैयत एवं गैर रैयत किसानों को फसल क्षति की स्थिति में लाभान्वित किया जाता है। खरीफ 2018 से खरीफ 2023 मौसम तक क्रियान्वित 11 मौसम अन्तर्गत कुल 19909113 (एक करोड़ निन्यानवे लाख नौ हजार एक सौ तेरह) किसानों द्वारा निबंधन किया गया है। योजना के दिशा–निर्देशों के तहत अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना से प्राप्त फसल कटनी प्रयोग आधारित प्राप्त उपज दर आँकड़ों के आधार पर योग्य ग्राम पंचायतों के निबंधित/आवेदक किसानों को सत्यापनोपरांत 28,45,136 (अट्ठाइस लाख पैंतालिस हजार एक सौ छत्तीस) लाभुक किसानों को 1824.37 (अठारह सौ चौबीस करोड़ सैंतीस लाख) करोड़ का भुगतान किया गया है।

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना

राज्य के सब्जी उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने एवं ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण एवं उचित मूल्य पर सब्जी की आपूर्ति करने के उद्देश्य से बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना विभाग द्वारा संचालित है। इस योजना के तहत राज्य के 20 जिलों के 300 प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी सहकारी समितियों में 38,858 सदस्य बनाये जा चुके है। अब तक सब्जी समितियों द्वारा 62214.52 एम.टी. सब्जी का व्यवसाय कर 109.04 करोड़ रूपए का टर्न ओवर किया गया है।

पैक्स कम्प्यूटराईजेशन योजना

पैक्सों के कम्प्यूटराइजेशन का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसके फलस्वरूप पैक्सों के कार्यकलाप में पारदर्शिता आएगी तथा व्यवसायिक विविधीकरण का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। विभाग की योजना है कि राज्य के पैक्सों में व्यवसाय का विविधीकरण इस प्रकार किया जाए कि पैक्स कृषि चक्र की समग्र व्यवसायिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र की गैर–कृषि व्यवसायिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। प्रथम चरण में 4477 पैक्सों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य किया जा रहा है।

सुगम कॉल सेंटर

सहकारिता विभाग के विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में ससमय एवं समग्र जानकारी उपलब्ध कराने तथा इन योजनाओं के संबंध में शिकायतों के ससमय निवारण हेतु विभाग के द्वारा टॉल फ्री कॉल सेंटर–"सुगम"(1800 1800 110) की स्थापना की गई है। अधिप्राप्ति व्यवसाय, बिहार राज्य फसल सहायता योजना एवं अन्य विभागीय योजनाओं के सफलतापूर्वक संचालन में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

चतुर्थ कृषि रोड मैप (2023–28)

चतुर्थ कृषि रोड मैप (2023–28) के अंतर्गत सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य के विकास को समग्रता प्रदान करने हेतु प्राथमिकताओं का निर्धारण इस प्रकार किया गया है कि किसानों की कृषि एवं गैर–कृषि व्यवसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय स्तर पर संस्थागत रूप से निरंतरता के साथ की जा सके।

राज्य के पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण–सह–कार्यालय की स्थापना से सहकारी संस्थाओं को भौतिक पहचान मिलने के साथ–साथ व्यवसाय विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत विभाग की योजना है कि शेष सभी पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में लगभग 10 लाख एम॰टी॰ भंडारण क्षमता का सृजन किया जाएगा।

राज्य सरकार के द्वारा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ सुनिश्चित कराने के लिए खाद्यान्न अधिप्राप्ति (धान एवं गेहूँ) का कार्य पैक्सों एवं व्यापार मंडलों द्वारा किया जा रहा है। विभाग की योजना है कि आगामी वर्षों में अधिप्राप्ति कार्य में राज्य के सभी पैक्सों एवं व्यापार मंडलों की सहभागिता सुनिश्चित किया जा सके।

राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को प्रतिस्पर्द्धात्मक दर पर आधुनिक कृषि तकनीक का लाभ सुनिश्चित कराने तथा कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु सहकारिता विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना का क्रियान्वयन जा रहा है। चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत कृषि उपकरण बैंक के सुचारु क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। साथ ही मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना की अवशेष राशि से चयनित प्राथमिक सब्जी, उत्पादक सहकारी समितियों में कृषि उपकरण बैंक की स्थापना की जानी है।

राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2018 से बिहार राज्य फसल सहायता योजना लागू की गई है। इसका उद्देश्य मूलतः फसलों के उत्पादन में ह्रास की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए उन्हें अगली फसल के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना में नए फसलों खासकर सब्जियों को इस योजना में समाहित किया किया गया है, ताकि सब्जी उत्पादक किसानों को भी फसल क्षति की स्थिति में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जा सके।

राज्य के पैक्सों को बहुद्देश्यीय व्यवसायिक संस्था के रूप में विकसित करने हेतु पैक्स कम्प्यूटराइजेशन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। चतुर्थ कृषि रोड मैप में राज्य के सभी पैक्सों में कम्प्यूटराइजेशन का कार्य पूर्ण किया जाना है। राज्य के पैक्सों में व्यवसाय का विविधीकरण इस प्रकार से किया जाएगा कि पैक्स कृषि चक्र की समग्र व्यवसायिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र की गैर–कृषि व्यवसायिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

राज्य के सहकारी बैंकों के माध्यम से पैक्स के सदस्य किसानों के बीच अल्पकालीन ऋण वितरण का कार्य किसान क्रेडिट कार्ड (के॰सी॰सी॰) के माध्यम से किया जाता है। इस योजना का विस्तार सभी जरूरतमंद किसानों तक किया जा रहा है।

कृषि रोडमैप वर्ष 2023–28 का वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यः–

1॰ भौतिक लक्ष्य (प्रस्ताव) –

क्र॰ सं॰	1	2	3	4	5	6	7
		2023–24	2024–25	2025–26	2026–27	2027–28	कुल
1	1) कृषि साख में अभिवृद्धि (क) किसान क्रेडिट कार्ड (संख्या)	80000	90000	100000	110000	120000	5,00,000
	(ख) साख प्रवाह (करोड़ में)	250	270	300	330	350	1500
2	पैक्स/व्यापार मण्डल में भण्डारण क्षमता में अभिवृद्धि (लाख मे॰टन)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	10.00
3	सहकारी समितियों द्वारा व्यवसाय विकास (क) कृषि आदानों की आपूर्ति हेतु अनुज्ञप्ति	500	500	500	500	500	2,500
	(ख) अधिप्राप्ति (पैक्स एवं व्यापार मंडल को अधिप्राप्ति कार्य में शामिल करने का लक्ष्य)	7500	7600	7700	7800	8000	–
4	प्रशिक्षण/कार्यशाला/संगोष्ठी के माध्यम से क्षमता वर्धन (क) सहकारी प्रशिक्षण संस्थान पूसा का आधुनिकीकरण, निर्माण एवं प्रशिक्षण।	नये भवन का निर्माण एवं पुराने भवन का जिर्णोद्धार।					
	(ख) पैक्स/व्यापारमंडल के कार्यकारिणी सदस्यों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण (संख्या)	600	600	600	600	600	3,000
	(ग) पैक्स प्रबंधकों/सदस्यों का वार्षिक प्रशिक्षण (संख्या)	500	2000	2000	2000	2000	8,500
	(घ) विभाग के अधिकारी/कर्मी का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण (संख्या)	300	300	300	300	300	1,500

5	पैक्स कम्प्यूटराइजेशन	2000	2500	3558	–	–	8058
6	बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत किसानों का निबंधन/आच्छादन (लक्ष्य–लाख में)	25	28	30	32	35	150

वित्तीय लक्ष्य –

कार्यक्रम — लक्ष्य (राशि लाख में)

क्र.सं.	1	2	3	4	5	6	7
		2023–24	2024–25	2025–26	2026–27	2027–28	कुल
1	1) कृषि साख में अभिवृद्धि (क) किसान क्रेडिट कार्ड (राशि) (ख) वार्षिक साख प्रवाह ('क' की राशि सहित)	25000 420000	27000 440000	30000 460000	33000 480000	35000 500000	150000 2300000
2	अधिप्राप्ति	950000	950000	1000000	1050000	1100000	5050000
3	पैक्स/व्यापार मण्डल में भण्डारण क्षमता में अभिवृद्धि (लाख मे.टन)	3761.60	3761.60	3761.60	3761.60	3761.60	18808.00
4	प्रशिक्षण/कार्यशाला/संगोष्ठी के माध्यम से क्षमता वर्धन (क) सहकारी प्रशिक्षण संस्थान पूसा का आधुनिकीकरण, निर्माण एवं प्रशिक्षण। (ख) पैक्स/व्यापारमंडल के कार्यकारिणी सदस्यों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण (ग) पैक्स प्रबंधकों/सदस्यों का वार्षिक प्रशिक्षण (घ) विभाग के अधिकारी/कर्मी का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण	 176 50 10 25	 141 50 10 25	 – 50 10 25	 – 50 10 25	 – 50 10 25	 317 250 50 125
5	पैक्स कम्प्यूटराइजेशन	6180	7725	10995	–	–	24900
	कुल (क्रमांक 3+4+5 का योग)	10202.60	11712.60	14841.60	3846.60	3846.60	44450.00

अधिप्राप्ति : एक सामान्य परिचय

परिचय :– राज्य में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजना (DCP) के अन्तर्गत धान एवं गेहूँ की अधिप्राप्ति की जाती है। धान एवं गेहूँ की अधिप्राप्ति पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के माध्यम से की जा रही है। राज्य में धान एवं गेहूँ अधिप्राप्ति E-Procurement प्रणाली के अन्तर्गत किया जाता है, जिसमें विभागीय पोर्टल अन्तर्गत मोबाईल ऐप के माध्यम से ऑनलाईन व्यवस्था अन्तर्गत सभी कार्य का निष्पादन किया जाता है।

उद्देश्य :– धान एवं गेहूँ अधिप्राप्ति का उद्देश्य किसानों को आपात बिक्री (Distress Sale) से बचाते हुए उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कराना है। अधिप्राप्त धान से तैयार चावल एवं गेहूँ का उपयोग राज्य खाद्य निगम द्वारा जन कल्याणकारी योजना अन्तर्गत किया जाता है।

उपलब्धि :–

विगत तीन वर्षों में धान अधिप्राप्ति का प्रतिवेदन :–

खरीफ विपणन वर्ष	लक्ष्य	किसान की संख्या	अधिप्राप्ति की मात्रा	प्रतिशत
2021–22	45.00 लाख मे.टन	6.42 लाख	44.90 लाख मे.टन	99.78 प्रतिशत
2022–23	45.00 लाख मे.टन	5.77 लाख	42.04 लाख मे.टन	93.42 प्रतिशत
2023–24	45.00 लाख मे.टन	3.73 लाख	30.79 लाख मे.टन	68.44 प्रतिशत

धान अधिप्राप्ति में कमी का कारण :–

1. इस वर्ष धान का बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर या उसके आस–पास रहने के कारण किसानों द्वारा सहकारी क्रय केन्द्रों के साथ–साथ खुले बाजार में निजी क्रेताओं को भी बिक्री की गई।
2. राज्य के आंतरिक आर्थिक विकास के तहत इथनॉल इकाईयों की स्थापना होने के कारण इसकी मांग उसमें भी रहने के कारण धान का बाजार मूल्य बढ़ाने में अहम भूमिका रही है।
3. सीमावर्ती राज्य झारखण्ड में राज्य सरकार द्वारा 2183 (न्यूनतम समर्थन मूल्य)+117 (बोनस)=2300/– रूपये प्रति क्विंटल तथा छतीसगढ़ में 2183 (न्यूनतम समर्थन मूल्य)+917 (बोनस)=3100/– रूपये प्रति क्विंटल धान खरीद के कारण भी धान का बाजार मूल्य बढ़ने में अहम भूमिका रही है।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना

- राज्य सरकार द्वारा खरीफ–2018 मौसम से "बिहार राज्य फसल सहायता योजना" लागू की गई है।
- बिहार राज्य फसल सहायता योजना का मूल उद्देश्य फसलों के उत्पादन में ह्रास की परिस्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए उन्हें अगली फसल के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना, प्रतिकूल परिस्थितियों में किसानों की आय में निरंतरता बनाए रखना तथा किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करते हुए राज्य में कृषि को लाभप्रद व्यवसाय के रूप में विकसित करना है।
- इस योजना का लाभ अन्य योजनाओं यथा–कृषि इनपुट अनुदान योजना एवं डीजल अनुदान योजना के लाभार्थियों को भी प्राप्त होगा।
- योजना के तहत् आवेदन करने हेतु किसानों को किसी प्रकार के शुल्क/प्रीमियम का भुगतान नहीं करना है।
- **योजना की प्रमुख विशेषताएँ :–**
  - **आच्छादित किसान :–**

(i) रैयत किसान – ऐसे सभी किसान, जो अपनी रैयती भूमि पर खेती स्वयं करते हों।
(ii) गैर–रैयत किसान – ऐसे सभी किसान, जो दूसरे रैयतों की भूमि पर खेती करते हों।
(iii) आंशिक रूप से रैयत एवं गैर–रैयत दोनों

- **इन्डेमनिटी (जोखिम) स्तर :–** प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के उत्पादन का कार्य उच्च जोखिम का है। अतः किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए इस योजना में 70 प्रतिशत इन्डेमनिटी स्तर का प्रावधान किया गया है।
- **थ्रेशहोल्ड उपज :–** अधिसूचित फसल का पिछले 07 वर्षों की औसत उपज एवं इन्डेमनिटी स्तर का गुणा करने पर प्राप्त उपज संबंधित फसल का थ्रेशहोल्ड उपज होगी।
- **आच्छादित/सहायता राशि की अधिसीमा**

(i) थ्रेशहोल्ड उपज की तुलना में वास्तविक उपज में 20% तक ह्रास की स्थिति में सत्यापन के उपरान्त 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम दो (02) हेक्टेयर तक कुल 15,000 रुपये सहायता राशि अनुमान्य है।

(ii) थ्रेशहोल्ड उपज की तुलना में वास्तविक उपज में 20% से ज्यादा ह्रास की स्थिति में सत्यापन के उपरान्त 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम दो (02) हेक्टेयर तक कुल 20,000 रुपये सहायता राशि अनुमान्य है।

- **आच्छादित फसल**

खरीफ :– अगहनी धान, भदई– मकई एवं सोयाबीन। खरीफ 2023 मौसम से सब्जी फसल यथा – आलू, बैंगन, टमाटर एवं गोभी को भी आच्छादित किया गया है।

रबी :– गेहूँ, रबी–मकई, चना, मसूर, अरहर, राई–सरसो, ईख, प्याज एवं आलू। रबी 2023–24 मौसम में सब्जी फसल यथा– बैंगन, टमाटर, गोभी एवं मिरचाई को भी आच्छादित किया गया है।

- खरीफ 2023 मौसम से रैयत श्रेणी के किसानों को गत वित्तीय वर्ष में निर्गत भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र अपलोड करने की सुविधा दी गई है। साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना हेतु कृषि विभाग, बिहार, पटना द्वारा संधारित एवं सत्यापित रैयत किसान बिहार राज्य फसल सहायता योजनान्तर्गत सिर्फ रैयत श्रेणी अथवा आंशिक रूप से रैयत एवं गैर–रैयत दोनों श्रेणी में ही आवेदन करने का प्रावधान किया गया है।
- **योजना के क्रियान्वयन हेतु सक्षम प्राधिकार :–**

(i) **राज्य स्तर पर** :– राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु सक्षम प्राधिकार विकास आयुक्त, बिहार सरकार की अध्यक्षता में गठित **राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC)** है।

(ii) **जिला स्तर पर** :– जिला स्तर पर योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु सक्षम प्राधिकार जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित **जिला स्तरीय समन्वय समिति (DLCC)** है।

- <u>सहायता राशि का भुगतान</u>

इस योजना के तहत् अनुमान्य सहायता राशि का भुगतान लाभार्थी किसानों को DBT के माध्यम से उनके आधार से संबद्ध बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जाता है।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना की प्रगति

बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ 2018 मौसम से क्रियान्वित है। खरीफ 2018 से खरीफ 2023 मौसम तक क्रियान्वित 11 मौसम अन्तर्गत कुल 19909113 (एक करोड़ निन्नावे लाख नौ हजार एक सौ तेरह) किसानों द्वारा निबंधन/किया गया है। योजना के दिशानिर्देशों के तहत अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार, पटना से प्राप्त फसल कटनी प्रयोग आधारित प्राप्त उपज दर आकड़ों के आधार पर योग्य ग्राम पंचायतों के निबंधित/आवेदक किसानों को सत्यापनोपरान्त 2845136 (अठाईस लाख पैतालिस हजार एक सौ छत्तीस) लाभुक किसानों को 1824.37 (अठारह सौ चौबीस करोड़ सैतीस लाख) करोड़ का भुगतान किया गया है। मौसमवार प्रगति निम्न रूपेण है:–

मौसम	निबंधित किसानों की संख्या				लाभार्थी किसानों की संख्या एवं राशि	
	कुल	रैयत	गैर–रैयत	रैयत एवं गैर–रैयत	संख्या	राशि (करोड़ में)
खरीफ 2018	1150627	515314	635213	--	453005	368.64
रबी 2018–19	1754350	865839	888511	—	180667	74.40
खरीफ 2019	2494495	1120162	1370287	4046	400417	288.28
रबी 2019–20	1955512	831812	1095328	26372	393520	185.14
खरीफ 2020	3929109	1623343	2245751	60014	472374	230.44
रबी 2020–21	1333100	406554	896979	29567	179715	70.43
खरीफ 2021	1566432	356317	1187637	22478	319354	207.23
रबी 2021–22	1294600	240482	1039979	14139	155936	101.28
खरीफ 2022	1664944	234358	1402632	27954	286536	296.83
रबी 2022–23	1169128	129139	1025070	14919	भुगतान प्रक्रियाधीन	
खरीफ 2023	1596922	78256	858934	659732	भुगतान मार्च/अप्रैल 2024 में	

मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना

- सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–3622 दिनांक–21.12.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष–2023–24 में 'मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स' प्रोत्साहन योजना लागू किया गया है।
- योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष–2023–24 में 3,97,00,000.00 (तीन करोड़ सन्तानवे लाख) रुपया व्यय किया जाना है।
- योजना का उद्देश्य स्वच्छ प्रतियोगिता के आधार पर पैक्सों को आदर्श पैक्स के रूप में विकसित करना है।
- योजना अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिले के तीन पैक्सों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 5 लाख रुपये, 3 लाख रुपये एवं 2 लाख रुपये की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा।
- राज्य स्तर पर भी तीन पैक्सों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 15 लाख रुपये, 10 लाख रुपये एवं 7 लाख रुपये की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। उक्त पुरस्कार की राशि के साथ–साथ पैक्सों को प्रमाण–पत्र एवं ट्रॉफी भी दिया जायेगा ।
- योजनान्तर्गत पैक्सों का चयन द्विस्तरीय है।
- पैक्सों द्वारा प्राप्त ऑन–लाईन आवेदन की समीक्षा हेतु जिलास्तर पर संबंधित प्रमण्डलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ की अध्यक्षता में कमिटी गठित है, तथा राज्यस्तर पर समीक्षा हेतु संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में कमिटी गठित है।
- इस योजना के अन्तर्गत 1209 पैक्सों द्वारा आवेदन समर्पित किया गया है।

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना

1. परिचय –

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का कार्यान्वयन त्रिस्तरीय सहकारी संरचना के माध्यम से किया जा रहा है। जहाँ प्रखंड स्तर पर सब्जी उत्पादक किसान मिलकर प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लि॰ (PVCS), क्षेत्रीय स्तर पर कुछ जिलों के PVCS को सम्मिलत करते हुए सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ एवं शीर्ष स्तर पर राज्यस्तरीय बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन का गठन किया जाना है।

2. योजना के मुख्य उद्देश्य–

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का मुख्य उद्देश्य सब्जी के उत्पादन, गुणवत्ता एवं उत्पादकता में वृद्धि, सब्जी क्षेत्र मे मूल्य संवर्द्धन करना, सब्जी उत्पादकों को उत्पाद का सही मूल्य दिलाना, कृषकों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराना, सब्जी आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावी बनाना तथा उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता के सब्जी उपलब्ध कराना है।

3. योजना की प्रगति–

- योजना अंतर्गत 20 जिलों के प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों (PVCS) को सम्मिलित कर तीन संघ यथा हरित सब्जी संघ पटना, तिरहुत सब्जी संघ मोतिहारी एवं मिथिला सब्जी संघ दरभंगा का गठन किया जा चुका है। शीर्ष स्तर पर बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि॰ (वेजफेड) पटना का भी गठन किया जा चुका है।
- इस प्रकार वर्त्तमान में योजना का आच्छादन राज्य के 20 जिलों में करते हुए 300 प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति का गठन किया जा चुका है। इन प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पादक समितियों में 38858 से ज्यादा सब्जी उत्पादक किसान सदस्य बन चुके हैं।
- इस योजना का ब्रांड–"तरकारी" है। संघों द्वारा संस्थागत एवं खुदरा बिक्री के माध्यम से सब्जी बिक्री का कार्य संचालित है। राज्य के विभिन्न सरकारी संस्थानों एवं निजि संस्थानों में सब्जी की आपूर्ति की जा रही है।
- सब्जी उत्पादक किसानों को उनके उत्पादक का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रसंस्करण इकाईयों के साथ लिंकेज स्थापित किया जा रहा है। इस क्रम में टमाटर की बिक्री हेतु हिन्दुस्तान यूनिलिविर लिमिटेड (HUL) के साथ एकरारनामा किया गया है।

- पटना संघ, तिरहुत संघ एवं मिथिला संघ द्वारा अबतक (19.02.2024 तक) 62214.52 मे॰ट॰ की सब्जी व्यवसाय में 109.04 करोड़ रूपये का व्यवसाय किया गया है।
- योजना अंतर्गत 09 PVCS में आधारभूत संरचना (10 मे॰टन॰ कोल्ड स्टोरेज, ग्रामीण मंडी, संग्रहण केन्द्र, सोर्टिंग एवं ग्रेडिंग शेड, कार्यालय) का निर्माण किया जा चुका है, जबकि 06 PVCS में निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। साथ ही 10 PVCS में आधारभूत संरचना विकास की कार्रवाई की जा रही है।
- वर्त्तमान में पटना शहर में ऑनलाईन (tarkaarimart.in) माध्यम से सब्जी की होम डिलवरी का कार्य किया जा रहा है। अब तक कुल 34,129 आर्डर की आपूर्ति की गई है।

योजना का विस्तारः– राज्य के अन्य जिलों में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का विस्तार प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री कृषि संयंत्र योजना अंतर्गत प्रथम चरण में 100 PVCS को कृषि संयंत्र के क्रय हेतु 15 लाख की दर से राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

उत्पादः सुरक्षाः समृद्धि

बिहार राज्य भंडार निगम

बी–2, प्रथम तल, मौर्यलोक परिसर, पटना

वित्त विभाग, बिहार सरकार, बिहार का पत्रांक–69 दिनांक 15.01.2024 के आलोक में माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 17.01.2024 को बजट भाषण सामग्री हेतु निर्धारित बैठक हेतु बिहार राज्य भंडार निगम, पटना से संबंधित कंडिकावार प्रतिवेदन।

कृषि उत्पादों के समुचित रख–रखाव एवं भंडारण की व्यवस्था हेतु बिहार राज्य भंडार निगम "राज्य भंडारण एजेंसी" के रूप में खाद्यान्नों, उर्वरकों एवं अधिसूचित वस्तुओं का वैज्ञानिक एवं सुरक्षित भंडारणकर्ता है। वर्त्तमान में बिहार राज्य भंडार निगम अन्तर्गत बिहार एवं झारखण्ड राज्यों में कुल 63 स्थानों पर भंडारगृह संचालित है। सम्प्रति इसकी कुल भंडारण क्षमता 8,22,823 मे.टन है। बिहार राज्य भंडार निगम कार्य व्यवस्था के आधुनिकीकरण एवं दक्षता निमित सचेष्ट है।

बैठक हेतु कंडिकावार कार्यावली का प्रतिवेदनः–

1)	रोजगार के अवसर/नई नियुक्तियों का विवरण	बिहार राज्य भंडार निगम के निदेशक पर्षद की दिनांक 22.12.2023 के कार्यक्रम संख्या–1 का क्रमांक–8 में अधीक्षक–I–9 पद, तकनीकी सहायक–15 पद, सहायक लेखापाल–3 पद, सहायक–II–24 पद एवं पी.सी.डी.ओ.–17 पद पर नियुक्ति करने की स्वीकृति दी गई है, जिसपर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।
2)	कृषि रोड मैप	बिहार राज्य भंडार निगम में कृषि रोड मैप योजनान्तर्गत (वर्ष 2012–13 से 2015–18) कुल 12 स्थानों पर कुल 3.10 मे.टन क्षमता का गोदाम निर्माण किया गया है एवं सभी उपयोग में है।
3)	आधारभूत संरचनाओं का विकास	वर्ष 2023–24 में 10 स्थानों पर सड़क मरम्मति/जीर्णोद्धार, चाहरदीवारी निर्माण एवं कार्यालय भवन से संबंधित निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है एवं 22 स्थानों पर निविदा प्रकाशन के साथ अग्रेतर कार्रवाई प्रारम्भ की जा चुकी है।
4)	नई परियोजनाएं/ योजनाएं	सहकारिता विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त अनुदान राशि रु. 12,51,14,400/– से तीन स्थानों यथा मुरलीगंज (मधेपुरा)–5000 मे.टन, मालीघाट (मुजफ्फरपुर)–4000 मे.टन तथा मसौढ़ी (पटना)–1500 मे.टन क्षमता का गोदाम निर्माण का कार्य कराया जायेगा।
5)	प्रावैधिकी में नवाचार	बिहार राज्य भंडार निगम तकनीकी के नये आयामों पर अमल करते हुए दो महत्वपूर्ण ऑनलाईन प्रणालियों यथा DOS एवं e-bhandaran (WMS) के अन्तर्गत भंडारण कार्यों को संचालित कर रहा है। केन्द्रीय भंडारण निगम के WMS ऑनलाईन प्रणाली को Customized कर e-bhandaran (WMS) के रूप में भंडारगृहों के सम्पूर्ण गतिविधियों को एक केन्द्रीकृत स्वचालित व्यवस्था के तहत संचालित करने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य है। उक्त दोनों प्रणालियों के माध्यम से कृषि उत्पादों/अधिसूचित सामग्रियों की प्राप्ति एव निर्गमन, इनका भंडारण, छल्लीकरण, रासायनिक उपचार, विपत्र भुगतान, गुण नियंत्रण आदि गतिविधियों को स्वचालित रूप से संचालित किया जाता है एव समय परक आंकड़े (Real Time Data) पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं निर्णय हेतु उपलब्ध होती है। e-bhandaran (WMS) के साथ Tally, Payment gateway, e-invoicing के साथ integration हो चुका है। DOS एवं e-bhandaran (WMS) के साथ Weighbridge का integration छः स्थानों पर पूर्ण किया जा चुका है शेष स्थानों पर प्रक्रियाधीन है।

16/1/24

बिहार राज्य भंडार निगम, पटना

भंडारगृहों/गोदामों की भंडारण क्षमता एवं उपयोगिता

दि०: 21.02.2024

क्रम सं०	भंडारगृह/गोदाम का प्रकार	कुल क्षमता (मे. टन में)	गोदाम की संख्या	संरचनात्मक उपयोगित क्षमता (मे.टन में)	भा.खा.नि. द्वारा पुर्नमूल्यांकित उपयोगित क्षमता (मे.टन में)	कुल संरचनात्मक उपयोगिता क्षमता+पुर्नमूल्यांकित क्षमत (मे.टन में)	कुल रिक्त क्षमता (मे. टन में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	स्वनिर्मित गोदाम (SYGS एवं RKVY योजनान्तर्गत)	2,09,493	81	1,73,534	9,725	1,83,259	34,275
2	स्वनिर्मित गोदाम (2nd ARM योजनान्तर्गत)	3,10,000	51	2,75,730	11220	2,86,950	35,000
3	पी.ई.जी. गोदाम (भारतीय खाद्य निगम प्रायोजित PPP योजनान्तर्गत)	1,70,000	34	1,70,000	0	1,70,000	0
4	किराये का गोदाम (बिहार)	98,113	29	61,784	0	61,784	36,995
5	किराये का गोदाम (झारखण्ड)	30,112	18	27,186	4297	31,483	2,718
	कुल	8,17,717	213	7,08,233	25,242	7,33,475	1,08,993

(A) कुल संरचनात्मक क्षमता का उपयोगित प्रतिशत (कॉलम 5) 86.61%

(B) कुल उपयोगित प्रतिशत (संरचनात्मक क्षमता + पुर्नमूल्यांकित क्षमता (कॉलम 7) 89.70%

* भंडारगृहों की संख्या - 62

बिहार - 54

झारखण्ड - 8

कुल - 62

* उपयोगित भंडारगृह/गोदाम की क्षमता - 7,33,475 MT

क्रम सं०	संस्थान	उपयोगित क्षमता (मे.टन में)	भंडारगृह की संख्या
I)	भारतीय खाद्य निगम	5,10,283	49
II)	राज्य खाद्य निगम	1,16,435	8
III)	अन्य	1,06,756	5
		7,33,475	62

* उपयोगिता विवरणी

1	(क) भा.खा.नि. (बिहार) संरचनात्मक क्षमता	:	2,87,855 मे.टन
	(ख) भा.खा.नि. द्वारा पुर्नमूल्यांकित क्षमता (बिहार)	:	20,945 मे.टन
2	भा.खा.नि. (पी.ई.जी.) (बिहार)	:	1,70,000 मे.टन
3	(क) भा.खा.नि. (झारखण्ड) संरचनात्मक क्षमता	:	27,186 मे.टन
	(ख) भा.खा.नि. द्वारा पुर्नमूल्यांकित क्षमता (झारखण्ड)	:	4,297 मे.टन
4	राज्य खाद्य निगम	:	1,16,435 मे.टन
5	बी.एम.एस.आई.सी.एल.	:	31,310 मे.टन
6	केन्द्रीय भंडारण निगम	:	23,158 मे.टन
8	कम्फेड (सीड प्लांट)	:	4,502 मे.टन
9	अन्य/निजी संस्थान	:	47,786 मे.टन
	कुल	:	7,33,475 मे.टन

BIHAR STATE WAREHOUSING CORPORATION, PATNA

List of Warehouses/Godowns in Bihar (Revenue Districtwise).

Dt-21.02.2024

Storage Capacity (in MT)

Sl. No.	Revene District	Name of Centre	Type of Godown				Total Capacity
			Own-Old	Own-ARM	PEG	Hired	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Araria	Forbesganj	7506	5000	0	0	12506
		Forbesganj (ARM-PEG)	0	15000	0	0	15000
		Narpatganj	0	0	0	6089.3	6089
2	Arwal		No Centre				
3	Aurangabad	PEG Aurangabad (A.N. Road)	0	0	20000	0	20000
		PEG Aurangabad (Obra)	0	0	10000	0	10000
4	Banka		No Centre				
5	Begusarai	Barauni	4460	0	0	3783.8	8244
		Begusarai	0	30000	0	0	30000
		PEG Begusarai	0	0	15000	0	15000
6	Bhagalpur	Bhagalpur	11583	0	0	0	11583
		Naugachhia	0	50000	0	0	50000
7	Bhojpur	Ara	16100	10000	0	0	26100
		Ara (ARM-PEG)	0	10000	0	0	10000
		PEG Ara	0	0	20000	0	20000
8	Buxar	Buxur	6720	0	0	0	6720
9	Darbhanga	PEG Darbhanga	0	0	10000	0	10000
10	East Champaran	Motihari	5000	0	0	0	5000
		PEG Motihari	0	0	20000	0	20000
		Raxaul	8780	0	0	0	8780
11	Gaya	Gaya	10730	0	0	0	10730
		Manpur (Gaya)	0	0	0	3569.5	3570
12	Gopalganj	PEG Gopalganj			15000		15000
13	Jamui	PEG Jamui	0	0	5000	0	5000
14	Jehanabad	Jehanabad	0	10000	0	0	10000
15	Khagaria	PEG Khagaria	0	0	10000	0	10000
16	Kishanganj	PEG Kishanganj	0	0	15000	0	15000
17	Kaimur	Mohania	5000	0	0	0	5000
		PEG Mohania	0	0	25000	0	25000
18	Katihar	Katihar	0	25000	0	1000	26000
19	Lakhisarai	Lakhisarai	0	0	0	1946.2	1946
20	Madhubani	Jhanjharpur	0	15000	0	0	15000
21	Munger		No Centre				
22	Madhepura	Rasna (Madhepura)	0	0	0	3776.4	3776
		Murliganj	4360	0	0	0	4360
23	Muzaffarpur	Muzaffarpur	28811				28811
24	Nalanda	Biharsharif	6720	10000	0	0	16720
		PEG Biharsharif	0	0	10000	0	10000
25	Nawada		No Centre				
26	Patna	Bihta	0	20000	0	0	20000
		Bihta (ARM-PEG)	0	5000	0	0	5000
		Fatuha	10000	0	0	1780	11780
		Masaurhi	2379	0	0	0	2379
27	Purnia	Gulabbag	9184	0	0	0	9184
		PEG Gulabbag	0	0	20000	0	20000
		Kasba	7000	0	0	0	7000
		Jankinagar	1000	0	0	0	1000
		Garhbanaili	0	0	0	5868.5	5869
28	Rohtas	Sasaram	21860	45000	0	0	66860
		Natwar	0	50000	0	0	50000

Storage Capacity (in MT)

Sl. No.	Revene District	Name of Centre	Type of Godown				Total Capacity
			Own-Old	Own-ARM	PEG	Hired	
29	Saharsa	Saharsa	0	0	0	12451	12451
30	Samastipur	Samastipur	10000	0	0	0	10000
31	Sheohar		No Centre				
32	Sheikhpura		No Centre				
33	Saran	Chapra	10000	0	0	0	10000
34	Sitamarhi	Sitamarhi	10660	0	0	0	10660
35	Supaul		No Centre				
36	Siwan		No Centre				
37	Vaishali	Mohammadpur (Vaishali)	0	0	0	7848	7848
38	West Champaran	Bettiah	11640	0	0	0	11640
		PEG Bettiah	0	0	25000	0	25000
		Narkatiyaganj	0	10000	0	0	10000.0
		Total	*209493*	*310000*	*220000*	*48112.8*	*787605.8*

List of Warehouses/Godowns in Jharkhand

Sl. No.	Revene District	Name of Centre	Type of Godown				Total Capacity
			Own-Old	Own-ARM	PEG	Hired	
1	Lohardaga	Lohardaga	0	0	0	2174	2174
2	Garhwa	Garhwa	0	0	0	3043.8	3044
3	Bokaro	Bokaro	0	0	0	3900	3900
4	Chatra	Chatra	0	0	0	6502.5	6503
5	Dumka	Dumka	0	0	0	2666.7	2667
6	Giridih	Giridih	0	0	0	2351.5	2352
7	Godda	Godda	0	0	0	4720	4720
8	Saraikela Kharsawan	Saraikela	0	0	0	4753	4753
		Total	*0*	*0*	*0*	*30112*	*30112*

Total Capacity of Godowns in Bihar)

1)	Own Old	=	209493
2)	Own ARM	=	310000
3)	PEG	=	220000
4)	Hired	=	48113
	Total	=	**787606**

Total Capacity of Godowns in Jharkhand

1)	Hired	=	**30112**

Total Capacity of Godowns (Bihar + Jharkhand) = ***817717***

Godowns Status in Bihar State

Total No. of Districts	=	**38**
BSWC Centres Operated in Districts	=	**30**
Districts where BSWC Centres not operational	=	**8**

* At Present No Centres exist in Eight Districts namely **Arwal, Banka, Munger, Nawada, Sheohar, Sheikhpura, Siwan, and Supaul** District of Bihar.
* Under **PEG Scheme**, the construction of godowns in Ara (10,000 MT), Biharsharif (10,000 MT), Gopalganj (20,000 MT), Saharsa (20,000 MT), Samastipur (10,000 MT), Sitamarhi (25,000 MT) **Banka (10,000 MT), Nawada (10,000 MT) Sheohar (10,000 MT), Sheikhpura (5000 MT) & Siwan (10,000 MT)** i.e. in 5 (Five) districts has been tendered.
* Vacant Districts (where neither Godown exist nor in process of construction):**3 (Arwal, Munger & Supaul)**

सहकारिता

02

बसंत ऋतु में एक बार फिर आई एनडीए की सरकार।

बिहार में फिर से बहने लगा खुशियों/विकास की बयार।।

विकास की गति फिर से होगी दिन दूनी रात चौगुनी। *

क्योंकि पीएम मोदी,सीएम नीतीश की जोड़ी आए हैं।।

सहकारिता का साख से देश में होगा बिहार नंबर वन,

कृत संकल्प से सब कुछ होगा कहता हूं तत्क्षण।

*पूर्व के साथियों के लिए_

कुछ कर गए,कुछ कह गए, कुछ कहते रहते रह गए।

प्रेम का वादा हैं होंगे कार्य तमाम विकसित बिहार के नाम।

*विपक्ष को कहना चाहूंगा_

एक दूजे से हाथ मिलाए विकसित बिहार के लिए दिल में है मलाल।

एकता_राष्ट्रवाद और विकसित बिहार की बने हम मसाल।

गरीब,नौजवान,महिला किसान सब के सब होंगे मालामाल।।

⇒(03) संस्कारी है एनडीए सरकार,सहकार से करेंगे बिहार का उद्धार।

51% गांव 94% किसान सहकारिता से जुड़े हैं होगा उनका कल्याण।

क्योंकि सहकार से समृद्धि की ओर की परिकल्पना को केंद्र की मोदी सरकार, सहकारिता मंत्री अमित शाह एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी कर रहे हैं साकार।

सहकारी बैंकों को भी आजादी के अमृत काल में खोलने होंगे अपने आर्थिक द्वार।

तभी बनेगा अपना विकसित बिहार।

*विपक्ष से करूंगा आह्वान_

⇒(04) हो विपक्ष भी गर साथ मेरे,जल्द विकसित बिहार का भाग्य लिखेंगें।

सहकार से समृद्धि लायेंगें,केंद्र_राज्य मिलकर विकसित बिहार बनायेंगे।

⇒(05) *सभापति महोदय के लिए_

विधायक,मंत्री,नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपने कई रिकॉर्ड बनाए हैं।

कप्तानी की नई पारी के लिए हम फिर लख_लख बधाई आपके लिए लाए हैं।

06 अंत में एक ही बात कहूंगा_ ए खुदा/हे भगवान/ओ गॉड

देना है तो निगाहों/आंखों में ऐसी रसायन दे

मैं देखूं आईना तो मुस्कुराता बिहार दिखाई दे।

जय जवान:_सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के लिए।

जयकिशान:_किसान सम्मान निधि और किसान मानधन के लिए।

जय विज्ञान;_गगनयान एवं चंद्रयान के लिए।

जय अनुसंधान:_आदित्य एल_1 सूर्य यान और समुद्र यान के लिए।

जय हिंदुस्तान:_नए संसद भवन और नए भारत मंडपम के लिए।

जय, जय सियाराम: काशी कॉरिडोर,महाकाल कोरिडोर और अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए।